



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49]

नई दिल्ली, शनिवार विस्तम्बर 4, 1982/अग्रहायण 13, 1904

No. 49]

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 4, 1982/AGRAHAYANA 13, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और आघसूचनाएँ  
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India  
(other than the Ministry of Defence)

### गृह मंत्रालय

(कानूनी और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 1982

क्रा० आ० 3975.—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अपराधों को, ऐसे अपराध घोषित करता है, जिनका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन द्वारा किया जाएगा, यथातः—

(क) भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 367 के अधीन दंडनीय अपराध

(ख) खण्ड (क) में वर्णित अपराधों में से एक या एक से अधिक अपराधों के संबंध में या उनसे संबंधित प्रयत्न, बुद्धिमत्ता और प्रयत्न और इन्हीं तथ्यों से उद्भूत उन्नी संशयबहारी के दौरान किया गया अन्य कोई अपराध।

[संख्या 228/6/82/ए०डी०आई०-11]

एच० के० वर्मा, उप सचिव

### MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

New Delhi, the 17th November, 1982

S.O. 3975.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25

of 1946), the Central Government hereby specifies the following offences as the offences which are to be investigated by the Delhi Special Police Establishment, namely :—

(a) Offences punishable under section 367 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860); and

(b) attempts, abetments and conspiracies in relation to, or in connection with, one or more of the offences mentioned in clause (a) and any other offence committed in the course of the same transaction arising out of the same facts

[No. 228/6/82-AVD-II]

H. K. VERMA, Under Secy.

### गृह मंत्रालय आयोग

राष्ट्रीय शांति प्रतिष्ठान एवं अन्य संगठनों के बारे में संशोधन

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 1982

क्रा०आ० 3976.—इस आयोग की कार्यविधि को विनियमित करने वाले आदेश के पैरा 3 का, जिसे तारीख 26 जुलाई, 1982 की अधिसूचना सं० 1/1/82-के०डी०आई० के तहत जारी किया गया था, इस प्रकार पढ़ा जाये :—

'कार्यालय का पता 3 22-11-1982 में, पहले आदेशों तह, इस आयोग का मुख्यालय कमरा नं० 13, "सी" विंग, दूसरी मंजिल, लोक नायक भवन, नजदीक खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 में होगा

और जब तक पते में कोई परिवर्तन अविज्ञापित न किया जाए तब तक सभी पत्रादि सचिव, कुदाल आयोग—गांधी शांति प्रतिष्ठान एवं अन्य संगठनों के बारे में—कमरा नं० 21, "सी" विंग, दूसरी मंजिल, लोक नायक भवन, नजदीक खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 के पते पर भेजे जायें।"

आयोग के आदेश से।

[सं० 1/1/82-के०सी०आई०]

बि० एम०के० मट्टो, सचिव

Kudal Commission of Inquiry on Gandhi Peace

Foundation and other Organisations

AMENDMENT

New Delhi, the 25th November, 1982

S.O. 3976.—Para 3 of the Order regulating the procedure of this Commission issued vide Notification No. 1/1/82-KCI dated the 26th July, 1982 may be read as under :—

"Official Address.—3 Until further orders, the Headquarters of the Commission will be at Room No. 13, 'C' Wing, IInd Floor, Lok Nayak Bhavan, Near Khan Market, New Delhi-110003, with effect from 22-11-1982 and all communications should be addressed to the Secretary to the Kudal Commission of Inquiry on Gandhi Peace Foundation and other Organisations, Room No. 21, 'C' Wing, IInd Floor, Lok Nayak Bhavan, Near Khan Market, New Delhi-110003, till a change in address is notified." By order of the Commission.

[No. 1/1/82-KCI]

B. M. K. MATTO, Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1982

आयकर

का० आ० 3977.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकार, अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग नई दिल्ली से निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक और अनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्र में "संगम" प्रयोग के अर्धान निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है अर्थात् :—

- (i) यह कि जैन वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान, नई दिल्ली कृषि/पशुपालन/मात्स्यिकी और औषधि से भिन्न प्राकृतिक और अनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।
- (ii) उक्त संगम करने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणों विहित प्राधिकारों की प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्रारूपों में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किए जाएं और उसे सूचित किए जाएं।
- (iii) उक्त प्रतिष्ठान वार्षिक विवरणों और लेखाओं का वार्षिक विवरण प्रति वर्ष आयकर आयुक्त को भेजेगा।

संस्था

जैन वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान, नई दिल्ली यह अधिसूचना 26-12-1981 से 25-12-1983 तक दो वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं० 4582/का० सं० 203/193/80-आई टी ए(II)]

मदन गोयल, प्रवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 23rd April, 1982

INCOME TAX

S.O. 3977.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Department of Science and Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category of "Association" in the area of other natural and applied sciences subject to the following conditions :—

- (1) That the Jain Foundation for Scientific Research and Development, New Delhi will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research in the field of natural and applied sciences other than Agricultural/Animal husbandry/Fisheries and medicines.
- (ii) That the said Association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimate to them for this purpose by 30th April each year.
- (iii) That the said Foundation will submit the Annual returns and statement of Accounts to the Commissioner of Income-tax for every year.

INSTITUTION

Jain Foundation for Scientific Research and Development, New Delhi.

This notification is effective for a period of two years from 26-12-1981 to 25-12-1983.

[No. 4582/F. No. 203/193/80-ITA (ii)]

M. G. C. GOYAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 1 जून, 1982

आयकर

का० आ० 3978.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (44) के उपखंड (iii) के अनुसरण में और भारत सरकार के राजस्व विभाग की दिनांक 3-5-80 की अधिसूचना सं० 3280 का अधिसूचन करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री एस० सी० गुप्त-II को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली अधिकारों की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना श्री एस० सी० गुप्त-II द्वारा कर वसूली अधिकारों के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से लागू होगी।

[सं० 4650 (का० सं० 398/14/81-आ० क० ब० (खंड 1)]

New Delhi, the 1st June, 1982

INCOME TAX

S.O. 3978.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No. 3280 (F. No. 398/3/80-ITB) dated 3-5-80, the Central Government hereby authorises Shri S. C. Gupta-II being a gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri S. C. Gupta-II takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 4650/F. No. 398/14/81-ITB (Pt. I)]

नई दिल्ली, 3 जून, 1982

#### आय-कर

क्रा० आ० 3979.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (44) के उपखंड (iii) के अनुसरण में और भारत सरकार के राजस्व विभाग की दिनांक 30-6-80 की अधिसूचना सं० 3498 (फा० सं० 398/15/80-आ० क० सं० क०) का अधिलेखन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री ए० आर० पिंपलवार को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना, श्री ए० आर० पिंपलवार द्वारा कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से लागू होगी।

[सं० 4658/फा० सं० 398/5/82-आ० क० सं० क०]

New Delhi, the 3rd June, 1982

#### INCOME TAX

S.O. 3979.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in pursuance of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No. 3498 (F. No. 398/15/80-ITCC) dated 30-6-80, the Central Government hereby authorises Shri A. R. Pimpalwar, being a gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri A. R. Pimpalwar takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 4658/F. No. 398/5/82-ITB]

#### आय-कर

क्रा० आ० 3980.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (44) के उपखंड (iii) के अनुसरण में और भारत सरकार के राजस्व विभाग की दिनांक 30-6-81 की अधिसूचना सं० 4066 (फा० सं० 398/20/81-आ० क० सं० क०) का अधिलेखन करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा श्री डी० आर० नन्दा को जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना श्री डी० आर० नन्दा द्वारा कर वसूली अधिकारी के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से लागू होगी।

[सं० 4660/फा० सं० 398/25/82-आ० क० सं० क०]

#### INCOME TAX

S.O. 3980.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No. 4066 (F. No. 398/20/81-ITCC) dated 30-6-81, the Central Government hereby authorises Shri D. R. Nanda, being a gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri D. R. Nanda takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 4660/F. No. 398/25/82-ITB]

#### आय-कर

क्रा० आ० 3981.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (44) के उपखंड (iii) के अनुसरण में तथा भारत

सरकार के राजस्व विभाग की दिनांक 30-6-79 की अधिसूचना संख्या 2918 (फा० सं० 404/134/का० व० अ० उ० सं० 79-आ० क० सं० क०) को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री एन० पी० रामाराव को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना श्री एन० पी० रामाराव द्वारा कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारीख से लागू होगी।

[सं० 4662/फा० सं० 398/21/82-आ० क० सं० क०]

#### INCOME TAX

S.O. 3981.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in supersession of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No. 2918 (F. No. 404/134/TRO-Orissa/79-ITCC) dated 30-6-79, the Central Government hereby authorises Shri N. P. Rama Rao, being a gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri N. P. Rama Rao takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 4662/F. No. 398/21/82-ITB]

नई दिल्ली, 18 जून, 1982

#### आय-कर

क्रा० आ० 3982.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (44) के उपखंड (iii) के अनुसरण में और भारत सरकार के राजस्व विभाग की दिनांक 16-1-80 की अधिसूचना सं० 3133 (फा० सं० 404/22/का० व० अ०-ग० सं० 79-आ० क० सं० क०) का अधिलेखन करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री बी० एस० बिस्वास को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना, श्री बी० एस० बिस्वास द्वारा कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारीख से लागू होगी।

[सं० 4702/फा० सं० 398/19/82-आ० क० सं० क०]

New Delhi the 18th June, 1982

#### INCOME TAX

S.O. 3982.—In exercise of sub-clause (iii) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No. 3133 (F. No. 404/22/TRO-WB/79-ITCC) dated 16-1-80, the Central Government hereby authorises Shri B. S. Biswas, being a gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri B. S. Biswas takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 4702/F. No. 398/19/82-ITB]

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 1982

#### आय-कर

क्रा० आ० 3983.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (44) के उपखंड (iii) के अनुसरण में और भारत सरकार के राजस्व विभाग की दिनांक 3-5-80 की अधिसूचना सं० 3276 (फा० सं० 398/3/80-आ० क० सं० क०) का अधिलेखन करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री राजेंद्र प्रसाद को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना, श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारीख से लागू होगी।

[सं. 4791/फा० सं० 398/14/81-आ० व० ब०]

एन० के० शुक्ल प्रवर सचिव

New Delhi, the 12th July, 1982

#### INCOME TAX

**S.O. 3983**—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No 3276 (F No. 398/3/80-ITCC) dated 3-5-80 the Central Government hereby authorises Shri Rajinder Prasad, being a gazetted Officer of the Central Government to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act

2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri Rajinder Prasad takes over charge as Tax Recovery Officer

[No 4791/F No 398/14/81-ITB]

N K SHUKLA, Under Secy

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 1982

प्राय-कर

**क्र० आ० 3984** — प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (44) के उपखंड (iii) के अनुसरण में और भारत सरकार के राजस्व विभाग की दिनांक 1-6-82 की अधिसूचना सं० 4650 (फा० सं० 398/14/81-आ० व० ब०) का अधिलेखन करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्रीमती सुमति के० मेहता को, जो केन्द्रीय सरकार की राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना, श्रीमती सुमति के० मेहता द्वारा कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारीख से लागू होगी।

[सं० 4876/फा० सं० 398/14/81-आ० व० ब०]

New Delhi, the 21st August, 1982

#### INCOME TAX

**S.O. 3984**—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No 4650 (F. No. 398/14/81-ITB) dated 1-6-82, the Central Government hereby authorises Smt. Sumati K. Mehta, being a gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from the date Smt Sumati K Mehta takes over charge as Tax Recovery Officer

[No. 4876/F. No 398/14/81-ITB]

नई दिल्ली, 13 अगस्त 1982

प्राय-कर

**क्र० आ० 3985** — प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (44) के उपखंड (iii) के अनुसरण में और भारत सरकार के राजस्व विभाग की दिनांक 23-1-79 की अधिसूचना सं० 2678 (फा० सं० 404/22-क० व० प्र०/प०/ब०)/79-आ० व० ब० का अधिलेखन करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री डी० भोमिक को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना, श्री डी० भोमिक द्वारा कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारीख से लागू होगी।

[सं० 4909/फा० सं० 398/19/82-आ० व० ब०]

New Delhi, the 13th September, 1982

#### INCOME TAX

**S.O. 3985**—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No 2678 (F No 404/22/TRO-WB/79-ITCC) dated 23-1-79, the Central Government hereby authorises Shri D Bhowmick, being a gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act

2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri D Bhowmick takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No 4909/F No 398/19/82-ITB]

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 1982

प्राय-कर

**क्र० आ० 3986** — प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (44) के उपखंड (iii) के अनुसरण में और भारत सरकार के राजस्व विभाग की दिनांक 10-8-1982 की अधिसूचना सं० 4863 (फा० सं० 398/8/81-आ० व० ब०) का अधिलेखन करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री बी० एन० के० वर्मा को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना, श्री बी० एन० के० वर्मा द्वारा कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारीख से लागू होगी।

[सं० 4945/फा० सं० 398/8/81-आ० व० ब०]

आर० सी० हान्डा, उप सचिव

New Delhi, the 12th October, 1982

#### INCOME TAX

**S.O. 3986**—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No 4863 (F No 398/8/81-ITB) dated 10-8-82 the Central Government hereby authorises Shri B N K Verma, being a gazetted Officer of the Central Government to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri B N K Verma takes over charge as Tax Recovery Officer

[No 4945/F. No 398/8/81-ITB]

R. C HANDA, Dy. Secy

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 1982

प्राय-कर

**क्र० आ० 3987** — केन्द्रीय सरकार प्राय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "श्री पद्मानभस्वामी मंदिर भ्यास की निष्कारण वर्ष 1982-83 से 1984-85 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं० 4878/फा० सं० 197/66/82-आ० व० (ए० I)]

New Delhi, the 25th August, 1982

#### INCOME TAX

**S.O. 3987**—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sri Padmanabhaswami Temple Trust" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1982-83 to 1984-85

[No 4878/F No 197/66 '82-IT(A)]



नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1982

## आय-कर

क्रा० आ० 3988.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "श्री बाहुबलि ब्रह्मचर्याश्रम बाहुबलि" को निर्धारण वर्ष 1981-82 और 1982-83 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं० 4894/क्रा० सं० 197/30/81-क्रा० क (ए I)]

New Delhi, the 31st August, 1982

## INCOME TAX

S.O. 3988.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Shri Bahubali Brahmacharyashram Bahubali" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1981-82 and 1982-83.

[No. 4894/F. No. 197/30/81-IT(AI)]

## आय-कर

क्रा० आ० 3989.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "दि कॉन्ग्रेगेशन ऑफ दि त्रस्ट्स ऑफ सेन्ट्रल हार्ट, पलायम कोटाई" को निर्धारण वर्ष 1977-78 से 1981-82 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं० 4895/क्रा० सं० 197/106/79-क्रा० क (ए I)]

## INCOME TAX

S.O. 3989.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "The Congregation of the Brothers of Sacred Heart, Palayamkottai" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1977-78 to 1981-82.

[No. 4895/F. No. 197/106/79-IT(AI)]

## आय-कर

क्रा० आ० 3990.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "दि सोसाइटी ऑफ आवर लेडी ऑफ डोलर्स, दि सर्वन्ट्स ऑफ मेरी" को निर्धारण वर्ष 1979-80 से 1982-83 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं० 4897/क्रा० सं० 197/195/81-क्रा० क (ए I)]

## INCOME TAX

S.O. 3990.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "The Society of Our Lady of Dolours, The Servants of Mary" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1979-80 to 1982-83.

[No. 4897/F. No. 197/195/81-IT(AI)]

## आय-कर

क्रा० आ० 3991.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "आर्चिडायोसेस ऑफ त्रिवंद्रम" को निर्धारण वर्ष 1982-83 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं० 4898/क्रा० सं० 197/85/80-क्रा० क (ए I)]

## INCOME TAX

S.O. 3991.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Archdiocese of Trivandrum" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment year 1982-83.

[No. 4896/F. No. 197/85/80-IT(AI)]

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 1982

## आय-कर

क्रा० आ० 3992.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "कुम्बा कोनम डायोसेस सोसायटी, कुम्बा कोनम" को निर्धारण वर्ष 1979-80 से 1982-83 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं० 4900/क्रा० सं० 197/93/80-क्रा० क (ए I)]

New Delhi, the 2nd September, 1982

## INCOME TAX

S.O. 3992.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Kumba Konam Diocese Society, Kumbakonam" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1979-80 to 1982-83.

[No. 4900/F. No. 197/93/80-IT(AI)]

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 1982

## आय-कर

क्रा० आ० 3993 केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "श्री वेदान्त देविकर देवस्थानम मायलापुर को निर्धारण वर्ष 1982-83 से 1984-85 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं० 4918/क्रा० सं० 197/56/82-क्रा० क (ए I)]

New Delhi, the 21st September, 1982

## INCOME TAX

S.O. 3993.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sri Vedantha Desikar Devasthanam, Mylapure" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1982-83 to 1984-85.

[No. 4918/F. No. 197/56/82-IT(AI)]

## आय-कर

क्रा० आ० 3994 केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "श्री आनन्दपुर न्यास" को निर्धारण वर्ष 1981-82 और 1982-83 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं० 4919/क्रा० सं० 197/216/80-क्रा० क (ए I)]

## INCOME TAX

S.O. 3994.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies

"Shri Anandpur Trust" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1981-82 and 1982-83.

[No. 4919/F. No. 197/216/80-IT(AD)]

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1982

आय-कर

का०आ० 3995—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "श्री ठाकुरजी लक्ष्मीनाथ जी व्यास हुनजुनु" को निर्वारण वर्ष 1981-82 से 1983-84 तक के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए, उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिवृत्ति करती है।

[सं० 4930/फा०सं० 197/169/79 आ०फ०(ए०I)]

मिलाप जैन, अवर सचिव

New Delhi, the 30th September, 1982

INCOME TAX

S.O. 3995.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Shri Thakurji Laxmi Nath Ji Trust, Jhunjhunu" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1981-82 to 1983-84.

[No. 4930/F. No. 197/169/79-IT(AD)]

MILAP JAIN, Under Secy.

आर्थिक कार्य विभाग

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 1982

का०आ० 3996—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिकारिश पर एतद्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 10ख की उपधारा (1) और (2) के उपबंध बैंक ऑफ़ तमिलनाडु लिमिटेड, तिरुनेलवेली पर 4 नवम्बर, 1982 से 3 फरवरी, 1983 तक 3 महीने की अवधि के लिए, प्रत्येक उक्त बैंक में प्रत्येक पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक, इनमें से जो भी पहले हो उस समय तक लागू नहीं होंगे।

[संख्या 15/21/82-बी०सं०-III]

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(Banking Division)

New Delhi, the 13th November, 1982

S.O. 3996.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-sections (1) and (2) of section 10B of the said Act, shall not apply to Bank of Tamilnad Ltd., Tirunelveli, for a period of 3 months with effect from 4th November, 1982 upto 3rd February 1983, or till the appointment of the next whole-time Chairman of that bank whichever is earlier.

[No. 15/21/82-B.O. III]

का०आ० 3997.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिकारिश पर एतद्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 10 ख की उपधारा (1) और (2) के उपबंध मिराज स्टेट बैंक लिमिटेड मिराज पर 3 नवम्बर, 1982 से

2 मार्च 1983 तक 40 महीने की अवधि के लिए प्रत्येक अवधि के कार्यभार संभालने तक, इनमें से जो भी पहले हो उस समय तक लागू नहीं होंगे।

[सं० 15/21/82-बी०सं०-III]

एन०डी० बट्रा, अवर सचिव

S.O. 3997.—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendations of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-sections (1) and (2) of Section 10B of the said Act, shall not apply to Miraj State Bank Ltd., Miraj for a period of 4 months with effect from 3rd November, 1982 upto 2nd March, 1983 or till the new Chairman assumes charge, whichever is earlier.

[No. 15/29/82 B.O. III]

N. D. BATRA, Under Secy.

विदेश संचालय

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 1982

का०आ० 3998.—राजनयिक एवं कंसुली अधिकारी (शपथ एवं शुल्क) अधिनियम, 1948 (1948 का 41वां) के खंड 2 की धारा (क) के अनुपालन में केन्द्र सरकार, इसके द्वारा, भारत का हाई कमिशन, लुसाका, जाम्बिया में सहायक श्री बिमल कपूर को तत्काल से कंसुली एजेंट का कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[सं०टी 4330(2) 823]

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 12th November, 1982

S.O. 3998.—In pursuance of the clause (a) of section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948) the Central Government hereby authorise Shri Bimal Kapoor, Assistant in the High Commission of India, Lusaka, Zambia to perform the duties of Consular Agent with immediate effect.

[No. T. 4330 (2)/82]

का०आ० 3999.—राजनयिक एवं कंसुली अधिकारी (शपथ एवं शुल्क) अधिनियम, 1948 (1948 का 41वां) के खंड 2 की धारा (क) के अनुपालन में केन्द्र सरकार, इसके द्वारा, भारत का राजदूतावास, बहरीना में सहायक श्री जे०आर० मानकतला को तत्काल से कंसुली एजेंट का कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[सं०टी 4330/2/82]

बी० एम० निडर, अवर सचिव

S.O. 3999.—In pursuance of the clause (a) of Section 2 of the Diplomatic and Consular Officer (Oaths and fees) Act, 1948 (41 of 1948) the Central Government hereby authorise Shri J. R. Manaktala, Assistant in the Embassy of India, Bahrain to perform the duties of Consular Agent with immediate effect.

[No. T. 4330/2/82]

B. S. NIDDA, Under Secy.

बाणिज्य संचालय

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 1982

का०आ० 4000.—केन्द्रीय सरकार, काफी अधिनियम, 1942 (1942 का 7) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, काफी बोर्ड साधारण भविष्य निधि नियम, 1965 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्, :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम काफी बोर्ड साधारण भविष्य निधि (संशोधन) नियम, 1982 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. काफी बड़े मासखान भविष्य मिथि नियम, 1965 में, नियम 8 में, उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतर्भावित किया जाएगा, अर्थात् — (4) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी कोई अभिदाता, निधि में उस मास के लिए जिसमें वह सेवा छोड़ता है तब तक अभिदाय नहीं करेगा, जब तक कि उसने उक्त मास के प्रारम्भ से पूर्व उक्त मास के लिए अभिदाय करने का अपना विकल्प लेखा अधिकारी को लिखित रूप में संवृत्त न कर दिया हो।”

[फाइल सं० 1/17/82-प्लांट (बी)]

बी०एम०एस० नेगी, अवर सचिव

## MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 18th November, 1982

S.O. 4000.—In exercise of the powers conferred by section 48 of the Coffee Act, 1942 (7 of 1942), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Coffee Board General Provident Fund Rules, 1965, namely :

1. (1) These rules may be called the Coffee Board General Provident Fund (Amendment) Rules, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Coffee Board General Provident Fund Rules, 1965, in rule 8, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

“(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), a subscriber shall not subscribe to the Fund for the month in which he quits service unless, before the commencement of the said month, he communicates to the Accounts Officer in writing his option to subscribe for the said month.”

[File No. 1/17/82-Plant (B)]

B. M. S. NEGI, Under Secy.

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

रद्द करने का आदेश

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 1982

का० अ० 4001—सर्वोच्च बैंक आफ बड़ोदा, 10/12, बम्बई समाचार मार्ग, फोर्ट, बम्बई को (1) वन मिनीटा प्लेन पेपर कापियर मॉडल, ई-बी-310 (2) बिजली के टाइपराइटर मॉडल 'हर्मेस' 808 दोनों कालतु पुर्जों और उपभोग्य सामग्री के साथ आयात के लिए 38,500/रुपए लागत-सीमा-भाड़ा मूल्य का एक आयात लाइसेंस सं० बी/ए/1091356, दिनांक 16.3.82 प्रदान किया गया था जो कि जारी होने की तारीख से 12 मास के लिए वैध था। अब पार्टी ने उपर्युक्त आयात लाइसेंस की अनुमिति सीमा-शुल्क प्रयोजन और मुद्रा-विनिमय नियंत्रण प्रतियां प्रदान करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल प्रतियां उनसे खो गई/अस्थानस्थ हो गई हैं। पार्टी ने आयात व्यापार नियंत्रण नियमों के अनुसार आवश्यक शपथपत्र/घोषणा भी भेजी है जिसके अनुसार उपर्युक्त आयात लाइसेंस किसी भी सीमा-शुल्क कार्यालय के पास पंजीकृत नहीं कराया गया था और उसका बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया था और लाइसेंस में अब 38,500 रुपए की राशि शेष है। शपथपत्र घोषणा में यह भी कहा गया है कि यदि आयात लाइसेंस की उक्त सीमा-शुल्क प्रयोजन और मुद्रा-विनिमय नियंत्रण प्रतियां बाद में मिल गई या प्राप्त हुई गई तो वे जारी करने वाले प्राधिकारी का लौटा दी जाएंगी। मैं संतुष्ट हूँ कि आयात लाइसेंस की मूल सीमा-शुल्क प्रयोजन और मुद्रा-विनिमय नियंत्रण प्रतियां खो गई/अस्थानस्थ हो गई हैं और निदेश देता हूँ कि आवेदक को आयात लाइसेंस की अनुमिति सीमा-शुल्क प्रयोजन और मुद्रा-विनिमय

नियंत्रण प्रतियां जारी की जानी चाहिए। आयात लाइसेंस की मूल सीमा-शुल्क प्रयोजन और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियां एतद्वारा रद्द की जाती हैं।

[मिल सं० 12/183/81-82/एम एल एस/572]

शंकर चन्द, उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

हूवे मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

Office of the Chief Controller of Imports and Exports

New Delhi, the 11th November, 1982

## CANCELLATION ORDER

S.O. 4001.—M/s. Bank of Baroda, 10/12, Bombay Samachar Marg, Bombay were granted an import licence No. G/A/1091356 dated 16-3-82 for a C.I.F. value of Rs. 38,500 for import of (i) One Minolta Plain Paper Copier Model EP-310; (ii) Electric Typewriter Model 'Hermes' 808, both with spares and consumables valid for twelve months from the date of issue. Now the party have applied for grant of Duplicate Customs Purpose and Exchange Control copies for the aforesaid import licence on the ground that the original one have been lost/misplaced by them. The party have furnished necessary affidavit/declaration as per I.T.C. Rules according to which the aforesaid import licence was not registered with any Customs House and was not utilised at all and the balance against the licence is Rs. 38,500. It has also been incorporated in the affidavit/declaration that if the said Customs purpose and Exchange Control copies of the import licence are traced or found later on, it will be returned to the issuing authority. I am satisfied that the original Customs purpose and Exchange control copies of the import licence have been lost/misplaced and direct that Duplicate Customs Purpose and Exchange control copies of the import licence should be issued to the applicant. The original Customs Purpose and Exchange Control copies of the import licence are hereby cancelled.

[File No. 12/183/81-82/MLS/572]

SHANKAR CHAND, Dy. Chief Controller of

Imports and Exports

for Chief Controller of Imports and Exports

राष्ट्रीय विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 1982

का० अ० 4002—केन्द्रीय सरकार, कृषि उपज श्रेणीकरण और (चिह्नकन) अधिनियम, 1937 (1937 क. 1) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम श्रेणीकरण और चिह्नकन नियम, 1964 का और संशोधन करना चाहती है। जैसा कि उक्त धारा में अपेक्षित है, प्रस्तावित संशोधनों का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है। इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उक्त तारीख से जिसको उस राजपत्र की प्रतियां जिसमें अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, 45 दिन के पश्चात् विचार किया जाएगा।

इस प्रकार विनिश्चित अधिध की समाप्ति के पूर्व नियमों के उक्त प्रारूप की बाबत जो भी आशेष या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

प्रारूप नियम

1 इन नियमों का संक्षिप्त नाम अधिनियम श्रेणीकरण और चिह्नकन (संशोधन) नियम, 1982 है।

2 घनिय श्रेणीकरण और चिह्नान नियम, 1964 की अनुसूची II में—

(क) सारणी के स्तम्भ 4 के शीर्षक में तुल्यमान शब्द का जोड़ किया जाएगा।

(ख) स्तम्भ 5 में 1.0, 2.0, 3.0 अंको के स्थान पर क्रमशः 2.0, 4.0, 6.0 और 6.0 अंक रखे जायेंगे।

(ग) पाद टिप्पणी 3 के स्थान पर निम्नलिखित पाद टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात्—

3 काले किए हुए बीज के फल या विभक्त फल होते हैं जो तात्त्विक रूप से क्वालिटी पर प्रभाव डालते हुए, काले किए जाते हैं।

टिप्पण (1) मूल नियम भारत के राजपत्र में कां०भा० 2391, तारीख 11-7-64 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

(2) पहला संशोधन भारत के राजपत्र में कां०भा० 523, तारीख 10-2-68 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

(3) दूसरा संशोधन भारत के राजपत्र में कां०भा० 2842 तारीख 24-7-71 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

[सं० एफ० 10-4/82-ए एम०]

डी०मेहता, निदेशक (विपणन)

#### MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 12th November, 1982

S.O. 4002.—The following draft rules, further to amend the Coriander Grading and Marking Rules, 1964, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937), are hereby published as required by the said section for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that said draft rules will be taken into consideration after forty five days from the date on which the copies of the Gazette of India in which this notification is published are made available to the public.

Any objections or suggestions received from any persons with respect to the said draft rules, before the expiry of the period so specified, will be considered by the Central Government.

#### DRAFT RULES

1. These rules may be called the Coriander Grading and Marking (Amendment) Rules, 1982.

2. In the Coriander Grading and Marking Rules, 1964 in Schedule II,

(a) in the heading of column 4 of the table, the word "Damaged" shall be deleted;

(b) in column 5 for the figures '1.0', '2.0', '3.0' and '3.0' the figures '2.0', '4.0', '6.0' and '6.0' shall respectively be substituted;

(c) for the foot note 3 the following foot note shall be substituted, namely:—

"3. 'Blackened Seeds' are those fruits or split fruits which are blackened, materially affecting the quality."

NOTE.—(1) Principle rules published vide S. O. 2391 of G.O.I. dated 11/7/64.

(2) 1st amendment published vide S. O. 523 of G.O.I. dated 10/2/68.

(3) 2nd amendment published vide S. O. 2842 dated 24/7/71.

[No. F 10-4/82-AM]

D. MEHTA, Director (M)

Dated.—11-11-82.

#### संचार मंत्रालय

(डाक तथा बोर्ड)

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 1982

कां०भा० 4003.—स्वायी आदेश संख्या 627, दिनांक 9 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक वे पालमपुर/जंदियाल गुरु टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 16-12-1982 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निर्णय किया है।

[सं० 5-5/82-पी०एच०बी०]

प्रार०सी० कटारिया, महापंक निदेशक  
(पी०एच०बी०)

#### MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P & T Board)

New Delhi, the 17th November, 1982

S.O. 4003.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S. O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies 16-12-1982 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Palampur/Jandiiala Gurm Telephone Exchanges N. W. Circle.

[No. 5-5/82-PHB]

R. C. KATARIA, Assistant Director General (PHB)

#### अनुश्रवण संघटन

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 1982

का. भा. 4004 :—केन्द्रीय सरकार, राज भाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1978 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में, अनुश्रवण संघटन, संचार मंत्रालय के निम्नलिखित अनुश्रवण केन्द्रों को, जिनके कर्मचारी-वृन्द ने हिन्दी का कार्यक्षम ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को अधिसूचित करती है :—

1. अनुश्रवण केन्द्र, त्रिवेन्द्रम.

2. अनुश्रवण केन्द्र, मंगलौर.

3. अनुश्रवण केन्द्र, नागपुर।

[संख्या 9-मौन/(10)/82]

र. ग. देवधर, निदेशक,

(बेतार अनुश्रवण)

#### (MONITORING ORGANISATION)

New Delhi, 6th November 1982

S.O. 4004.—In pursuance of sub-rule 4 of the Official Languages (Use for official purpose of the union) Rule 1976 the Central Government hereby notify following Stations of



Monitoring Organisation of the Ministry of Communications, the staff whereof, have acquired working knowledge of Hindi.

1. Monitoring station Nagpur.
2. Monitoring station, Trivendrum.
3. Monitoring station, Manglore.

[No. 9-Mon (10)/82]

R. G. DEODHAR, Director

(Wireless Mon.)

## ऊर्जा मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 1982

क्रमांक 4005-यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य में बंबई से पुणे तक पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन के लिये पार्सल लाईन हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्भाष्य अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पार्सल लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

वर्तते कि उक्त भूमि में हिस्सबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पार्सल लाईन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई पुणे पार्सल लाईन प्रोजेक्ट फायुल रिफायनरीज कॉरिडोर रोड बम्बई को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विशेष व्यवसायी की माफत।

## अनुसूची

पार्सल लाईन जांचूले कान्हे तक

तालुक : मावल, जिला : पुणे, महाराष्ट्र

गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल	
			हेक्टर	ऐयर
जांचूल	239 का भाग	---	00	60
"	240 "	---	00	60
"	168 "	---	00	19
"	169 "	---		
"	170 "	---		
"	171 "	---		
"	172 "	---		
"	173 "	---		
"	174 "	---	00	29
"	175 "	---		

गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा	क्षेत्रफल	
			नम्बर	ऐयर
जांचूल	256 का भाग	---	00	23
"	268 "	---		
"	252 "	---	00	12
"	253 "	---		
"	254 "	---		
"	255 "	---		
"	241 "	---	00	20
"	251 "	---		
"	261 "	---	00	25
"	262 "	---		
"	274 "	---		
"	275 "	---		
"	277 "	---		
"	291 "	---	00	84
"	292 "	---		
"	296 "	---		
"	297 "	---		
"	298 "	---		
"	299 "	---		
"	300 "	---		
"	301 "	---		
"	302 "	---		
"	303 "	---		
"	293 "	---	00	09
"	294 "	---		
"	295 "	---		
"	296 "	---	00	39
"	297 "	---		
"	298 "	---		
"	299 "	---		
"	304 "	---		
"	307 "	---		
"	332 का भाग	---	00	03
"	(1 ए 1(-))	---		
"	332 "(1 ए 2)	---		
"	332(1 ए 3)	---		
"	333 "	---		
"	334 "	---		
"	335 "	---	00	73
"	336 "	---		
"	342 "	---		
"	351 "	---		
"	352 "	---	00	05
"	353 "	---		
"	354 "	---	00	14
"	361 "	---		
"	224 "	---		
"	228 "	---		
"	229 "	---		
"	327 "	---		
"	330 "	---	00	29
"	334 "	---		
"	326 "	---	00	14
"	53 "	---		

## MINISTRY OF ENERGY

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 9th November, 1982

गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल		
		हिसा नम्बर	हेक्टर	ऐयर
काण्हे	54 "	---	00	41
"	55 "	---		
"	56 "	---		
"	257 "	---		
"	258 "	---		
"	259 "	---		
"	260 "	---		
"	261 "	---		
"	262 "	---		
"	263 "	---		
"	264 "	---	00	13
"	265 "	---		
"	266 "	---		
"	267 का भाग }	---		
"	268 "	---		
"	269 "	---		
"	270 "	---		
"	282 "	---		
"	283 "	---		
"	284/2 "	---	00	04
"	284 "	---		
"	288 "	---		
"	292 "	---		
"	293 "	---		
"	312 "	---		
"	314 "	---		
"	311 "	---		
"	316 "	---		
"	315 "	---	00	17
"	512/1,2 "	---		
"	521 "	---		
"	522 "	---		
"	523 "	---		
"	524 "	---		
"	540 "	---		
"	536 "	---		
"	537 "	---		
"	538 "	---		
"	539 "	---	00	16
"	541 "	---		
"	532 का भाग	---		
"	535 "	---		
"	533 "	---		
"	460 "	---		
"	452 "	---		
"	453 "	---		
"	454 "	---		
"	455 "	---		
"	456 "	---	00	04
"	457 "	---		
"	458 "	---		
"	449 "	---		

S.O. 4005.—Whereas it appears to Central Government that it is necessary to lay a pipeline for transporting Petroleum Products from Bombay to Pune in the State of Maharashtra through Pipe-line and that said Pipe-line is to be laid through the agency of Hindustan Petroleum Corporation Limited, Bombay.

And whereas it appears to Central Government that for laying pipe-line it is necessary to acquire the Right of User in respect of the lands appended to herewith in schedule.

Now therefore in exercise of the powers vested in them by virtue of Section 3 (i) of Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) AO 1962 (50 of 1962) Central Government notify intention to acquire the Right of user in the lands referred to above.

Any person having his interest in the lands referred to above having any objection for laying the Pipe-line through above mentioned lands may prefer an objection within 21 days of the publication of this notification before the competent authority Hindustan Petroleum Corporation Limited, Bombay Pune Pipeline Project, Fuels Refinery, Corridor Road, Bombay-74.

All persons having any objection may also state whether they want to be heard in person either himself or through any lawyer appointed by him.

## SCHEDULE

## PIPELINE FROM : VILLAGE JAMBHUL TO KANHE

Tajuka : Mawal, District : Pune (Maharashtra)

Village	Gutt No.	AREA		
		Hissa No.	H—R	
Jambhul	239 PART	—	00	60
"	240 "	—	00	60
"	168 "	—		
"	169 }	—	00	19
"	170 "	—		
"	171 "	—		
"	172 }	—		
"	173 "	—		
"	174 }	—	00	23
"	175 "	—		
"	236 }	—		
"	268 "	—		
"	252 }	—	00	12
"	253 "	—		
"	254 }	—		
"	255 "	—		
"	241 }	—	00	20
"	251 "	—		
"	261 }	—		
"	262 "	—		
"	274 }	—	00	25
"	275 "	—		
"	277 }	—		
"	291 "	—		
"	292 "	—	00	34
"	296 "	—		
"	297 }	—		
"	299 "	—		
"	300 }	—	00	09
"	301 "	—		
"	302 }	—		
"	303 "	—		
"	293 }	—	00	09
"	294 "	—		
"	295 }	—		

Village	Gutt No.	Hissa	AREA		Village	Gutt No.	Hissa No.	AREA										
			H	R				H	R									
Kanhe	296	"	—		"	535	"	—	00 01									
"	297	"	—	00 39	"	533	"	—	00 43									
"	298	"	—		"	460	"	—	00 45									
"	290	"	—		"	452	"	—										
"	304	"	—		"	453	"	—										
"	307	"	—		"	454	"	—										
"	332	(1 A 2, Part)	—		"	455	"	—	00 04									
"	332	(1 A 3, Part)	—		"	456	"	—										
"	332	(1 A 3 Part)	—		"	457	"	—										
"	333	"	—	00 03	"	458	"	—										
"	334	"	—		"	449	"	—	01 34									
"	335	"	—		[No. 12016/49/82-Prod.]													
"	336	"	—		<p>का०मा० 4006.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कानावाडा-2 से चांगडा-1 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।</p> <p>और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्प्राबन्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।</p> <p>अतः अब पेट्रोलियम और खनिज काइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।</p> <p>बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।</p> <p>और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चितः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।</p> <p style="text-align: center;"><b>अनुसूची</b></p> <p>कानावाडा 2 से चांगडा-1 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए</p> <table><tr><th>राज्य - गुजरात</th><th>जिला : बेंदा</th><th>तालुका : बेंदा</th></tr><tr><th>गांव</th><th>सर्वे नं०</th><th>हैक्टेयर एंथारई सिन्टीअर</th></tr><tr><td>कानावाडा</td><td>91/1</td><td>0 15 20</td></tr></table> <p style="text-align: right;">[सं० 12016/50/82-प्रोड०]</p> <p>S.O. 4006.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Kanawada 2 to Changda-1 in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil &amp; Natural Gas Commission;</p> <p>And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;</p> <p>Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines( Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;</p>					राज्य - गुजरात	जिला : बेंदा	तालुका : बेंदा	गांव	सर्वे नं०	हैक्टेयर एंथारई सिन्टीअर	कानावाडा	91/1	0 15 20
राज्य - गुजरात	जिला : बेंदा	तालुका : बेंदा																
गांव	सर्वे नं०	हैक्टेयर एंथारई सिन्टीअर																
कानावाडा	91/1	0 15 20																
"	442	"	—															
"	351	"	—															
"	352	"	—															
"	353	"	—	0 73														
"	354	"	—															
"	361	"	—															
"	224	"	—															
"	228	"	—															
"	229	"	—	0 05														
"	327	"	—	00 02														
"	330	"	—	00 29														
"	334	"	—															
"	326	"	—	00 14														
"	53	"	—															
"	54	"	—															
"	55	"	—															
"	56	"	—															
"	257	"	—															
258 PART																		
"	259	"	—															
"	260	"	—															
"	261	"	—															
"	262	"	—															
"	263	"	—	00 41														
"	264	"	—															
"	265	"	—															
"	266	"	—															
"	267	"	—															
"	268	"	—															
"	269	"	—															
"	270	"	—															
"	282	"	—															
"	283	"	—	00 13														
"	284/2	"	—															
"	284	"	—	00 04														
"	288	"	—	00 29														
"	292	"	—	00 32														
"	293	"	—	00 22														
"	312	"	—	00 27														
"	314	"	—															
"	311	"	—	00 43														
"	316	"	—	00 08														
"	316	"	—	00 37														
"	512/2	"	—	00 19														
"	512/1	"	—															
"	521	"	—															
"	522	"	—	00 17														
"	523	"	—															
"	524	"	—															
"	540	"	—	00 16														
Kanhe	536	PART	—															
"	537	"	—															
"	538	"	—	00 17														
"	539	"	—															
"	541	"	—															
"	532	"	—	00 10														

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

#### SCHEDULE

##### PIPELINE FROM KANAWADA-2 TO CHANGADA-

State: Gujarat District: Kaira Taluka: Cambay

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
KANAWADA	91/1	10	15	20

[No. 12016/50/82-Prod.]

का० आ० 4007.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में कि यह आवश्यक है गुजरात राज्य में एस०एन०ए०जे० पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा से एस०एन०ए०जे० प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी साइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वाक्य अनुसूची में उद्योग का वर्णित भूमि में अधिकार को अर्जित उपयोग का करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बतते कि उक्त भूमि में हितवन् कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आशेष सख्त अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग, निर्माण और वेबमाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बदोहरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आशेष करने वाला हर व्यक्ति निनिदिष्टतः यह भी ध्यान करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

#### अनुसूची

एस०एन०ए०जे० से एस०एन०ए०जे० तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात	जिला और तालुका : मेहसाणा	गांव	ब्लॉक नं०	हेक्टेयर एघारई सेन्टीघर
		कसलपुरा	674	0 06 50
			672	0 12 50
			668	0 04 80
			669	0 13 80
			619	0 03 10

[सं० 12016/51/82-प्रोड]

एस०एम० गोयल, निदेशक

S.O. 4007.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from SNAJ to SNAJ in Gujarat state pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any persons interested in the said land, may within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

#### SCHEDULE

##### Pipeline From S. N. A. J. to S. N. A. O.

State : Gujarat District : & Taluka : Mehsana

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
KASALPURA	674	0	06	50
	672	0	12	50
	668	0	04	80
	669	0	13	80
	619	0	03	10

[No. 12016/51/82-Prod.]

L. M. GOYAL, Director

#### सिमा तथा संस्कर्त मंत्रालय

(सिमा विभाग)

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 1982

का०आ० 4008.—सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत दखल कारों को निकालने) अधिनियम 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा अयोग्य मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर होने के नाते निम्नलिखित सारणी के कालम (1) में उल्लिखित व्यक्ति को भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी के तर्ज के समकक्ष इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एतद्द्वारा सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है और जो उक्त सारणी के कालम 2 की तदनुसूची प्रविष्टि में निविष्ट सार्वजनिक स्थानों के सम्बन्ध में उसकी सम्बन्धित प्रशासनिक नियंत्रण की स्थानीय सीमाओं के भीतर इस अधिनियम के अंतर्गत सम्पदा अधिकारी के अधिकारों का उपयोग करेंगे और उनका कार्य निष्पादन करेंगे।

#### सारणी

नाम	सार्वजनिक स्थानों और प्रशासनिक नियंत्रण की स्थानीय सीमाएं
(1)	(2)
प्रो० अब्दुल मजीद सिद्दीकी	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय,
रसायन शास्त्र प्रोफेसर	प्रशासनिक नियंत्रणाधीन और
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	उमसे सम्बन्धित अलीगढ़ जिले
अलीगढ़	की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर
	स्थान

[सं० का० 382/82/डिस्क(यु)]

आसा सिंह, डेस्क अधिकारी



## MINISTRY OF EDUCATION &amp; CULTURE

(Department of Education)

New Delhi, the 16th November, 1982

S. O. 4008.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the person mentioned in column (1) of the Table below, being a professor of the Aligarh Muslim University, Aligarh, equivalent to the rank of a gazetted officer of the Government of India, to be Estate Officer for the purposes of the said Act, and who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on Estate Officer by or under the said Act, within the local limits of his respective jurisdiction in respect of the public premises specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table.

TABLE

Name:	Categories of public premises and local limits of jurisdiction.
(1)	(2)
Professor Abdul Majid Siddiqi, Professor in Chemistry, Aligarh Muslim University, Aligarh.	Premises within the territorial local limits of Aligarh District belonging to and under the administrative control of the Aligarh Muslim University, Aligarh.

[No. F. 3-82/82/Desk (U)]  
ASSA SINGH, Desk Officer

## भारत और पुनर्वासि मंत्रालय

(भारत विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 1982

का०आ० 4009.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपायय प्रनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में विवादास्पद पतन न्यास के प्रबंधन से सम्बन्धित एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्दिष्ट करना वांछनीय समझती है;

अतः केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एस०वी० रामना रेड्डी होंगे, जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्दिष्ट करती है।

अनुसूची

क्या एस०वी० अनुभाग के धारा 11 के प्रावधानों को जूते देने से इंकार करने की विवादास्पद पतन न्यास के प्रबंधन की कार्रवाई न्यायोचित है? यदि नहीं तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार है?

[सं० एन०-34011(10)/82-डी० iv(ए)]

टी०बी० सीतारामन, डेस्क अधिकारी

## MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour)

## ORDER

New Delhi, the 14th October, 1982

S.O. 4009.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Visakhapatnam Port Trust and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas, the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri S. V. Ramana Reddy shall be the Presiding Officer, with headquarters at Hyderabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

## SCHEDULE

"Whether the action of the management of Visakhapatnam Port Trust in refusing to supply shoes to Grade-II Drivers of M. V. Section is justified? If not, to what relief are the concerned workmen entitled?"

[No. L-34011(10)/82-D. IV(A)]

T. B. SITARAMAN, Desk Officer

आदेश

नई दिल्ली 20 अक्टूबर, 1982

का०आ० 4010.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपायय प्रनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में दक्षिण रेल प्रशासन के प्रबंधन से सम्बन्धित एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्दिष्ट करना वांछनीय समझती है;

अतः केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी०बी० रामना रेड्डी होंगे, जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्दिष्ट करती है।

अनुसूची

'रेल बोर्ड' के पत्र संख्या पी०जी०-72/आर०एल०टी०/69-3, ता० 12-6-74 में अतिरिक्त आदेशों को ध्यान में रखते हुए, क्या दक्षिण रेल प्रशासन उन पुनर्नियुक्त किए गए श्रमिकों को, जिनकी पहले छुट्टी की गई थी और जो अपनी छुट्टी के समय मजदूरी की स्केल पर प्राप्त कर रहे थे, मजदूरी की स्केल दूर कर संवाय न करना न्यायोचित ठहराया जा सकता है? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार है?

[एल०-41011(6) 82-डी०-II-बी]

एस०एस० पराशर, डेस्क अधिकारी

## ORDER

New Delhi, the 20th October, 1982

S.O. 4010.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Southern Railway Administration and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule

in the Schedule hereto annexed ;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri T. Arul Raj shall be the Presiding Officer, with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

#### SCHEDULE

"The view of the Railway Board's orders contained in letter No. PG-72/RLT/69-3 dated 12-6-1974 whether the Southern Railway Administration is justified in not paying the scale rate of wages to re-engaged workers who were retrenched earlier and were in receipt of the scale rate of wages at the time of their retrenchment ? If not, to what relief are the workmen entitled ?"

[No. L-41011(6)/82-D. II (B)]

New Delhi, the 23rd November, 1982

**S.O. 4011.**—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Airforce Halleswar, Post Office Tezpur, District Darrang, Assam, and their workmen, which was received by the Central Government on the 17th November, 1982.

#### CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA.

Reference No. 30 of 1982

#### PARTIES :

Employers in relation to the management of Airforce, Halleswar, P. O. Tezpur, Distt. Darrang, Assam.

#### AND

Their Workmen.

#### PRESENT :

Mr. Justice M. P. Singh.—Presiding Officer.

#### APPEARANCES :

On behalf of Employers.—Absent

On behalf of Workmen.—Absent.

STATE : ASSAM

#### AWARD

By Order No. L-14012/3/81-D. II(B) dated 23 August 1982 the Government of India, Ministry of Labour sent to this Tribunal the following dispute for adjudication :

"Whether the action of Garrison Engineer, Airforce, M.E.S. Tezpur in discharging Shri Kamal Chandra Keot, Valveman from service w.e.f. 24-8-72 is justified ? If not, to what relief the workman is entitled ?"

2. On receipt of the Reference notices were issued to parties fixing 2-11-1982 as first hearing date with direction to file their respective documents and written statements, if any. But to-day when the case was called out nobody appeared. The Tribunal received a letter from the office of Garrison Engineer Airforce, Tezpur, P. O. Halleswar intimating that the concerned workman Sri Kamal Chandra Keot,

Valveman had been reinstated and he reported for duty on 14th July, 1982 (Forenoon). In view of above there seems to exist no dispute in the matter.

I, therefore, pass a 'No Dispute' Award in the case.  
Dated, Calcutta,  
The 2nd November, 1982.

Sd/-

M. P. SINGH, Presiding Officer,

[No. L-14012(3)/81-D. II (B)]

New Delhi, the 23rd November, 1982

**S.O. 4012.**—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Security Paper Mills, Hoshangabad, and their workmen, which was received by the Central Government on 9-11-82.

BEFORE JUSTICE SHRI S. R. VYAS (REGD.) PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

Case No. CGIT/LC(R) (45) of 1981

#### PARTIES :

Employers in relation to the management of Security Paper Mills, Hoshangabad and their workmen represented through the S.P.M. Staff Union, C/o Security Paper Mills, Hoshangabad (M.P.).

#### APPEARANCES :

For Workmen.—Shri P. S. Nair, Advocate.

For Management.—Shri K. K. Adhikari, Advocate.

INDUSTRY : Paper Mills DISTRICT : Hoshangabad (M.P.)

#### AWARD

Hoshangabad, the 29th October, 1982

This is a reference made by the Central Government in the Ministry of Labour vide Notification No. L-42011(12)/80-D. II (B) dated 20th November, 1981, for adjudication of the following dispute by this Tribunal :—

"Whether the action of the management of Security Paper Mills, Hoshangabad in denying overtime and night duty allowances to its staff members drawing basic pay of Rs. 751 and above is legal and justified when their counterparts in Indian Security Press, Nasik are entitled to such allowances ? If not, to what relief the concerned workmen are entitled ?"

2. Facts which are not in dispute in this case are as under :—

Workmen in this case are the employees of the Security Paper Mills, Hoshangabad, hereinafter referred to as the Mills. The Mills employ different categories of workmen some of whom are getting Rs. 750 p.m. as wages. Neither any Overtime Allowance nor any Night Duty Allowance is paid by the Mills management to such workmen who are drawing their basic pay of more than Rs. 750 p.m. Workmen claim that since in the Indian Security Press at Nasik such allowances are paid to such members of the staff whose basic pay is more than Rs. 750 p.m. the Mills management is not justified in denying such allowances to them also. As the claim made by the workmen of the Mills was not conceded to by the Mills management an industrial dispute was raised which has resulted in the present reference to this Tribunal.

3. The case of the workmen is that in the Indian Security Press, Nasik, which is also an Undertaking of the Government of India as also in other Government Undertakings

like Ordnance Factory etc. Overtime Allowance and Night Duty Allowances are paid to those employees whose basic pay is more than Rs. 750 ; that those workmen who are receiving these two allowances in the Indian Security Press, Nasik and other Undertakings of the Government of India are employees of the same Government of which these workmen are the employees; that in the other establishment of Security Press Nasik there is no ceiling of basic pay for entitlement of these two allowances; that in the Ordnance Factory Khamaria, Jabalpur, Ordnance Factory Itarsi, Government Mint at Calcutta, Hyderabad and Bombay, Central Government pays these two allowances to the workmen even though their basic pay is more than Rs. 750; that duty hours of the employees are fixed at 8 hours per day and taking duties from the workmen beyond this duty period of 8 hours without payment of Overtime Allowance is not legal; that the Government cannot discriminate the case of one employee with the case of the other employees in the other establishment; that Overtime & Night duties involve extra physical and mental burden on the workmen and that denial of Overtime and Night Duty Allowances to the workmen by the Government and grant the same allowances to the similar workmen working in similar undertakings is a clear discrimination in law by the Government of India.

4. On behalf of the management, it is contended that members of the Security Papers Mills Staff Union (at whose instance the present reference has been made) are not workers as defined under the Factories Act, 1948; that overtime allowance of the workers who are covered under the Factories Act is regulated under Sec. 59 of the Factories Act; that these workmen are non-industrial workmen in the Mills; that the question of overtime allowance of workers of the Mills except those covered under Sec. 59 of the Factories Act is regulated by the Government of India Circulars referred to in Annexures A to E; that in accordance with these circulars overtime allowance is not payable to those employees who have been drawing basic pay Rs. 750 and above; that in accordance with the Ministry of Finance letters (Annexures H to Annexure I) the industrial and non-industrial employees drawing a basic salary exceeding Rs. 750 are not eligible for Night Shift Allowance; that these circulars are applicable to all departmental undertakings of the Government of India; that the terms and conditions with regard to Overtime and Night Shift Allowances which are applicable to the members of the Staff of the Security Press, Nasik, cannot be made applicable to the non-industrial employees of the Mills; that the Government of India have a number of industrial undertakings and unless the dispute referred to for adjudication is in respect of all the Industrial Undertaking; the employees of the Mills cannot choose one undertaking only for determination of the question of Overtime and Night Shift Allowances; that the Government have the absolute right to determine the terms and conditions of service of the employees of a particular undertaking; that Overtime Allowance and Night Shift Allowance is paid to the employees of the Indian Security Press, Nasik by two different orders of the Government of India (These orders are referred to in Para 11 of the statement); that the Government are justified in regulating, fixing and prescribing different scales of pay and other allowances for different industrial undertakings; that in the Security Paper Mills the employees are getting production incentive allowance which is not paid to the employees of the Security Press at Nasik and that in the Security Press, Nasik and Security Paper Mills at Hoshangabad the working hours are different.

5. Rejoinder was filed only by the workmen and not by the Mills. In this rejoinder the workmen have reiterated the allegations of discrimination allegedly being made by the Government as also for their entitlement to the Overtime and Night Shift Allowances at par with the employees of the Security Press at Nasik.

6. On these pleadings of the parties, the following issues were framed :—

#### ISSUES

- 1(a) Whether the workmen of the Security Paper Mills Hoshangabad are entitled to claim Overtime Allow-

ance and Night Shift Allowance as claimed in this case ?

- (b) If so, from what date and at what rates ?

#### 2. Relief.

7. My findings on the aforesaid issues are as under :—

Issue No. 1(a).—That the workmen of the Security Paper Mills Ltd. drawing pay of Rs. 751 or more are entitled to Overtime and Night Shift Allowance at the same rate at which the same is being to the similar employees of the Security Press at Nasik.

Issue No. 1(b) & (2).—As per order passed below, Reasons for the above findings :

8. Issue No. 1(a).—In this case no oral evidence has been given by either party. Only the management of the Mills has filed certain Government Circulars/Orders etc. in support of its contentions. Accordingly in the absence of any oral evidence the issues referred to above have to be decided on the basis of the pleadings of the parties and the documents filed by the management.

9. Ex. M/10 is the first document in order of time dated 10-8-1927 from the Finance Department, Government of India, addressed to the Master, Security Printing, India which gives him power to employ overtime labour to meet the work. It also specifies the manner in which the overtime is to be paid. Ex. M/11 is the next order of the Finance Department, Government of India, dated 6-1-1942 which allows 25 per cent more in addition to normal days pay as Night Shift Allowance. The next order of the Government in order of time is Ex. M/1 dated 8-3-1968 by which overtime allowance was allowed to non-industrial staff of the Mills for work done in excess of 48 hours on the terms and conditions stated therein. Ex. M/7 is the next document in order of time dated 10-2-1970. By this order the Finance Ministry allowed Night Duty Allowance to non-industrial employees of the Mills drawing pay upto Rs. 470 Ex. M/2 is the next document dated 18-5-1972 by which calculation of the rate of overtime allowance was fixed. By Ex. M/3 dated 13-10-1972 the period of work for entitlement of overtime and night shift allowances to workmen drawing basic pay of Rs. 500/- was regulated. Ex. M/4 dated 1-5-1974 is the next order of the Finance Ministry by which the ceiling of Rs. 500/- was raised to Rs. 750/-. To the same effect is order Ex. M/5 dated 6-1-75. The last order is dated 6-6-1980 Ex. M/6. By this order the General Manager of the Mills was informed by the Ministry of Labour that the limit of Rs. 750/- has been fixed on the recommendation of the Third Pay Commission and is applicable to all Industrial undertakings of the Government. It was further stated in this letter dated 6-6-1980 that under Sec. 64(1) of the Factories Act payment of overtime allowance to employees drawing pay Rs. 750/- or more per month is barred.

10. From the aforesaid documentary evidence it would therefore be clear that sometime in the beginning overtime/night duty allowance was payable but subsequently the ceiling was fixed at Rs. 470 Rs. 500 and lastly at Rs. 750.

11. Section 59 of the Factories Act referred to in the statement of demand provides that where a worker works in a factory for more than nine hours in any day or more than forty-eight hours in any week, he shall be entitled to overtime wages at the rate of twice his ordinary rate of wages. Sub-section (1) of Sec. 64 referred to in Ex. M/6 dated 6-6-1980, with is the last order of the Government, Provides for making rules to define persons who holds position of Supervision or management or who are employed in confidential position in a factory. No document has been produced before this Tribunal about the making of such rules or definition of persons holding the position of supervision or management employed as a confidential position in the factory. In the light of the aforesaid documentary evidence given by the management only, the only question that arises for consideration is as to whether the non-payment of overtime and night shift duty allowance of employees getting Rs. 750/- or more can be said to be justified only on the basis of the Government Order ?



12. The grievance of the workmen that their counter-parts in the Security Press at Nasik are being paid these two allowances and the same are being denied to them.

13. In para 11 it is stated by the management that restrictions imposed by the Government Order dated 1-5-1974 (Ex.M/4) for payment of overtime allowance to persons getting Rs. 750 is applicable to all the industrial undertakings of the Government including the Indian Security Press at Nasik. It is, however, admitted in this paragraph that despite the imposition of ceiling non-industrial employees of the Security Press at Nasik are paid overtime at the single rate in view of an old practice of paying this allowance without putting any limitation by virtue of the Government of India in the Finance Ministry's letter dated 16-8-1927 (Ex. M/10). It is also admitted that night shift allowance is also allowed to the employees of the Security Press in view of the order dated 6-1-1942 (Ex. M/11).

14. It would thus be clear that despite the order Ex. M-10 dated 16-8-1927 and Ex. M/11 dated 6-1-1942 and the subsequent orders passed by the Government of India by which ceilings have been fixed the employees of the Security Press are paid overtime and night shift allowances by the Government of India. Government of India is the owner of the Security Press at Nasik and the Security Paper Mills at Hoshangabad. An important question arises as to whether there can be any discrimination between the two employees of the same employer in the matter of payment of overtime and night shift allowances?

15. Though the Government have absolute right to fix different scales of pay and allowances according to categories of employees in different industrial undertakings but there can be no departure from the basic principle of equal pay for equal work which is deducible from the constitutional provisions of the Constitution of India.

16. The question whether there can be any such discrimination as is apparent in this case was considered in the case of *Randhir Singh Vs. Union of India and others* (AIR 1982 SC 879). In that case their Lordships were considering the case of a Driver in the Delhi Police Force whose pay scale was different and lower as compared to the other drivers in the Railway Protection Force and other Departments of the Government. Considering the question as to whether the principle of equal pay for equal work is or is not a fundamental right or an abstract doctrine, it was held by their Lordships as under :—

"Construing Articles 14 and 16 in the light of the Preamble and Art. 30(d), we are of the view that the principle 'Equal pay for Equal work' is deducible from those Articles and may be properly applied to cases of unequal scales of pay based on no classification or irrational classification though those drawing the different scales of pay do identical work under the same employer."

On the facts of that case their Lordships directed the Delhi Administration to fix the scale of pay of the Petitioner at least at par with the scale of pay of the Drivers of the Railway Protection Force which was higher than the scale of pay admissible to the petitioner driver-constable in that case.

17. In this case in para 11 referred to above the management admits that the ceiling of Rs. 750 for non-entitlement of night shift and overtime allowances though applicable to the non-industrial employees of the Security Press also but that is being paid because of the two orders of 1927 and 1942 (Ex. M/10 and Ex. M/11). It is not understood as to why when employees of the same employer i.e. Government of India in this case are being paid overtime and night duty allowances to employees of one industrial undertaking the same should be denied to the employees of the other industrial undertaking of the same employer.

18. It may also be observed that there are fixed working hours of the employees in all the industrial undertakings. At some stage employees getting less than Rs. 750 were allowed overtime and night shift allowance but the same is being

denied now. How can an employee in an industrial undertaking be asked to work overtime without payment of overtime allowance. Night shift allowance is paid because an employee is required to work during night hours which are not the normal hours of work. However, on principles of 'equity' and on the principle of 'Equal pay for Equal work' the claim by the workmen in this case appears to be justified. Though it was stated that the conditions of working in the Security Press at Nasik and Security Paper Mills at Hoshangabad are different but there is not an iota of evidence placed before this Tribunal by the management to show as to whether and to what extent the difference lies in the work and method of these two industrial undertakings. If some material has been placed before this Tribunal to justify the discrimination the matter could have been considered in the light of the material so placed, but since that has not been done the only inference is that the general conditions of both the industrial undertakings under which the employees getting pay over Rs. 750 is the same. Consequently, there is no justification made out by the management for discrimination in the matter of payment of overtime and night shift allowances.

19. Issue No. 1(b) & (2).—As per orders passed below.

20. Accordingly for the reasons given above, the following award is given :—

The workmen of the Security Paper Mills Ltd., Hoshangabad who are drawing pay over Rs. 750 are entitled to overtime allowance and night shift allowance at par with such allowances being paid to the similar employees of the Security Press at Nasik. Such allowance shall be paid to these workmen from the date of this award.

In the circumstances of the case, both the parties shall bear their own costs as incurred.

S. R. VYAS, Presiding Officer

[No. L-42011(12)/80-D.II(B)]

S. S. PRASHER, Desk Officer

आदेश

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1982

कां०आ० 4013.—केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, म्यू. मंगलोर पोर्ट और टूटिकोरिन पोर्ट के अध्यक्ष से यह आदेश करता है कि वह औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम, 1957 में विहित मामलों के लिए अपने अधीन औद्योगिक स्थापन में एक कार्य समिति गठित करे।

[का० सं० एम०-11018(6)/81-डी 1(ए)]

ORDER

New Delhi, the 4th November, 1982

S.O. 4013.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby requires the Chairman of New Mangalore Port and Tuticorin Port to constitute a Works Committee in the industrial establishment under him in the manner prescribed in the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957.

[F. No. S-11018(6)/81-D.I(A)]

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1982

कां०आ० 4014.—केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 3-ग की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के भूतपूर्व अथ, रोजगार और पुनर्वसि मंत्रालय (अथ और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का०नि० 4650 तारीख 19 दिसम्बर, 1967 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्



उक्त अधिसूचना से उपर्युक्त सारणी में कम से 9 और उससे अधिक प्रकृतियों के म्यान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् --

Belgum District Utr  
Karna District By pur  
District and Plow d  
District

9 (क) कर्नाटक राज्य सरकार  
द्वारा गठित श्रम न्ययानालय  
हुवनी

मुलबागि जिला बहिर जिला राश्वर जिला  
बल्लारो जिला बेलगांम जिला  
उत्तर कानारा जिला, बीजापुर  
जिला और धारवा जिला।

9(b) Labour Court Bangalore To State of Karnataka  
excluding Gulbarga and  
Belgaum Divisions

9 (ख) अथ स्यात् न च द्वगलस्य गलवर्गा श्रीर वेनगाम प्रथमो को  
छोत्कर कर्तव्य राज्य

Note: Principal Notification published by vide S.O. 4650 dated the 19.12.67, Part II, Section 3 Sub-section (ii) of Gazette of India dated the 30.12.1967 subsequently amended by

निष्पन्न मूल अग्रिम्बन्धनः क. प्र. ० १६५० तारीख १९-१२-६७  
भारत के राजपत्र भाग २ खंड ३ उपखंड (१) तारीख  
३०-१२-६७ को प्रकाशित हो गई और तत्पश्चात् निम्नलिखित  
द्वारा उसका संपादन किया गया

(i) Notification No. SO 1175 dated 20-2-68 Gazette of 30-3-68

(ii) Notification No S O. 668 dated 11-2-6 Gazette of 22-2-60

(1) आधुनिकता संकाय ० ११७५ तारीख २०-३-६८ ३०-३-६८ वा  
गजपत्र

(iii) Notification No. S.O. 1894 dated 9-5-69 Gazette of 17-5-69

(11) अधिसूचना सं. का.अ. 668 तारीख 11-2-69 22-2-69 का  
र जपत्र

(iv) Notification No S O 1768 dated 20.4.69, Gazette of 10-5-69

(111) अधिसूचना सं० का०आ० 1894 तारीख 9-5-69 17-5-69  
का राजपत्र

(v) Notification No. S.O. 2696 dated 3-7-71 Gazette of 24-7-71

(IV) अधिसूचना सं० का०प्रा० 1768 तारीख 30-4-69, 10-5-69  
का राजपत्र

(vi) Notification No S O 3510 dated 23.9.72 Gazette of India 41-1-72

(v) अधिसूचना सं० का०घ्रा० 2796 तारीख 3-7-71 24-7-71  
का राजपत्र

(vii) Notification No S O 4521 dated 26-9-75, Gazette of 18-10-80

(vi) अधिमूचना सं. कां.आ. 3810 तारीख 23-9-72, 4 11 72  
का राजपत्र

(viii) Notification No. G.O. 2914 dated 13-10-80, Gazette of 25-10-80

(vii) अधिचना सं० का०अ० 4521 तारीख 26-9-75, 18-10-80  
का राजपत्र

(ix) Notification No. S.O. 45 dated 10-12-81, Gazette of 2-1-82

(VIII) अधिसूचना सं० कांआ० 2914 तारीख 13-10-80  
25-10-80 का राजपत्र

(x) Notification No S O 1613 dated 16-4-82, Gazette of 1-5-82

(IX) अधिसूचना सं. कां. प्रा. 45 तारीख 19-12-81, 2-1-82 का राजपत्र

[N<sup>o</sup> S 11020 (9)/81 D I (A)]

L K NARAYANAN Under Secy

नई दिल्ली 22 नवम्बर 1982

का.आ. 4015 - केन्द्रिय मन्त्रालय के यह रूप है कि राक पाम्फलेट (प्रपाट इट खातो) के नियोजन के बबन मजदूर के द न्यूनतम मजदूरी प्राधिनियम 1948 (1948 का 11) के अधिनियम का ज्ञान वाणिज्य

(X) अधिसूचना सं० का०आ० 1633 तारीख 16-4-82, 1-5-82  
का राजपत्र

अ० कन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के धारा १७ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत हुए उक्त नियोजन वा उक्त अधिनियम के अनुसर्ज के भाग १ से जाने के अपने अणय के सूचना दन "

[सं० एस-11020/9/81-जि० प्र ई० प]०

तल०के० नारायणन अवर सचिव

New Delhi the 22nd November 1982

**S. O. 4014** . In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 33-C of the Industrial Disputes Act, 1947 (4 of 1947), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S. O. 4650, dated the 19th December, 1967, namely:

In the Table annexed to the said Notification, for serial No. 9 and the entries relating thereto the following shall be substituted, namely:—

"2) (1) Lab 101 Co 1 Hubli cons- Gulbarga District, Bidar  
tired by th Sate Go- Dist,  
vernmento Kuria ka Raichur District, Bellary  
Dist

[एस 32017/38 डायरी (एस - 4)]

पम० ३० महंत अवर मचिव

New Delhi, the 22nd November 1982

**S.O 4015.**—Whereas the Central Government is of opinion that the minimum rates of wages should be fixed under the Minimum Wages Act 1948 (11 of 1948) in respect of the employment in Rock Phosphate (Apatite Mines),

Now, therefore in exercise of the powers conferred by Section 27 of the said Act the Central Government hereby gives notice of its intention to add the said employment to Part-I of the Schedule to the said Act.

Any suggestions or objections which may be received from any person in respect of the said addition on or before the expiry of a period of three months from the date of publication of this notification in the Official Gazette, will be considered by the Central Government.

[No S-32017/3/81-WC (M.W.)]

M. L. MFHTA, Under Secy.

New Delhi the 22nd November, 1982

**S.O. 4016**—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Hyderabad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Singareni Collieries Co. Limited Kothagudem, and their workmen, which was received by the Central Government on the 13th November, 1982.

**BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL)  
AT HYDERABAD**

Industrial Dispute No. 20 of 1980

**BETWEEN**

Workmen of Singareni Collieries Company Limited,  
Kothagudem, Khammam District (A.P.).

**AND**

The Management of Singareni Collieries Company  
Limited Kothagudem, Khammam District (A.P.).

**APPEARANCES :**

Sri D. S. R. Varma, Advocate—for the Workmen.

Sri K. Srinivasa Murthy, Honorary Secretary Andhra Pradesh Chambers of Commerce and Industry,  
Hyderabad—for the Management

**AWARD**

By Order No. L-21012(1)/80-DIV.B, dated 15-12-1980, the Government of India referred the following industrial dispute existing between the Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem and their Workmen to this Tribunal for adjudication :—

"Whether the management of Messrs Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem is justified in dismissing Sri D. Subbarao, Watchman, Manuguru Collieries with effect from 7-4-1980? If not to what relief is he entitled?"

2. After the above industrial dispute was taken on file in I.D. No. 20 of 1980 on 22-12-1980, notices were issued to both the Management and the Workmen. The Workmen filed their claims statement on 12-2-1981. To the above claims statement, the Management filed their counter on 17-3-1981. Sri K. Srinivasa Murthy appeared for the Management as Management's representative whereas Sri D.S.R. Varma filed his vakalat for the Workmen with the consent of the other side. The case underwent some adjournments for enquiry.

3. While so, on 9-8-1982, a compromise petition signed by the Management and the Workmen was filed into this Tribunal. Since the parties were absent on that day, the compromise petition numbered as M.P. No. 100/82 was posted to 27-8-1982 for appearance of the parties to record the compromise. On 27-8-1982 Sri. V. Gopala Sastry, Deputy Chief Personnel Manager of the Company was present. He admitted the execution and the terms of the compromise read over to him. As the Workmen were not present on that day, the case was adjourned from time to time till today. Today also the Workmen were absent. The advocate of the Workmen namely, Sri D. S. R. Varma who is present for

the Workmen admits the truth and the execution of the compromise and the terms thereof. Hence the compromise is recorded today.

4. The following are the terms of the compromise recorded in M.P. No. 100/82 :—

- "(1) The Management agreed to consider the case of Sri D. Subba Rao, Ex-Watchman, S&PC., Manuguru on compassionate grounds
- (2) Sri D. Subba Rao will be reappointed as Watchman, S&PC., in the Company and posted in any Division. He will be allowed the basic pay he was drawing at the time of his dismissal.
- (3) The intervening period i.e. from the date of dismissal to the date of his reporting for work on re-appointment will be treated as leave on loss of pay. Mr. Subba Rao shall not have any claim for wages or other benefits during the intervening period.
- (4) The parties are filing this compromise on the above terms and conditions before the Hon'ble Tribunal, in full and final settlement of the dispute, with a prayer to the Hon'ble Tribunal to pass an Award accordingly"

5. In view of the above compromise admitted by both the parties, this Award is passed in terms of the above compromise. A copy of the compromise petition is appended to this Award.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him and corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 15th day of October, 1982.

'No. L-21012(12)/80-DIV(B)]

Sd/-

S. S. MFHTA, Desk Officer  
Industrial Tribunal

**APPENDIX OF EVIDENCE**

—NII—

Sd/-

Industrial Tribunal

**BEFORE THE HON'BLE INDUSTRIAL TRIBUNAL  
(CENTRAL), HYDERABAD**

In the matter of I.D. No 20 of 1980

**BETWEEN**

The Workmen of S.C. Co Ltd, Manuguru Division.

—Claimant/Workman.

**AND**

The Management of S.C. Co. Ltd, Manuguru Division.  
Respondent/Management.

It is submitted that without prejudice to the merits of the case before the Hon'ble Industrial Tribunal (Central), the parties desired to settle the issue mutually. Accordingly, the issue is settled on the terms and conditions set out hereunder :—

- "(1) The Management agreed to consider the case of Sri D. Subba Rao, Ex-Watchman, S&PC., Manuguru on compassionate grounds.
- (2) Sri D. Subba Rao will be reappointed as Watchman, S&PC., in the Company and posted in any Division. He will be allowed the basic pay he was drawing at the time of his dismissal.
- (3) The intervening period i.e. from the date of dismissal to the date of his reporting for work on re-appointment will be treated as leave on loss of pay. Mr. Subba Rao shall not have any claim for wages or other benefits during the intervening period.

- (4) The parties are filing this compromise on the above terms and conditions before the Hon'ble Tribunal, in full and final settlement of the dispute, with a prayer to the Hon'ble Tribunal to pass an Award accordingly".

In the circumstances, both the parties pray the Hon'ble Industrial Tribunal (Central), to pass an Award in terms of the above compromise.

For Workmen :

Sd/-

(M. Komariah),  
General Secretary,  
Singareni Collieries Workers' Union.  
Sd/- D. Subba Rao.

Dated : 13-7-1982.

Kothagudem Collieries.

For Management :

Sd/-

(R. D. Sharma),  
Executive Director,  
M/s. The Singareni  
Collieries Company Limited.

New Delhi, the 23rd November, 1982

**S.O. 4017.**—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Deoli Colliery, Ranipur Sub-Area of Messrs Eastern Coalfields Limited, and their workmen, which was received by the Central Government on the 17th November 1982

#### CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, CALCUTTA

Reference No. 51 of 1978

#### PARTIES :

Management of Deoli Colliery, Ranipur Sub-Area,  
Eastern Coalfields Limited

AND

Their Workmen.

#### APPEARANCES.

On behalf of Management—Mr. J. N. Mishra, Senior  
Personnel Manager.

On behalf of Workmen—Absent

STATE : West Bengal

INDUSTRY : Coal Mine

#### AWARD

The following dispute was sent to this Tribunal by the Government of India, Ministry of Labour vide Order No. L-19012(63)/77-D.IV(B) dated 12th May, 1978, for adjudication :

"Whether the action of the management of Ranipur Sub-Area of Eastern Coalfields Limited in stopping

Shri Umapada Kumbhakar, Office Boy of Deoli Colliery from work with effect from 30-4-73 is justified? If not, to what relief is the concerned workman entitled?"

2. No one appeared on behalf of the workman. The management is present and the case has been heard *ex-parte*. The case of the Coal Mine Employees Union, Disheigarth (Briefly the Union) is that the concerned workman Umapada Kumbhakar was an office boy of the colliery and he worked as such till 29th April, 1973. But the management illegally stopped him from work with effect from 30th April 1973 on the ground that he was a minor. The management of the Deoli Colliery, Ranipur Sub-Area of Eastern Coalfields Ltd. contends that the reference is not maintainable against the Government company, the dispute having arisen prior to 1st May, 1973 the appointed date as per the coal-mines Nationalisation Act, 1973 and also because no industrial dispute existed between the parties concerned. It is denied that the concerned workman was an office boy of the colliery. The management stated that the concerned workman was a domestic servant of an officer of the colliery and was aged only 14 years.

3. In view of the order dated 1st October, 1980 passed in this case by Sri R. Bhattacharya, my predecessor-in-office, it is not necessary to go into the merits of the case or other contentions of the management. By that order it has been held that no appreciable number of workmen of Deoli colliery were members of this union, that no appreciable number of workmen authorised the union to espouse the cause of the workman and that the union had no authority or locus standi to espouse the cause of the concerned workman and had no representative character to represent the workmen of the Deoli colliery. It has also been held by that order that the present dispute is, therefore, not an industrial dispute. After having held so the Learned Tribunal applied Section 2A of the Act and directed the concerned workman to authorise the Joint Secretary of the Union or any other competent person to conduct his case. In my opinion this case cannot be treated as one under Section 2A of the Act. No individual workman raised any industrial dispute in this case. It was the Union who raised the present industrial dispute. It was a collective dispute which was referred to this Tribunal for adjudication. When the union has been held to have no locus standi to espouse the cause of Umapada Kumbhakar the reference is not maintainable. I see the Division Bench case of Calcutta High Court in Deepak Industries Ltd. and another vs. State of West Bengal and Others, 1975 Lab. IC 1133. In Swapan Dasgupta v. 1st Labour Court, West Bengal, 1976 Lab. IC 202 at 206, Para 9, it has been held by Sabyasachi Mukherji J. that when the reference is not under Section 10 read with Section 2A, that is to say, the reference has not been made on the ground that there is a dispute existing between the employer and the individual workman, the reference cannot be upheld on the ground of Section 2A of the Act. Further more, it has to be noticed that it is a case of non-employment, that is, stopping the concerned workman from work and not a case of dismissal, discharge or termination of service and hence Section 2A of the Act can have no application.

Accordingly I hold that the present reference is not maintainable and it is dismissed as such.

Dated, Calcutta,

The 2nd November 1982.

Sd/-

M. P. SINGH, Presiding Officer

[No. L-19012(63)/77-D.IV(B)]

S. S. MEHTA, Desk Officer

New Delhi, the 23rd November, 1982

**S.O. 4018.**—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Hyderabad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of Hyderabad and their workman, which was received by the Central Government on the 13-11-82.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) :  
AT HYDERABAD.

INDUSTRIAL DISPUTE NO. 9 OF 1982.

BETWEEN :

The Workmen of  
State Bank of Hyderabad.

AND

The Management of  
State of Bank of Hyderabad.

APPEARANCES :

Sri B. V. Raghavulu, President, State Bank of Hyderabad  
Staff Association for Workmen.

Sri K. Srinivasa Murthy, Honourary Secretary, Andhra  
Pradesh Federation of Commerce and Industry,  
Hyderabad for Management.

AWARD

By Order No. L-12011/41/81-D II(A), dated 19-2-1982,  
The Government of India referred the following industrial  
dispute existing between State Bank of Hyderabad and their  
Workmen to this Industrial Tribunal for adjudication :—

"Whether the management of State Bank of Hyderabad  
is justified in discontinuing the subsidised transport  
facility provided to the Workmen working at their  
Ramchandrapuram Branch, Medak District, Andhra  
Pradesh with effect from 1st June, 1981?"

2 After the above industrial dispute was taken on file in  
I. D. No. 9 of 1982 on 25-2-1982, notice were issued to  
both sides. The workmen engaged their representative,  
namely, Sri B. V. Raghavulu, whereas the Management  
engaged Sri K. Srinivasa Murthy. The Workmen took some  
adjournments for filing their claims statement. Then both  
parties represented that the matter was under talks of  
compromise.

3 Ultimately today both the parties, representing that  
they settled this dispute out of Court, filed a joint memo  
withdrawing the industrial dispute. Accordingly permission  
was granted to the parties for withdrawing the dispute and  
this Award is passed. A copy of the joint memo is  
appended to this Award.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him and  
corrected by me and given under my hand and the seal of  
this Tribunal, this the 29th day of October, 1982.

INDUSTRIAL TRIBUNAL.

APPENDIX OF EVIDENCE :

--NIL--

S. V. RAMANA REDDY, Presiding Officer.

[No. L-12011/41/81-D.H(A)]

N. K. VERMA, Desk Officer

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL)  
AT HYDERABAD A. P.

Industrial Dispute No. 9 of 1982

BETWEEN

The Workmen of State Bank of Hyderabad.

AND

The Management of State Bank of Hyderabad.

JOINT MEMO FILED BY BOTH THE PARTIES

It is submitted that

The petitioners pray that the petition be treated as  
withdrawing as the dispute no longer exists.

For Management

(P. V. Bapiraju)

Manager,  
Personnel Administration Dept.,  
State Bank of Hyderabad  
Hyderabad.

Hyderabad.  
29-10-82.

For Petitioner

(B. V. RAGHAVULU, President)

State Bank of Hyderabad Staff Association.

New Delhi, the 24th November, 1982

S.O. 4019.—In pursuance of section 17 of the Industrial  
Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government  
herby publishes the following award of the Central Govern-  
ment Industrial Tribunal Court No. 1, Bombay in the indus-  
trial dispute between the employers in relation to the Food  
Corporation of India, Bombay and their workmen, which  
was received by the Central Government on the 6th Novem-  
ber, 1982.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL  
TRIBUNAL NO. 1 AT BOMBAY

PRESENT :

Justice M. D. Kambl Esqr, Presiding Officer

Reference No. CGIT 24 of 1978

PARTIES :

Employers in relation to the Food Corporation of India.

AND

Their Workman

APPEARANCES :

For the employer.—Mr. S. G. Ghate, Advocate.

For the workman.—Mr. A. R. Atrey, Advocate.

INDUSTRY : Food Corporation

STATE : MAHARASHTRA

Camp : Nagpur

Nagpur, the 20th October, 1982

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by order  
No. L-42012(7)/78-D. II(B), dated 4th December, 1978,  
in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-  
section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act,  
1947, referred to this Tribunal for adjudication an industrial  
dispute between the employers in relation to the management  
of the Food Corporation of India and their workman in  
respect of the matters mentioned in the schedule given  
below.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of the Food  
Corporation of India (Maharashtra Region), Bom-  
bay in removing Shri D. C. Thakkar, Jeep Driver,  
from service with effect from the 23rd March, 1977  
is justified? If not, to what relief is the said work-  
man entitled?"

2. The workman, D. C. Thakkar, Jeep Driver, was in the  
employment of the Food Corporation of India (Maharashtra  
Region). He has been removed from service after hold-



ing a domestic inquiry with effect from 23-3-1977. The point to be decided in this reference is whether the action of the management in removing the workman from service is justified.

3. The workman was chargesheeted on the following charges :—

- (1) That in spite of repeated instructions given, Shri D. C. Thakkar, Driver Grade II refused to comply with and obey lawful orders and refused to wear uniform thus contravened conduct Regulation 31(d) and 32 of the F.C.I. (Staff) Regulations, 1971.
- (2) That Shri D. C. Thakkar, wilfully absented from duty w.e.f. 16-9-75 to 26-12-75 and again w.e.f. 5-1-1976 till date to avoid wearing uniform thus contravened Regulation 24(iv) & (vi) of FCI (Staff) Regulations, 1971.
- (3) That Shri D. C. Thakkar, misbehaved with the acting District Manager, Shri N. G. Tongrekar on 12-8-75 and also with the Asst. Manager (Audit) camp Nagpur during August 1975 when he was instructed in writing to wear uniform, contravening the conduct Regulation 31 of the FCI (Staff) Regulations, 1971.
- (4) That Shri Thakkar, purchased 20 liters petrol on credit coupons, when there was sufficient petrol in tank of Jeep No. MPJ-8883 and 20 liters petrol could not be accommodated in the tank. Thus Shri Thakkar has misappropriated and used petrol for non-official use.
- (5) That Shri D. C. Thakkar, Driver is doing private business of plying three wheeler as Taxi, contravening the conduct Regulations 24(iii) and 45(i) of the FCI (Staff) Regulations, 1971.

4. One Miss. I. M. Tahilani was appointed as the Inquiry Officer. She issued a notice dated 20th October, 1976, calling upon the workman to attend the hearing on 29-11-1976. Accordingly, the Inquiry Officer held the inquiry which she called the preliminary hearing on 29-11-1976 at the office of the Zonal Manager, Ministry Bhavan, Bombay. Accordingly, the delinquent workman remained present before the Inquiry Officer on that date. It is not in dispute that on that day the workman appeared before the Inquiry Officer and admitted the charge No. 1 viz., that in spite of repeated instructions given to him he refused to comply with them and refused to wear uniform thus contravening conduct Regulation 31(d) and 32 of the F.C.I. (Staff) Regulations, 1971. At that time, he did not admit the other charges.

5. According to the employer-corporation, later on, on the same day, the workman gave a letter to the Inquiry Officer which stated :—

"With reference to today's proceedings of the inquiry, I agreed for the charges against me and I therefore request you, kindly to excuse me and further I request for apology."

According to the employer, on the same day he submitted his resignation to the Regional Manager, Food Corporation of India, Bombay, with a copy addressed to the District Manager, Food Corporation of India, Nagpur. However, before this letter admitting the other charges was given to the Inquiry Officer, the inquiry proceedings of that day i.e. of 29-11-1976 were closed and the next date for the inquiry was fixed on 13-12-1976.

6. According to the employer, as the workman had filed a letter admitting all the charges he did not appear before the Inquiry Officer on 13-12-1976. The Inquiry Officer, therefore, submitted her report on 14-12-1976 to the Regional Manager (Maharashtra), Food Corporation of India, informing him :

"Since the official has admitted all the charges and therefore there is no necessity for any further en-

quiries to be conducted into the charges framed against him. Moreover it is learnt that the official has also submitted his resignation to the office. Under the circumstances no further action appears to be taken by the Inquiry Officer. The enquiry is therefore treated as completed from my side."

7. After the said report was received from the Inquiry Officer, the Regional Manager (Maharashtra) issued a show-cause notice to the workman informing him that he had come to the conclusion that the workman was not a fit person to be retained in service and he proposed to impose on him the penalty of removal from service. The workman was called upon to show-cause against the proposed penalty.

8. The workman gave a reply to the show-cause notice on 12-2-1977 stating therein that he had accepted only the charge No. 1 and that some writing was obtained from him in which it was stated that he had accepted the other charges also. In this reply the workman denied that he had accepted the other charges. He, therefore, requested that he may be given a chance to defend him before the Inquiry Committee. The Regional Manager (Maharashtra) did not accept this representation and he proceeded to remove the workman from service from the date the order was served on him.

9. In the statement of claim the workman stated that he had admitted charge No. 1 in the morning at about 11 or 11.30 a.m. on 29-11-1976 before the Inquiry Officer. Thereafter, he was called by the Inquiry Officer in the afternoon for collecting the relieving order to enable him to collect his train fare, etc. The workman alleged that when he went before the Inquiry Officer in the afternoon she started offering inducements. His version in the statement of claim is as follows :—

"It may be stated here that though the workman is Gujarathi, he knows Sindhi. The Inquiry Officer was also a Sindhi lady and she induced the workman to admit charges framed against him by observing that he would only be warned in the matter and nothing would be done to him. She also made it clear to the workman that in case he does not accept the course suggested by her of admitting the charges framed against him, he would find himself in a very tight position. She also had promised and assured the workman that she shall see that he gets all the leave, dues etc. in case he accepts the charges. It is during the talk the workman had also informed the Inquiry Officer that on account of the behaviour of Shri Rathod, he does not want to work under him. It is in this background, the Inquiry Officer collected two documents from the workman on or about 29-11-76. Those documents do not represent the true state of affairs. Latter dated 29-11-76 wherein the alleged claim is made that all the charges are admitted by the workman, is not a voluntary admission on the part of the workman; nor it is an admission of the fact that he has committed any misconduct or that he is guilty on any account whatsoever."

It will thus be seen that the workman wanted to say that the Inquiry Officer had induced him to give some writing and collected two documents from him viz., the document admitting all the charges and the other document of resignation. The version of the management is that the letter of resignation was sent by the workman direct to the Regional Manager, Bombay.

10. A preliminary inquiry was therefore held as to whether the inquiry conducted against the workman was fair and proper. In that preliminary inquiry the employer examined the Inquiry Officer, Miss. I. M. Tahilani. She was cross-examined at length by Mr. Atrey, the learned counsel for the workman. The workman also examined himself. There is on record an application given by the workman to the Inquiry Officer on 29-11-1976 (exhibit XE-33). The text of the application is as follows :

"With reference to today's proceedings of the inquiry, I agreed for the charge, against me, and I, therefore,

request you kindly to excuse me and further I request for apology. Further it is requested to do the necessary in my favour on humanitarian ground as I am having a family and I did not receive the salary since Sept., 1975."

The workman admits that this letter bears his signature. There is another application dated 29-11-1976 (exhibit E-4) by the workman to the Regional Manager, Food Corporation of India, Bombay, whereby he submitted his resignation from the post of Driver grade II at Nagpur and requested the Regional Manager to accept the same at an early date. The workman admits that this application also bears his signature. In the preliminary inquiry held by me as regards the fairness of the departmental inquiry the version of the workman was that the Inquiry Officer had got the two above documents written from some clerk and that she had induced him to sign them. The version of the Inquiry Officer was that the workman handed over to her the letter at exhibit E-3 in the afternoon of 29-11-1976 in the earlier part of the day in which admittedly the workman admitted the charge No. 1. The Inquiry Officer stated in the preliminary inquiry held by me that when the workman handed over to her the letter at exhibit E-3 she asked him why he was admitting all the charges. The workman then told her that he had already submitted his resignation to the competent authority i.e. the Regional Manager, Bombay and therefore he was not interested in the job and he was therefore admitting all the charges. The version of the workman as regards the document of resignation i.e. exhibit E-4 was that the Inquiry Officer had prepared the document and had obtained his signature telling him that it was in respect of the sanction of his leave. The version of the workman in respect of the document at exhibit E-3 wherein he is said to have admitted all the charges is that he was told that it was in respect of the admission of the charge No. 1 only. In my order on the preliminary point dated 27-8-1982 I have disbelieved the version of the workman as regards these two documents. I have given my reasons in that order. I have held there that the workman wanted to resign on his own accord as he was not pulling on well with his immediate superior one Mr. Rathod, the District Manager, Nagpur. I have also held that the workman voluntarily admitted all the charges against him, probably to ensure that he was leniently dealt with in respect of the sanctioning the leave to his credit and other benefits, if any. Rejecting all the contentions raised on behalf of the workman I held in my order on the preliminary point dated 27-8-1982 that I did not find any substantial infirmity in the inquiry proceedings and that the workman had voluntarily admitted all the charges. One of the charges framed against the workman was that he was doing private business while remaining absent from duty and that he has been plying a three wheeler as taxi. It is therefore probable that he was not interested in his job under the present employer. I have therefore pointed out in my said order that this may be one of the reasons why he wanted to resign the job and to admit all the charges in the inquiry.

11. It is not in dispute that he admitted the charge No. 1. It is not in dispute that he signed the letter dated 29-11-1976 (exhibit E-3) in which he admitted all the other charges. I have rejected the contention of the workman that he had signed that letter not knowing the contents thereof on account of some inducement offered by the Industry Officer. The charge No. 1 is as follows:—

"That inspite of repeated instructions given. Shri D. C. Thakkar, Driver Grade II refused to comply with and obey lawful orders and refused to wear uniform thus contravened conduct Regulation 31 (d) and 32 of the F.C.I. (Staff) Regulations, 1971."

The other charges which are set out in paragraph 3 above show that the workman wilfully absented from duty for a substantial period. He misbehaved with the acting District Manager, Mr. N. G. Tongaonkar on the date mentioned in the charge and also with the Asstt Manager (Audit) camp Nagpur when he was instructed in writing some time in the month of August, 1975, to wear uniform. He purchased 20 litres of petrol on credit coupons when there was sufficient petrol in the tank of the jeep and thus misappropriated and

used petrol for non-official use. He was doing private business of plying a three wheeler as taxi thereby contravening the conduct Regulations 24(ii) and 45(i) of the F.C.I. (Staff) Regulations, 1971. The regulations of the employer-corporation which he contravened by committing the above acts have been set out in the charges.

12. The question for consideration is whether the punishment awarded to the workman is justified. Now, the punishment imposed upon the workman by the competent authority, Regional Manager, (Maharashtra) is one of removal from service. Mr. Ghate, the learned counsel for the employer, submitted that the charges admitted by the workman merited the punishment of dismissal. However, on compassionate ground the punishment awarded against him is only one of removal from service. I am inclined to hold that no interference is called for in the punishment awarded to the workman.

13. Mr. Atray, the learned counsel for the workman, submitted that as the workman had tendered his resignation, further departmental proceedings should have been dropped. He also submitted that the punishment at any rate is highly disproportionate to the charges held proved against the workman. His arguments further was that the competent authority who awarded the punishment was not examined on behalf of the employer and did not offer himself for cross-examination. I do not find any substance in any of the submissions. Admittedly the workman admitted the charges No. 1. That charge, in my opinion, is sufficient to merit the punishment awarded to the workman.

14. I therefore find that the action of the management of the Food Corporation of India (Maharashtra Region), Bombay, in removing the workman, D. C. Thakkar, from service with effect from 23-3-1977 is justified, and, therefore, the workman is not entitled to any relief.

15. My award accordingly. No order as to costs.

M. D. KAMBLI, Presiding Officer.  
[No. L-42012(7)/78-D II(B)]

S. S. PRASHER, Desk Officer.

New Delhi, the 24th November, 1982

**S.O. 4020.**—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Bombay, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Punjab National Bank, Bombay, and their workman, which was received by the Central Government.

**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY**

Reference No. CGIT-2/2 of 1982

**PARTIES:**

Employers in relation to the management of Punjab National Bank

**AND**

Their Workmen.

**APPEARANCES:**

For the Employers—Shri Gurbachan Singh, Manager (Staff)

For the workmen—Shri K. N. Mehrotra, Vice-President, A.I.P.N.B. Employees Association, 2, Shri G. L. Kadam, General Secretary, P.N.B. Staff Union.

**INDUSTRY:** Banking.

**STATE:** Maharashtra.

Bombay, the 19th October, 1982

**AWARD**

By their order No. L-12012/8/81-D.II(A), dated 6-1-1982 the Central Government have referred the following dispute for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947:—

"Whether the action of the management of Punjab National Bank, Bombay in refusing to grant extra

allowance to Shri G. L. Kadam, Clerk, is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?"

2. On the allegation that the clerk-cum-typist Shri G. L. Kadam besides his routine duties was performing other extra duties like Care-taker officer looking after the property of the Bank both moveable and immovable and also performing some additional duties, the Union who is espousing the cause of the workman namely Punjab National Bank Staff Union has made a demand for special allowance as payable to Special Assistant from 18-8-1965 till June 1973 and in the statement of claim, although the order of reference does not speak to this effect, a further demand that from July, 1973, the clerk-cum-typist should be promoted in the grade of an officer grade 'C' or in the alternative as a Special Assistant.

3. The claim is refuted by the Respondent Bank on whose behalf written statement is filed at Ex. 2/M and rejoinder at Ex. 16/M, denying the allegation that the clerk-cum-typist was performing any extra duties involving greater skill and responsibilities, and therefore according to the Bank the employee concerned is not entitled to any extra allowance as claimed neither under any award nor under the Bipartite Settlements and as such the claim is not entertainable.

4. On the strength of these pleadings the following issues arise for determination and my findings thereto are:—



#### ISSUES

#### FINDINGS

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 1. Whether the Union proves that Shri G.L.Kadam was performing special duties as contended?   | Doing extra duties,                  |
| 2. If yes, was he entitled to special allowance as claimed?   | Extra allowance of Rs.50/-per month. |
| 3. Whether in the light of the order of reference the question regarding the wrongful designation as tried to be pleaded by the Union in the statement of claim can be gone into? | No                                   |
| 4. What award   | As per award                         |

#### REASONS

5. In support of the contention that Shri Kadam was performing some extra duties besides his normal duties namely the routine duties there is the evidence of the clerk concerned Ex. WW whereby stating that he was performing some extra duties namely attending to the complaints of the tenants occupying the Bank's quarters, attending the Corporation office to obtain permission for carrying out additions and alterations of the property of the Bank, examining the work of repairs carried out in the building and also the repairs to furniture and fixtures and to see whether the repairs were carried out according to the specification and to report to the superior officer and to attend the property cases pending in the courts, attending the office of the Bombay Telephone for obtaining additional lines, attending various garages for obtaining quotations for carrying out repairs to vehicles of the Bank, attending the office of the R.T.O. for getting the vehicles passed and to pay taxes. He used to purchase cloth from the market for preparing the uniform for the staff in the region and verify the petrol bills of the cash-Vans, looking after the work of contractors undertaking repairs to Typewriters, Water-coolers, Air conditioners etc. and to see the same is done according to the specification, to arrange disposal and auction of unserviceable goods, attending the office of the Controller of accommodation for obtaining N.O.C. and booking Railway and plane tickets for the executives, obtaining quotations for purchase of stationery and to visit the shops and make recommendations to the Manager and also to be in charge of the furniture and fixtures lying in the residential houses of executives on transfer.

6. Though in the cross-examination the actual nature of duties was tried to be challenged, the fact that all duties were performed by the employee is also stated by another two witnesses serving in the same Bank S/shri B. L. Desai and S. V. Pikelay and further there is an important piece of evidence in the shape of report by the Manager under whom Shri Kadam was then serving recommending the grant of Rs. 50 P.M. as special allowance. Shri B. L. Desai who is serving as a Special Assistant says that from June, 1981 he is serving in Property Section of the Bank and that before him Shri Kadam was performing the duties in the said Section and there is further admission that his duties were wider than the duties performed by the Special Assistant. But Special Assistant performing certain duties would not make them duties of a Special Assistant for which purpose we shall have to refer to the Award and Settlements especially Chapter V and Appendix B of Bipartite Settlement of 1966. Another witness Shri S. V. Pikelay refers to the attendance of Shri Kadam in the Municipal Corporation office in connection with Bank work, but this evidence is not of much help to the Union.

7. It is evident that the claim of Shri Kadam or the Union on his behalf cannot be for special allowance as admissible and defined under Chapter V of the Bipartite Settlement dated 19-10-1966, for such special allowance an employee must be appointed as a Special Assistant and performing such duties for which certain modalities have been prescribed in the earlier awards. Consequently unless and until Shri Kadam was entitled to become a Special Assistant or performing duties as laid down he could not have claimed special allowance payable to the Special Assistant.

8. This however does not mean that if there is proof of his performing extra duties, duties not routine, of a clerk-cum-typist and further the duties for which he was required to work during odd hours and not restricted to the office hours, then the claim of the workman shall not stand justified, especially when the record speaks that for such type of duties outsiders were demanding Rs. 800 per month, and that too for attending the work for one or two hours a day.

9. Apart from the oral evidence, there are the various reports of the Manager under whom Shri Kadam was then serving. At Ex. 20/M there is a Memorandum dated 25-7-73 written by the Manager, P.N.B. House, to the Senior Regional Manager recommending the sanction of an allowance to the tune of Rs. 50 per month since Shri Kadam according to him was well trained in attending to such type of work referred in the letter. The Asstt. Regional Manager however as can be seen from Ex. 21/M turned down the said recommendations, even then the Manager by another Memorandum dated 26-11-1973 Ex. 22/M made the same recommendation saying that it was not possible to requisition a sub-overseer and it would be economical to pay the same amount to Shri Kadam was posted as Clerk-cum-typist and in that capacity another letter Ex. 25/M dated 19-8-1974 from the same Manager to the Regional Manager followed by another letter Ex. 26/M dated 30-9-1974 and Ex. 27/M dated 7-10-1974. When all these letters are reach together, the only conclusion possible is that besides his normal duties Shri Kadam was performing some extra duties to the knowledge of the Manager under whom he was placed and said authority was also satisfied about the legitimacy of the employee's claim. We know that Shri Kadam was posted as Clerk-cum-typist and in that capacity he could not have been expected to attend the Municipal Corporation office to obtain permission for carrying on additions and alteration of the property of the Bank, to examine the work of repairs carried out in the buildings and repairs to furniture and fixtures in order to verify whether work was carried out according to the specification and to attend various offices in connection with the Bank's work and he was not adhering to the office hours and even the manager in his letter says that he was required to work at odd hours. Considering therefore the proof rendered by the Manager's correspondence although the superior authorities were not convinced of the legitimacy of the claim, having regard to the totality of the evidence and having regard to the fact that a sub-overseer would have been required to be appointed for performing the same duties and that subsequently the Bank appointed as Special Assistant agreeing to pay him Rs. 283 as special allowance for doing the same type of duties done by Shri Kadam I am convinced that he was performing extra duties as contended and that his claim for extra allowance can be said to be just and legitimate.



10. From the representation of Shri Kadam which is referred in the Manager's letter dated 25-7-1973, Ex. 20/M it seems that for the first time the incumbent started claiming extra emoluments from July, 1973 though he was on that job since 1965 and if the incumbent himself realised about the extra duties in the year 1973 and then started moving in the matter, despite the proof that he was doing the same type of work earlier in point to the time he claim will have to be restricted to the period from July, 1973 and not before.

11. Once it is appreciated that what is claimed is not special allowance which cannot be claimed by Shri Kadam as he could never be appointed as special Assistant till 16-8-81, the quantum of Special allowance can never be Rs. 283 which is the special allowance prescribed under the Bipartite Settlement. The Union has got produced various correspondence and since the Manager who was the best person under whom Shri Kadam was working has recommended to grant Rs. 50 as allowance, it carries great weight. What was the representation of Shri Kadam is not on record but the fact that the correspondence was got produced shows that the Union also must be agreeing with his recommendations. Considering therefore that it is not special allowance but at the same time considering that Shri Kadam was performing extra duties other than the normal routine duties, that too during odd hours which fact the Bank has admitted, I am convinced that he is entitled to extra allowance of Rs. 50 from July, 1973 to the end of July, 1981.

12. There is a prayer that either Shri Kadam should be granted the special allowance as Special Assistant or he should be promoted as Officer in grade 'C' but in the light of the order of reference, the prayer can never be considered as the prayer falls outside the scope of reference. I may add here that for promotion as officer there are certain formalities prescribed, similarly for the posting as Special Assistant there are certain modalities. So far as the promotion to the Officer's cadre, not only there is seniority but also it depends upon how Shri Kadam is suitable to the post which can be judged by the superior officers of the Bank appointed for the same purpose. While deciding the present reference I can not consider the claim for promotion or for his posting as Special Assistant, as such request to this effect cannot be considered at all. The only conclusion is that Shri Kadam is granted extra allowance of Rs. 50 per month for the period as stated earlier. The Bank is to calculate the extra allowance and accordingly to pay the same to the concerned employee within one month from the date of this Award. No order as to costs.

M. A. DESHPANDE, Presiding Officer  
[No. L-12012(8)/81-D.II(A)]  
Central Govt. Industrial Tribunal  
N. K. VERMA, Desk Officer.

New Delhi, the 24th November, 1982

**S.O. 4021.**—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of New India Assurance Company Limited, Calcutta, and their workmen, which was received by the Central Government on the 11th November, 1982.

#### CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, CALCUTTA

Reference No. 60 of 1980

#### PARTIES:

Employers in relation to the management of New India Assurance Company Limited, Calcutta

AND

Their Workmen.

#### PRESENT:-

Mr. Justice M. P. Singh, Presiding Officer.

#### APPEARANCES:

On behalf of Employers—Mr. T. N. Mukherjee, Labour Adviser for the management.

On behalf of Workmen—Mr. Anil Das Choudhury, Advocate.

STATE : West Bengal.

INDUSTRY : Insurance.

#### AWARD

By its Order No. L-17011/5/79-D.IV(A) dated 15th July, 1980 the Government of India, Ministry of Labour, referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:

"Whether the action of the management of New India Assurance Co. Ltd., Calcutta in denying officiating position and officiating allowance to Shri N. C. Tarafdar, Assistant at Area Office Accounts and Shri M. Dhara, Assistant at Division No. 3, with effect from 7th July, 1976 is justified? If not, to what relief are the concerned workmen entitled?"

2. The two questions to be determined in the present case are, (i) whether the two assistants aforesaid officiated in the post of Senior Assistant and (ii) whether they are entitled to officiating allowance from the management for the same with effect from 7th July, 1976. In my opinion the answer should be in the affirmative.

3. WW-1 Nemai Chandra Tarafdar, the Assistant (No. 4643) of the Area office Accounts is one of those two. His evidence is that he acted in officiating capacity on the post of Senior Assistant K. P. Nair from March, 1976 to March, 1979 when K. P. Nair Senior Assistant was promoted as acting Superintendent, under verbal order of the Assistant Manager R. Krishnan. His further evidence is that that was a higher post and that all the relevant documents concerning his officiating position were lying with the management; that he while acting in the post of Senior Assistant performed the duties mentioned in the letter Ext. W-1 dated 29th March, 1978. Those duties are also mentioned in para (8) of the written statement and run as follows:—

- (i) G.I.C. Premium Statistics (Eastern Region).
- (ii) Area performance Gross Direct premium Income.
- (iii) Monthly premium in respect of number of claims paid and outstanding summary (Eastern Region).
- (iv) Number of documents Summary.
- (v) Codewise analysis of Misc. Disbursement book.
- (vi) Various."

He has further said that M. Dhara, another Assistant also officiating in the higher post of Senior Assistant and he too performed underwriting work in connection with the Inspector Code. The witness has also deposed that Barin Ghosh and Pradeep Kumar Dutta got officiating allowance for having done the work of Mr. Taimol in the Marine Claim Department, that they also had worked under the verbal order and similarly one Chakraborty (Samar Chakraborty as per written statement) and N. Chanda got officiating allowance. These two had worked with Mr. M. Dhar and they also had worked under the verbal order. In the cross-examination WW-1 says that there is clear division between the work of the Assistant and the work of Senior Assistant, that the work of underwriting is done both by Assistant and Senior Assistant. He explained it by saying that an Assistant does it without correspondence. He has further deposed that in the branch and Divisional office either Assistant or Senior Assistant does the work of statistics but in the Area office or



in Controlling office the it is done only by Senior Assistant. It is needless of say that WW-1 is in the Area office. I see no reason to disbelieve him.

4. The managements own letters to the various Assistants go to show that the fact of officiating was not challenged. Ext. M-1 is letter dated 27th June, 1978 written by the management to Samarendra Chakraborty, another letter Ext. M-2 dated 5th December, 1979 written to Subir Chakraborty (with whom N. Dhar and N. Chand had worked) and Ext. W-2 the letter written to WW-1, namely, Mr. Tarafdar indicates that the fact of officiating was not in dispute. All these persons had claimed officiating allowance. The claim was considered and rejected on the ground that officiating allowance was not admissible as per provisions of General Insurance Scheme, 1974 for Class III and IV employees read with Administrative instructions from GIC. The ground is vague. The claim was rejected on a vague technical ground and not on the ground that they did not officiate.

5. The argument of the management before this Tribunal has not examined R. Krishnan, the Assistant Manager under not at all correct. It is to be noted that the management has not examined R. Krishnan, the Assistant Manager under whose verbal order WW-1 claim to have acted in officiating capacity. It is also to be noted that in the written statement the management raised only preliminary issue and did not deny the fact officiation. In the written statement which is on record only preliminary objection has been stated. No statement about the fact of officiating has been made. The reference is of the year 1980. Even within this period of two years and more no other written statement on merit has been filed. There is thus no denial of the fact of officiation. So far as the preliminary objection is concerned it is frivolous and at the very commencement of the hearing of the case I pointed it out and then evidence was taken on merit. The witness of the union was cross-examined by the management and the case has been heard on merit only. From the various letters aforesaid indicating that the fact of officiating was not in dispute, from the absence of denial in the written statement of the management and from the evidence of WW-1 N. C. Tarafdar I come to the conclusion that the two Assistants officiated in the post of Senior Assistant. There can be no doubt that the two posts are different with difference scales of pay. The post of Senior Assistant carries a scale of Rs. 230-735 and the post of Assistant has the scale of Rs. 175-585. The contention of the management that there is no distinction between the two posts is naturally wrong.

6. The next question is whether the two Assistants are entitled to officiating allowance. There can be no doubt that they are entitled. Clause 15 of the General Insurance (Nationalisation) and Revision of Pay Scales and other conditions of service of Supervisory Clerical and Subordinate Staff Scheme, 1974 runs as follows :

"15. Officiating Allowance—An employee may be required to hold officiating charge of a post in a higher category or additional charge of an equivalent post whenever considered necessary and where such officiating charge or additional charge is held for a continuous period of 15 days or more, the employee shall be paid a pro-rata allowance as follows, namely :—

(i) Officiating in a higher category of post : 20 per cent of his basic salary, subject to a maximum of Rs. 1000/- per month;

(ii) Additional charge of an equivalent post : 10 per cent of his basic salary, subject to a maximum amount of Rs. 50/- per month."

On a perusal of the above it is obvious that the two Assistants concerned in the present case are entitled to officiating allowance. The management argued that there was doubt and difficulty in the interpretation of this clause and so in 1001 GI/82—4

paragraph 21 of the 1974 Scheme it is the Central Government which can decide the dispute and not this Tribunal. The point has no force. I do not see any doubt or difficulty in interpreting the provisions of Clause 15. The words of this clause are plain and unambiguous. It clearly confers right on an employee to get officiating allowance on pro-rata basis as mentioned therein. The contention is, therefore, rejected.

7. In the result my award is that the action of the management in denying officiating position and officiating allowance to Sri N. C. Tarafdar Assistant at Area office Accounts and Sri M. Dhar, Assistant at Division No. III with effect from 7th July 1976 is unjustified. Both these Assistants are held to have officiated in the post of Senior Assistant as claimed by them and both are entitled to officiating allowance admissible in Clause 15 of General Insurance (Nationalisation and Revision of Pay Scales and other conditions of service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Scheme, 1974.

[No. L-17011(5)/79-D.IV(A)]  
M. P. SINGH, Presiding Officer

Dated, Calcutta the  
7th October, 1982

New Delhi, the 25th November, 1982

S.O. 4022.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Bombay in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Life Insurance Corporation of India, Nasik Division and their workmen, which was received by the Central Government on the 9th November, 1982.

## BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

### PARTIES :

Employers in relation to the Management of Life Insurance Corporation of India Nasik Division.

AND

Their Workmen

### APPEARANCES :

For the Employers—Shri P. R. Pal, Advocate.

For the workmen—Shri V. D. Kathuria, Jt. Secretary, All India Life Insurance Corporation Employees Federation.

STATE : Maharashtra

INDUSTRY : Insurance

Bombay, dated the 18th October, 1982

### AWARD

By their order No. L-17011/4/78-D.IV(A) dated 15-4-1980 the following disputes pertaining to Nagpur Division has been referred for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act and subsequently by order No. L-17025/4/80-D.IV(A) dated 31-3-1981 the Nasik Division of the Life Insurance Corporation of India was added :

‘Whether the demand of the existing empanelled badli workmen in Nagpur and Nasik Divisions of the Life Insurance Corporation of India for their absorption as regular employees is justified? If so, to what relief and from which date are the concerned workmen entitled?’

2. The Parties including Vima Karamchari Sanghatana Nasik have filed their pleadings and the written statement of Sanghatana assumes importance that being the only Union which is contesting the whole claim.

3. Now though as reference stands speaks of the existing empanelled badli workmen, the Union in paragraph 17 of Ex. 13/W states that there is no panel of Badli workmen at Nasik. Because of this assertion the contention raised on behalf of the Life Insurance Corporation of India is that when there was no panel, while the reference speaks of existing empanelled badli workmen, and if it is the order of reference which gives and confers jurisdiction to entertain the dispute, the present reference would not be sustainable in the absence of any panel. There is great force in this contention and when the order of reference is specific I cannot read in between the line or something different than what it speaks and the only course open to the Tribunal is to dispose of the reference on the ground that it is not sustainable. This order is not being passed on merits nor the real dispute is being decided and therefore if the parties especially the workmen are in a position to raise a dispute, the disposal of the present reference on the issue in question should not create any bar in their path.

4. I was given to understand that with regard to similarly placed badli workmen at Nagpur, the Life Insurance Corporation of India entered into a settlement with the Union representing the case of those workmen whereby certain rights have been conferred and they have been absorbed in service, in terms of which settlement I am told there is an award passed by the Tribunal. When therefore the Life Insurance Corporation has entered into a settlement with regard to similarly placed employees at Nagpur, apart from the technical defect as noted, when the case of the employees at Nasik is on par with their counterpart at Nagpur, the Corporation should consider whether those very benefits which it has decided to extend to the Badli workmen at Nagpur should not be conferred on the workmen similarly placed at Nasik, since their contentions are of similar nature and they are alleged to have put in certain years of service in the Corporation. After all the Corporation has to give lead to other employers so that no cause for any just grievance remains.

No order as to costs.

Dt : 2-11-82.

M. A. DESHPANDE, Presiding Officer

[No. L-17025/4/80/DIV(A)]

T. B. SITARAMAN, Desk Officer.

New Delhi, the 25th November, 1982

**S.O. 4023.**—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 3, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Kenda Area of Messrs Eastern Coalfields Limited, Post

Office Bahula, District Burdwan, and their workmen, which was received by the Central Government on the 18th November, 1982.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL—CUM—LABOUR COURT NO. 3, DHANBAD

Reference No. 52/82

PRESENT :

Shri J. N. Singh.

Presiding Officer.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Kenda Area of M/s. Eastern Coalfields Ltd., P.O. Bahula, Dist. Burdwan.

AND

Their workmen

APPEARANCES :

For the Employers—Shri N. Das, Advocate.

For the Workmen—None.

INDUSTRY : Coal.

STATE : West Bengal

Dated, the 9th November, 1982

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them U/S 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 14 of 1947 has referred the dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. 19012 (23)/82-D. IV (B) dated the 28th May, 1982.

SCHEDULE

‘Whether the action of the General Manager, Kenda Area of M/s. Eastern Coalfields Ltd., P.O. Bahula, Dist. Burdwan in not properly designating and placing Shri Sushil Kumar Pathak and Paresch Chandra Mandal as Store Keepers in Clerical Grade-I, is justified? If not, to what relief are the workmen concerned entitled?’

2. After receipt of the Reference notices were issued to both the parties for submission of their written statement. The management filed their written statement on 10-8-82 but the union was absent in spite of notice. The case was adjourned to 1-9-82 and on that date also the union absented themselves. A fresh notice was issued to the union directing them to file written statement by 24-9-82 failing which the case will proceed ex parte. On 24-9-82 also the union did not appear in spite of service of notice and again a fresh notice was issued fixing 22-10-82 for hearing but again the union did not appear nor filed any written statement.

3. Thus it is clear that the union is not taking any interest in the case and they have no dispute with the management.

4. In such circumstances a ‘no dispute’ award is passed.

J.N. SINGH, Presiding Officer

[No. L-19012/(23)/82-D.IV(B)]

**S.O. 4024.**—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 3, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Nimcha Colliery of Messrs Eastern Coalfields Limited, Post Office Jaykaynagar, District Burdwan, and their workmen which was received by the Central Government on the 18th November 1982

**BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NO. 3, DHANBAD**

Reference No. 4/81

**PRESENT :**

Shri J. N. Singh, Presiding Officer.

**PARTIES :**

Employers in relation to the management of Nimcha Colliery of Eastern Coalfields Ltd., P.O. Jaykaynagar, Dist. Burdwan

**AND**

Their workman.

**APPEARANCES :**

For the Employers—Shri N. Das, Advocate

For the Workman—None.

**INDUSTRY :** Coal.

**STATE :** West Bengal.

Dated, the 10th November, 1982

**AWARD**

The Govt. of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them U/S 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 14 of 1947 has referred the dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-19012(35)/80-D.IV(B) dated the 31st January, 1981.

**SCHEDULE**

“Whether the management of Nimcha Colliery of M/s. Eastern Coalfields Ltd., P.O. Jaykaynagar (Burdwan) was justified in not regularising Shri Kamta Prasad Gupta as Canteen Manager/Canteen Supervisor in Clerical Grade II with effect from 1-12-1977? If not, to what relief the workman is entitled to?”

2. On 9-11-82 both the parties have filed a joint petition of compromise duly signed on their behalf and they pray that an award be passed in terms of the settlement.

3. I have gone through the settlement which is beneficial for the workman.

4. In the circumstances the award is passed in terms of the settlement which shall form part of the award.

( N. SINGH, Presiding Officer  
[No. L-19012(35)/80-D.IV(B)]

Enc : Settlement.

**BEFORE THE HONOURABLE PRESIDING OFFICER,  
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL  
NO. 3, DHANBAD**

Ref. No. 4 of 1981

**PARTIES :**

Employers in relation to the Management of Nimcha Colliery, ECL, P.O. Jaykaynagar, Dist. Burdwan

**AND**

Their workman

The Parties most humbly pray as under :—

That the above mentioned reference case has been fixed for hearing on 9-11-82.

That, the parties have discussed the matter and have come to an amicable settlement in favour of disposal of the case on the following terms and conditions,

- (a) the incumbent namely Sri Kamta Prasad and Gupta will be designated as Canteen Manager and will be placed in Clerical Grade-II in the pay scale of Rs. 508-23-692-29-808/- under the Wage Board for the Coal Mining Industry/NCWA-II with effect from 1-4-1982.
- (b) Sri Gupta will continue to be posted at Nimcha Colliery until further orders.
- (c) It has been also considered and agreed by the parties that Sri Gupta would be given 3 increments in the aforesaid Clerical Gr. II on fixation/fitment of his basic salary in Gr. II. The union or the workman shall have no claim for any other payments on any account relating to the dispute under disposal.
- (d) the instant settlement shall have no precedence. Under the aforesaid circumstances, the parties jointly pray for accepting the said terms of settlement by the Hon'ble Tribunal and to pass an Award accordingly for disposal of the case under the Reference No. 4 of 1981.

J. N. SINGH, Presiding Officer

For the Union representing  
the workman,

Sd/-  
(Shiv Kant Pandey),  
Secretary,  
Koyala Mazdoor Congress.  
Satgram Area,  
Dt. 8-11-82.

For the Employers,

Sd/-  
(D.R.K. Rao),  
Personnel Manager,  
Satgram Area, ECL.

Filed by

Sd/-  
P. L. OJHA,

9-11-82

S. R.P.O. Satgram Area.

**S.O. 4025.**—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 3, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Ningha Colliery of Messrs Eastern Coalfields Limited, Post Office Kalipahari, District Burdwan, and their workmen which was received by the Central Government on the 18th December, 1982.

**BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO. 3, DHANBAD**

Reference No. 57/80

**PRESENT :**

Shri J. N. Singh, Presiding Officer.

**PARTIES :**

Employers in relation to the management of Ningha Colliery, Eastern Coalfields Ltd., P.O. Kalipahari (Burdwan)

AND

Their workman.

**APPEARANCES :**

For the Employers—Shri B. N. Lala, Advocate.

For the Workman—None.

**INDUSTRY :** Coal **STATE :** West Bengal

Dated, the 10th November, 1982

**AWARD**

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them U/S 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 14 of 1947 has referred the dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-19012(63)/79-D.IV(B) dated the 23rd September, 1980.

**SCHEDULE**

"Whether the action of the management of Ningha Colliery, Eastern Coalfields Ltd., P.O. Kalipahari, (Burdwan) in not changing the designation of Shri Rameshwar Yadav as Labour Supervisor and in not placing him in proper grade with effect from 1st September 1974 was justified? If not, to what relief is the concerned workman entitled?"

2. On 8-11-82 both the parties have filed joint petition of compromise duly signed on their behalf and they pray that an award be passed in their terms of the settlement.

3. I have gone through the settlement which is beneficial for the workman.

4. In the circumstances the award is passed in terms of the settlement which shall form part of the award.

Sd/-  
J. N. SINGH, Presiding Officer

**BEFORE THE HON'BLE PRESIDING OFFICER,  
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-  
CUM-LABOUR COURT NO. 3, DHANBAD**

Ref. No. 57 of 1980

**PARTIES :**

Employers in relation to the Management of Ningha Colliery of Eastern Coalfields Limited

AND

Their workman.

Joint petition of compromise :—

Both the parties, herein concerned, most respectfully submit and state as follows :—

(1) That the above matter is pending adjudication before the Hon'ble Tribunal.

(2) That, in the meantime, both the parties mutually negotiated the instant dispute and have settled the dispute on the following terms :

(a) That the employers agree to post Sri Rameshwar Yadav, the workman, herein concerned in the post of Clerk in Clerical Gr. II of the National Coal Wage Board Recommendation NCWA-I and II within a week from the date of Honble Tribunal accepts this settlement.

(b) That the workmen agree that they shall have no claim whatsoever for any back wages in any matter arising out of the present dispute.

(c) That the settlement fully resolves the instant dispute.

(d) That the parties shall bear their own costs of the proceedings.

(3) Both the parties pray that the Honble Tribunal may be pleased to accept this settlement as fair and reasonable and may be pleased to pass an award in terms of the settlement.

And for this act of kindness the parties as in duty bound shall ever pray.

Dated this the 6th day of November, 1982

Sd/-

For and on behalf of the workman. For and on behalf of the General Secretary.

Sd/-

Management.

[No. L-19012(63)/79-D.IV(B)]  
S. S. MEHTA, Desk Officer



## आवेष्ट

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 1982

का०आ० 4026—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपायद्वय अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में सेन्ट्रल बैंक प्राक इंडिया, जयपुर के प्रबंधन से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उप-धारा (i) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री रामराज लाल गुप्त होंगे, जिनका मुख्यालय जयपुर में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

## अनुसूची

क्या सेन्ट्रल बैंक प्राक इंडिया, जयपुर के प्रबंधन की श्री एस० एस० शर्मा, उप-लेखापाल तथा एक संरक्षित कर्मकार की तारीख 19-10-66 के द्विपक्षीय समझौते के उपबंधों के अनुसार झूठी छुट्टी तथा यात्रा भत्ता/वैनिक भत्ता न देने की कार्यवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार है ?

[सं० एल-12012/269/81-डी. II. ए.]

## ORDER

New Delhi, the 3rd August, 1982

S.O. 4026.—Whereas the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Central Bank of India Jaipur and their workman in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitute an Industrial Tribunal of which Shri Ramraj Lal Gupta shall be the Presiding Officer, with headquarters at Jaipur and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

## SCHEDULE

"Whether the action of the management of Central Bank of India, Jaipur in denying duty leave and payment of T.A./D.A. as per the provisions of Bipartite Settlement dated 19-10-66 to Shri S. S. Sharma, Sub-Accountant, and a protected workman is justified ? if not, to what relief is the workman concerned entitled ?".

[No. L-12012/269/81-D. II(A)]

## आवेष्ट

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 1982

का०आ० 4027—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपायद्वय अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में कर्नाटक बैंक लि०, हुबली के प्रबंधन से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उप-धारा (i) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री बी० एच० उपाध्याय होंगे, जिनका मुख्यालय बंगलूर में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

## अनुसूची

क्या कर्नाटक बैंक लि०, हुबली के प्रबंधन को हवारी शाखा के धन-निक्षेप प्रचारक श्री एस. सी. बेल्लारी को वेतन मासिक कमीशन को रोकने उसको दिए गए संग्रहण कार्डों को मांगने तथा प्रबंधन के आदेश सं० 5306/81 तारीख 23-9-81 द्वारा 1-9-81 के भूतलकी प्रभाव से उसकी सेवाओं को समाप्त करने की कार्यवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल-12011/75/81-डी. 2ए.]

## ORDER

New Delhi, dated the 10th August, 1982

S.O. 4027.—Whereas the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Karnataka Bank Ltd., Havari and their workman in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri V. H. Upadhaya shall be the Presiding Officer, with headquarters at Bangalore and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

## SCHEDULE

"Whether the action of the management of Karnataka Bank Ltd, Hubli in withholding the monthly commission payable to Shri S. C. Bellary, Money Deposit Canvasser, Havari Branch in demanding collection cards given to him and in terminating his services with retrospective effect from 1-9-81 by order No. 5306/81 dated 23-9-81 of the manager is justified ? If not, to what relief is the workman entitled ?".

[No. L-12011/75/81-D.II(A)]

## आवेष्ट

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 1982

का०आ० 4028—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपायद्वय अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में स्टेट बैंक प्राक सौराष्ट्र के प्रबंधन से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री जी. एस. बरोत होंगे, जिनका मुख्यालय अहमदाबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

## अनुसूची

“क्या स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के प्रबंधन के श्री विजु भाई रायभाई चेखलिया, गोवाम चौकीदार, जवाहर चौक शाखा सुरेन्द्र नगर, की सेवा 1-8-79 से समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुसूची का हकदार है ?”

[सं० एल-12012/348/81-डी. 2(ए)]

## ORDER

New Delhi, the 21st August, 1982

**S.O. 4028.**—Whereas the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of State Bank of Saurashtra, Surendranagar and their workman in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri G. S. Barot shall be the Presiding Officer, with headquarters at Ahmedabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

## SCHEDULE

“Whether the action of the management of State Bank of Saurashtra in terminating the service of Shri Viju-bhai Rayabhai Chekhalia, Godown Chowkidar Jawahar Chowk Branch, Surendranagar with effect from 1-8-79 is justified ? If not, to what relief is the workman concerned entitled ?”

[No. L-12012/348/81-D. II(A)]

## आदेश

नई दिल्ली, 23 अगस्त 1982

का० आ० 4029.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में बैंक ऑफ बड़ोदा, अहमदाबाद के प्रबंधन से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना बांछनीय समझती है ,

अतः केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठामीन अधिकारी श्री जी० एस० बरोत होंगे, जिनका मुख्यालय अहमदाबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

## अनुसूची

“क्या बैंक ऑफ बड़ोदा के क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद के प्रबंधन की श्री एन० वी० दिगे, सब-स्टाफ की 31-5-1981 से सेवाओं की विछोड़ करने तथा समाप्त करने की कार्यवाही उचित और न्यायसंगत है ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुसूची का हकदार है ?”

[सं० 12012/397/81-डी० 2(ए)]

## ORDER

New Delhi, the 23rd August, 1982

**S.O. 4029.**—Whereas the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Bank of Baroda, Ahmedabad and their workman in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri G. S. Barot shall be the Presiding Officer with headquarters at Ahmedabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

## SCHEDULE

“Whether the action of the management of Bank of Baroda Region Office, Ahmedabad in terminating and or discontinuing the services of Shri N. V. Dige, sub-staff with effect from 31-5-80 is legal, proper and justified ? If not, to what relief is the said workman entitled ?”

[No. 12012/397/81-D. II(A)]

## आदेश

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 1982

का० आ० 4030.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में जयपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक के प्रबंधन से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना बांछनीय समझती है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठामीन अधिकारी श्री रामराज लाल गुप्ता होंगे, जिनका मुख्यालय जयपुर में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

## अनुसूची

“क्या जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक, जयपुर के प्रबंधन की अपने कर्मचारियों की भविष्य निधि अंशदान की कटौती 1-11-1978 से 8.33 प्रतिशत के स्थान पर 6.25 प्रतिशत करना न्यायोचित है ? यदि नहीं तो संबंधित कर्मकार किस अनुसूची का हकदार है ?”

[सं० एल-12011/65/81-डी० 2(ए)]

एन० के० वर्मा, डेस्क अधिकारी

## ORDER

New Delhi, the 25th August, 1982

**S.O. 4030.**—Whereas the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Jaipur Aanchalik Gramin Bank and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri Ram Raj Lal Gupta shall be the Presiding Officer, with headquarters at Jaipur and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

## SCHEDULE

“Whether the action of the management of Jaipur Nagaur Aanchalik Gramin Bank, Jaipur in deducting Provident Fund Contribution of its employees @ 6.25 per cent of their basic Pay instead of @ 8.33 per cent with effect from 1-11-1978 is justified ? If not, to what relief are the workmen concerned entitled ?”

[No. L-12011/65/81-D. II (A)]

N. K. VERMA, Desk Officer

नई दिल्ली 8 नवम्बर, 1982

क्र० अ० 4031—मैसर्स जुपिटर रेडियो (रजि०) सी-46, ओखला, इण्डियन एरिया, फेज II, नई दिल्ली-20 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी गुप्तक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी विशेष महबूद बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन में छूट देती है।

#### अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त नई दिल्ली को ऐसी विवरणियाँ भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएँ प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निदिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निदिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रणालन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तर्गण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहुत नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमावित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुबाव, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बावत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को भुगत करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों को लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक भारिम/नामनिर्देशित को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त नई दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना वृष्टिकोण स्पष्ट करने का व्यक्तिगत अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी की व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिकर की दशा में उन मूल सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक बारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन जाने वाले किसी सदस्य को मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक बारिसों की बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/230/82-एफ-2]

New Delhi, the 8th November, 1982

S.O. 4031.—Whereas Messrs Jupiter Radios (Regd.) C-46, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-20 (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

#### SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of



accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employers.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium etc. the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014 (230)/82-PF. III]

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 1982

कां०आ० 4032—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कैमिकल इन्स्ट्रुमेंट्स कारपोरेशन, 573, ब्लाक-एन०, न्यू प्रसीपुर, कलकत्ता-53 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35017/101/82-पी०-एफ०-II]

New Delhi, the 9th November, 1982

S.O. 4032.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Chemical Distributors Corporation, 573, Block-N, New Alipore, Calcutta-53, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35017/101/82-PF. III]

कां०आ० 4033—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स आर्ट ट्रेन्ड एक्सपोर्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड, 12, बर्गा रोड, कलकत्ता-17 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35017/96/82-पी०-एफ०-II]

S.O. 4033.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Art-Trend Exports (Private) Limited, 12, Darge Road, Calcutta-17, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No.S-35017/96/82-PF.II]

कां०आ० 4034—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स जालान प्रोडक्शन्स, 183/1, धर्मटोला स्ट्रीट, (2<sup>nd</sup> फ्लोर) कलकत्ता-13 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35017/89/82-पी०-एफ०-II]

S.O. 4034.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Jalan Productions, 183/1, Dharamtolla Street, (2nd Floor), Calcutta-13, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No.S-35017/89/82-PF.II]



कां०आ० 4035.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसेस बारतानालय, 56/1, कनिंग स्ट्रीट, कलकत्ता-1 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35017/94-82-पी०एफ०-II]

S.O. 4035.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Baratanalaya 56/1, Canning Street, Calcutta-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017/94/82-PF-II]

कां०आ० 4036.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसेस कुमार एजेन्सीस, 1/4, डी० खामेन्द्र चटर्जी रोड, कोसीपुर, कलकत्ता-2 जिसके अन्तर्गत 16 इंचिया एक्सचेंज प्लेस कलकत्ता-1 स्थित इसका मुख्यालय भी है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35017/110/82-पी०एफ०-II]

S.O. 4036.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Kumar Agencies, 1/4-D, Khagendra Chatterjee Road, Cossipore Calcutta-2 including its Head Office at 16, Indla Exchange Place, Calcutta-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35017/110/82-PF-II]

कां०आ० 4037.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसेस सिल्वर प्लास्टोकेम (प्राइवेट) लिमिटेड, सी०-101, हिन्द मीरान्द्र इंडस्ट्रियल एस्टेट) अंधेरी कुर्ना रोड, मुम्बई-59 जिसके अन्तर्गत 95 बावेरी बाजार कालबादेवी रोड मुम्बई-2 स्थित इसका रजिस्टर्ड कार्यालय भी है नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35018/57/82-पी०एफ०-II]

S.O. 4037.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Silver Plastochem (Private) Limited, C-101, Hind Saurashtra Industrial Estate, Andheri Kurla Road, Bombay-59 including its Registered Office at 95, Zaveri Bazar, Kalbadevi Road, Bombay-2, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35018/57/82-PF-II]

कां०आ० 4038.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसेस सुनावला आईस फैक्ट्री, 188, लैमिंग्टन रोड, मिनेर्वा सिनेमा के पीछे, मुम्बई-4 और उनके 35-ती जेराईभोय स्ट्रीट, म्युनिसिपल वर्कशॉप के पास, फोरस रोड, मुम्बई-8 स्थित कार्यालय सहित नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35018/58/82-पी०एफ०-II]

S.O. 4038.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sunawalla Ice Factory, 188, Lamington Road, Behind Minerva Cinema, Bombay-4, including its office at 35/C, Jerajbhoy Street, Near Municipal Workshop, Foras Road, Bombay-8, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35018/58/82-PF-II]

कां०आ० 4039.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसेस आर्बोरेस फैक्टरी एम्प्लॉयज कन्स्यूमर्स को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, आर्बोरेस फैक्टरी एस्टेट, वरणगांव, जिला जलगांव, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं०एस०-35018/65/82-पी०एफ०-II]

S.O. 4039.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Ordnance Factory Employees Consumers Co-operative Society Limited, Ordnance Factory Estate, Varangaon, District Jalgaon, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35018/65/82-PF-II]

का०आ० 4040.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स हर्ष प्रिंटर, 122, ड०-मेजरी रोड, सर्वोदय केन्द्र बिल्डिंग, मुम्बई-9, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहियें;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35018/66/82-पी० एफ०-I.]

S.O. 4040.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Harsha Printery, 122, Dr. Meisheri Road, Sarvodaya Kendra Building, Bombay-9, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35018/66/82-PF.II]

का०आ० 4041.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पटेल सिन्थेटिक यार्न (प्राइवेट) लिमिटेड, मिटल एस्टेट सं० 2, गाला सं० 6 और 10, अंधोरी-कुर्ला रोड, मुम्बई-59, जिसके अस्तित्व चोकसे चैम्बर्स, 117, आवेरी बाजार, मुम्बई-2 स्थित इसका सञ्चालन में है। नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों का बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहियें,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35018/68/82-पी० एफ०-I.]

S.O. 4041.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Patel Synthetic Yarn (Private) Limited, Mittal Estate No. 2, Gala No. 6 and 10, Andhori-Kurla Road, Bombay-59 including its Head Office at Choksey Chambers, 117, Zaveri Bazar, Bombay-2, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35018/68/82-PF.II]

का०आ० 4042.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मनीषा नलक नन्द, 11वीं मंजिल, राहेजा चैम्बर्स, नरमन पार्क, मुम्बई-21 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहियें;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35018/56/82-पी० एफ०-II]

S.O. 4042.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Manilal Talakchand, 11th Floor, Reheja Chambers, Nariman Point, Bombay-21, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35018/56/82-PF.II]

का०आ० 4043.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स लक्ष्मी फाइनेंस, 3-6-140/5-बी, हिमायत नगर, हैदराबाद-29, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहियें,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35019/197/82-पी० एफ०-II]

S.O. 4043.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Lakshmi Finance, 3-6-140/5C, Humayat Nagar, Hyderabad-29, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35018/197/82-PF.II]

का०आ० 4044.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स वेंकटेश्वर एग्रो केमिकल्स एण्ड मिनेरल्स (प्राइवेट) लिमिटेड, इन्जीनियरिंग डिविजन, प्लॉट सं० 3-बी, इंडस्ट्रियल एस्टेट, अम्बटूर, मद्रास-98, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहियें;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35019/185/82-पी० एफ०-I]

S.O. 4044.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Venkateswara Agro Chemicals and Minerals (Private) Limited, Engineering Division, Plot No. 3-B, Industrial Estate, Ambatur, Madras-98, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35019/185/82-PF.II]

का० आ० 4045.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ए० श्रीनिवास भट्ट एण्ड कम्पनी, कट्टुकुलम रोड, कोचीन-2, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/186/82-पी०एफ-2]

**S.O. 4045.**—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs A. Srinivasa Bhat and Company, Kettukulam Road, Cochin-2, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35019/186/82-PF.II]

का० आ० 4046.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्री विजय इंडस्ट्रीज, प्लॉट सं० 19, आई०डी०ए० पत्तंचेरु मेडक जिला, आन्ध्र प्रदेश, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/187/82-पी०एफ-2]

**S.O. 4046.**—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sri Vijaya Industries, Plot No. 19, I.D.A., Pathancheru, Medak District, Andhra Pradesh, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35010/187/82-PF.II]

का० आ० 4047.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मुगल महल रेस्तराँ, सेठी भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-8 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/195/82-पी० एफ०-2]

**S.O. 4047.**—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Mughal Mahal Restaurant, Sethi Bhavan, Rajendra Place, New Delhi-8, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35019/195/82-PF. II]

का० आ० 4048.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्रीकाकुलम गवर्नमेंट एम्प्लाइज, को-ऑपरेटिव स्टोर्स लिमिटेड, श्रीकाकुलम (आन्ध्र प्रदेश), नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/196/82-पी० एफ०-1]

**S.O. 4048.**—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs The Srikakulam Government Employees Co-operative Stores Limited Srikakulam (Andhra Pradesh), have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35019/196/82-PF. II]

का० आ० 4049.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स गेल्लू एण्ड सर्विस, आर० एम० कर्नाड बिल्डिंग, उदुपी 576101 जिला कन्नारा कर्नाटक, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/199/82-पी० एफ०-2]

**S.O. 4049.**—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sales and Service, R. M. Karnad Building, Udupi-576101, District Kannada, Karnataka, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35019/199/82-PF. II]



का० भा० 4050.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्रीर एचिवा ग्रार्क एंड मैसर्स वेस्टिंग हावर्स, 18, कोन्नूर हाई रोड, मद्रास-23, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/204/82-पी० एफ०-2]

S.O. 4050.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Our India Arc and Gas Welding Works, 18, Konnur High Road, Madras-23, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35019/204/82-PF. II]

का० भा० 4051.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मिलाक ब्रदर्स, कान्दला फ्री ट्रेड ज़ोन, गान्धी घाट (कच्छ) जिसके प्लॉट नं० 509, चर्चगेट चैम्बर्स-5, न्यू मेरीन लाइन्स, मुम्बई-20 स्थित इसकी शाखा भी है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध, उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/205/82-पी० एफ०-2]

S.O. 4051.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Milak Brothers, Kandla Free Trade Zone, Gandhidham (Kutch) including its branch at 509, Churchgate Chambers, 5, New Marine Lines, Bombay-20, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35019/205/82-PF. II]

का० भा० 4052.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एक्सप्रेस प्रोसेस एन्ग्रेवर्स, 4/1, कीर्तिनगर औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली-15, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/210/82-पी० एफ०-2]

S.O. 4052.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Express Process Engravers, 4/1, Kirti Nagar, Industrial Area, New Delhi-15, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35019/210/82-PF. II]

का० भा० 4053.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स यूनियन इंजीनियर्स 7/27 कीर्तिनगर औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/211/82-पी० एफ०-2]

S.O. 4053.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Unison Engineers, 7/27, Kirti Nagar, Industrial Area, New Delhi, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35019/211/82-PF. II]

का० भा० 4054.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स प्रभात किरण फ्लैट ओनर्स एसोसिएशन प्रभात किरण 17 राजेन्द्र प्लेस नई दिल्ली-8 जिसके प्रतियोग इसके दो यूनिट अर्थात् दीप शिखा फ्लैट ओनर्स एसोसिएशन और कीर्ति महल फ्लैट ओनर्स 17 राजेन्द्र प्लेस नई दिल्ली भी है नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/212/82-पी० एफ०-2]

S.O. 4054.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Prabhat Kiran Flatowners Association, Prabhat Kiran, 17, Rajendra Place, New Delhi-8 including its two units namely Deep Shikha Flatowners Association and Kirti Mahal Flatowners, 17, Rajendra Place, New Delhi, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35019/212/82-PF. II]



कां.आं. 4055.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कावेरी कन्टेनर्स (प्राइवेट) लिमिटेड बी/12-13/जय भारत इंडस्ट्रियल एस्टेट जलहाली कैम्परोड यशवंतपुर बंगलूर-22 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस०-35019/213/82-पी.एफ.-II]

S.O. 4055.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Cauvery Containers (Private) Limited, B, 12-13, Jai Bharat Industrial Estate, Jalahalli Camp Road, Yeswanthpur, Bangalore-22, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019/213/82-PF. II]

कां.आं. 4056.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्री बासाली माडर्न राइस मिल, 27, रेलवे स्टेशन रोड, मिरकाली, तमिल नाडु, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस०-35019/221/82-पी.एफ०-II]

S.O. 4056.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sree Balaji Modern Rice Mill, 27, Railway Station Road, Sirkali, Tamil Nadu, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019/221/82-PF. II]

कां.आं. 4057.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स गांधीगंज प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गांधी गंज, बोडार, कर्नाटक, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस०-35019/232/82-पी.एफ०-II]

S.O. 4057.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs The Gandhi Gunj Primary Co-operative Bank Limited, Gandhi Gunj, Bidar, Karnataka, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019/232/82-PF. II]

कां.आं. 4058.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इंटिग्रेटेड प्रोसेस ऑटोमेशन (प्राइवेट) लिमिटेड, ए-173 फर्स्ट फेज, कीर्षी क्रास, पीन्या इंडस्ट्रियल एस्टेट, बंगलूर-58 जिसके अन्तर्गत कार्ड सं० 16, कासरिडीह, धानी भवन के सामने, दुर्ग-1, मध्य प्रदेश स्थित इसकी शाखा भी है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस०-35019/231/82-पी.एफ०-II]

S.O. 4058.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Integrated Process Automation (Private) Limited, A-173, 1st Phase, 4th Cross, Peenya Industrial Estate, Bangalore-58 including its branch at Ward No. 16, Kasaridih, Opposite Dhani Bhavan, Durg-1, Madhya Pradesh, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019/233/82-PF. II]

कां.आं. 4059.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रोमर फैशन्स, 2, एरबालू चेट्टी स्ट्रीट, पहली मंजिल, मद्रास-1, नाम स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस०-35019/234/82-पी.एफ०-II]

S.O. 4059.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Romar Fashions, 2, Errabalu Chetty Street, 1st Floor, Madras-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019/234/82-PF. II]

का०आ० 4060.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स जनरल कामर्स लिमिटेड, 102, बंगला साहिब रोड, नई दिल्ली-1 जिसके अन्तर्गत 50/2-3 हनुमान रोड, नई दिल्ली-1 स्थित इसकी शाखा भी है, मागक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इन बातों पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उप-बंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/236/82-सी०एफ०-II]

ए०के० भट्टारार्ई, अवर सचिव

S.O. 4060.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs General Commerce Limited, 102, Bangla Sabib Road, New Delhi-1 including its branch at 50/2-3, Human Road, New Delhi-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019/236/82-PF. II]

A. K. BHATTARAI, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 1982

का०आ० 4061.—केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची के भाग-1 में मैग्नेटाइट खानों का नियोजन जोड़नी है जिसे जोड़ने के संबंध में वह भारत के राजपत्र समाचारण, दिनांक 14 मई, 1982 के भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के मंत्रपरिषद् श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 320(ए) दिनांक 14 मई, 1982 द्वारा अपने आशय की सूचना पहले दी जा चुकी है।

[सं० एम०-32017/2/81-इल्यू सी (एम० इल्यू०)]

एम०एल० मेहता, अवर सचिव

New Delhi, the 11th November, 1982

S.O. 4061.—In exercise of the powers conferred by Section 27 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), the Central Government hereby adds to Part I of the Schedule to that Act, the employment in Magnetite mines, notice of its intention to do so having already been given, by the notification of Government of India in the late Ministry of Labour number S. O. 320 (E) dated the 14th May, 1982 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 14th May, 1982 as required by the said section.

[No. S-32017/2/81-WC(MW)]

M. L. MEHTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 1982

का०आ० 4062.—मैसर्स अग्रः ट्रास्टपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड, सं० 12, रामकृष्ण रोड, सलीम-7 टी० अं० 7460, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) के कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अधिवाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निधम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निवेश मंडल बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपबन्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

#### अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्रिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रचारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्रिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रचारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उन संशोधन की प्रति नया कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उनकी मुख्य भाषा का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम पुरस्कृत करेंगे और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निधम को संवत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस वक्ता में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता हो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/गैम निर्दिष्टी को प्रतिवर्ष के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का व्यक्तिगत अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापना के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों की प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस निवृत्त तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में, असफल रहता है, और पालिसी को अमान्य हो जाने दिया जाता है, तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्ति-क्रम की वक्ता में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों की जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उनके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रवेष्ट दाता में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के मान बिना के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस० 35014/440/82-भ०नि०-II]

New Delhi, the 11th November, 1982

**S.O. 4062.**—Whereas Messrs Anna Transport Corporation Limited, No. 12, Rama Krishna Road Salem-7 (TN/7460) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contributions or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

#### SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide for such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would, have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014 (440)/82-PF. II]

कोटांश 4063.—मैंमें गन्धार्थ पेरियार हांगपोट कांफोरेणन लिमिटेड, 3/137, मायनेड, वाक्करोडी पोस्ट ग्रामिना, पोस्ट कोटा नं० 56, बिल्लपुरम-605602 (तमिलनाडु/8001), (जिसे हमें इसके परम्परागत स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे हमें इसके परम्परागत



प्रधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (अ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए प्रावधान किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक भविष्य या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये वे फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निवेश सहस्रक बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा (अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाय्य अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

### अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, तमिलनाडु को ऐसे विवरणों का प्रेषण और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएँ प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रचारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा (अ) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिससे सम्बन्धित लेखाओं का रखा जाना, विवरणों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तर्गण, निरीक्षण प्रचारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहुत नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी भुक्त्य वाली का अनुवाद, स्थापन के सूचना पत्र पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि पर या उक्त प्रधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम पुरस्त दर्ज करेगा और उसकी आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम की संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों की उपलब्ध फायदे बढ़ते जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों की उपलब्ध फायदों में अनुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देश राशि उस रकम से कम है, जो कर्मचारी की उस क्षण में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी को विधिक जाप/नामाविर्निती की प्रतिलिपि के रूप में दोनो रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और अर्थात् किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल

प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पड़ता अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियम तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियम करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को अग्रगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों की जो यदि यह छूट नहीं गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन घाने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्पराता से और प्रत्येक वारिस में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/383/82-नॉ-एफ-0-II]

S.O. 4063.—Whereas Messrs. Thanthal Periyar Transport Corporation Limited, 3/137, Salamedu, Valudhareddy Post Office, Post Box No. 56, Villupuram-605602, (TN/8094) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

### SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.



5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014 (383)/82-PF. II]

क्र० आ० 4064—सर्वमं पॉइन्टान रोडवेज कार्पोरेशन लिमिटेड, बार्ड पास रोड, मयुरी-625016 (टी एन/6882) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19), जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उक्त फायदों से अधिकानुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहज बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुश्रेय है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए और इसमें उपाध्व अनुमूर्ती में निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापनों को तीन वर्षों की अवधि के लिए, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

1001 G of I/82--6

### अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि अधिनियम तमिलनाडु को ऐसी विवरणियाँ भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुद्राधार प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निश्चित करे।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभावों का प्रत्येक माम की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निश्चित करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रभावों में, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाधारा का अन्तर्गण, निरीक्षण प्रभावों के संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम पुरस्कृत करेगा और उसकी श्रावित आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदाय करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों की उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों की उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उक्त फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुश्रेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी क्षति के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन मन्वेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में मिले होंगी, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के धिक्क वारिस/नामनिर्देशनी की प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के अंतर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का व्यक्तिगत अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्रदान होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियम तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियम करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्ययनिकम दशा में उस मूल सदस्यो के नामनिर्देशनियों या अधिकारियों को जो अधिक छूट दी गई होनी ता उक्त स्कीम के अंतर्गत होने, बीमा फायदो के संदाय का उदरदायिक नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशनियों अधिकारियों की बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के तत्त दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस 35014/278/82-पी.एफ. II]

S.O. 4064.—Whereas Messrs Pandiyan Roadways Corporation Limited, Byc Pass, Road, Madurai-625016 (TN/6882) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

#### SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that

would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment scheme do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(278)/82 PF. II]

नई दिल्ली, 12 नवम्बर 1982

कां०आ० 4065.—संसद में पी.पी. हर्षदेविका एण्ड हर्षदेविका लिमिटेड, 7154, अशासलाई, मद्रास (टी.एन. 3072) (जिसे हमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) (जिसे हमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

श्री केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अधिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी भविष्य निधि सदस्य बीमा स्कीम, 1976 (जिसे हमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुमेष हैं।

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और हमसे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

#### अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर सिद्ध करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभागों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संचाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का, संचाय, लेखाओं का अन्तर्गण निरीक्षण प्रभागों का संचाय प्रादि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को बहुमुख, की भाषा में उनकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम दुरुस्त करेंगे और उसको मासिक आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सौंप करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदों उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुभूत हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन भव्य रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस वृत्ति में संचय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशित को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संचाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां कि संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का व्यक्तिगत अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संचाय करने में असफल रहता है, और पालिसी की व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संचाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की वृत्ति में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संचाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उनके हकदार नामनिर्देशितों/

विधिक वारिसों की समाकृत रकम का संचाय दरपरा से और प्रत्येक वृत्ति में भारतीय जीवन बीमा निगम से समाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस० 35014/87/82-पी०एफ-2]

New Delhi, the 12th November, 1982

S.O. 4065.—Whereas Messrs Peigo Electronics and Electricals Ltd., Philips, 154, Anna Salai, Madras-600002 (TN/3072) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

#### SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.



8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(87)/82-PF. II]

का०शा० 4066.—मैसर्स क्रिसेन्ट डायस एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, क्रिसेन्ट हाउस, बेलार्ड एस्टेट, बम्बई (मन्त्रा/1108) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों में अधिकानुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुश्रेय है,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

#### अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र का ऐसा विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा या केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाता विवरणियां का प्रस्तुत किया जाता, बीमा प्रीमियम का संचाय, लेखाओं का अन्वयण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में, उनकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम नुस्न दर्ज करेगा। और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदाय करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि को जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुश्रेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन मृत्यु रकम उस रकम के कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संवेद्य होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिकारि/नामनिर्देशितों का प्रतिफल के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने में पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और वागिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की वशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिकारियों को जो यह छूट दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होंगे, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन जाने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिकारियों की बीमाकृत रकम का संदाय तत्पश्चात् से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के मातृ दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/315/82 पी०एफ०-2]

S.O. 4066.—Whereas Messrs Crescent Dyes and Chemicals Limited, Crescent House, Ballard Estate, Bombay-400038 (MH/1108), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance scheme of the



Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

#### SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (3) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(315)/82-PF. II]

क्र.० आ.० 4067—संसर्ग इनेक्स इजिन्ट बाल्बज लिमिटेड 17-बी, इंदौर इंडस्ट्रियल एस्टेट, पुणे-411013. (महा/11763) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपग्रह अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (3क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अधिदाय या प्रीमियम का संशय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उक्त फायदे से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारियों निरंतर महबूद बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुसूच्य है,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा, (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसमें उल्लेख अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपधारा के प्रवर्तन से छूट देता है।

#### अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आवृत्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार संलग्नमध्या पर निदिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभावों का प्रत्येक भाग की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निदिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रणालन में, जिसके अनुरूप लेखाभावा रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संशय, लेखाभावा का अन्तर्ग, निरीक्षण प्रभावों का सदाय आदि भी है, होना बाकि सभी व्ययों का बहुत नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तथा उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को बहुसंका की भाषा में उनकी मुख्य भाषाओं का अनुवाद, स्थापना कर्मचारी-वृद्ध पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का, पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उनका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदाय करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उल्लेख फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों का उल्लेख फायदों में समूचित रूप से वृद्धि का आदेश देकर देगा जिस कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उल्लेख फायदे उक्त फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुसूच्य हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अर्धीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अर्धीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशनी को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उद्देश्यों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भावपूर्ण निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपनी चुका है अर्धीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अर्धीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से घटा हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियम तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पॉलिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यवस्थापन की दशा में उस मूल सदस्यों के लाभनिर्देशनियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होता।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अर्धीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशनियों विधिक वारिसों की बंभाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सान्वित के भीतर मुनिष्ठित करेगा।

[सं० एम-35014(313)/82-पी०एफ० II]

**S.O. 4067.**—Whereas Messrs Inex Engine Valves Limited, 17-B, Hadapsar Industrial Estate, Pune (MH/11765), thereafter referred to as the said establishment have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (thereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

#### SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case with 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(313)/82-PF.II]

का० आ० 4068.—मैसर्स एन० जी० ई० एफ० लिमिटेड, तिर्हर-कोन हाऊस, डा० ई० मोसेम रोड, महाश्वर, बम्बई-11 (महा/17509) (जिसे इनमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उद्देश्य अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इनमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अर्धीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अधिवाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना हो,

भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निवेश म्यूचुअल बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उठाने योग्य है,

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इसमें उल्लेख अनुसूची में किर्तिपिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को नीत बर्ष की अवधि के लिए, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

#### अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसी लेखा रखाता तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रसारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) के अन्तर्गत (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अवरणन, निरीक्षण प्रसारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का उक्त नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदन सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रवर्तित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदाय करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी को मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दुर्दृष्टिकोण स्पष्ट करने का धुनियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपनी चुका है

अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असमर्थ रहता है, और पारिमी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मूल सदस्यों के नामनिर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निवेशितियों/विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम में बीमाकृत रकम प्राप्त होने के मान दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एम-35014/1978-पी० एफ-11]

**S.O. 4068.**—Whereas Messrs N.G.F.F. Limited, Ticericon House, Dr. E. Moses Road, Mahalaxmi, Bombay-11 (MH/17509) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India, in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

#### SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra (Bombay), maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premium, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme.



appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heirs/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra (Bombay) and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(297)/82-PF. II]

का.आ. 4069 -- मैसर्स इर्जिनिया इण्डस्ट्रियल फौरी कम्पनी, मेतपायाम रोड कोयम्बटूर-9 (नामलनाचु/2356) (जिसे हमने इसके पञ्चान उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और पक्षी उपायधन अधिनियम, 1952 (1952 का. 14) जिसे हमने इसके पञ्चान उक्त अधिनियम कहा गया है) को धारा 17 की उपधारा (अक) के अन्तर्गत छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार ने, समाधान हा गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अधिदाय या प्रीमियम का सहाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अर्धीत जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये वे फायदे उक्त फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निधेय सहस्र बीमा स्कीम, 1976 (जिसे हमने उक्त पञ्चान उक्त स्कीम कहा गया है) के अर्धीत उन्हें अनुशेय हैं,

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (अक) द्वारा प्रदत्त शर्तियों का प्रयोग करने हुए, और इससे उपायधन अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अर्धीत रहने हुए, उक्त स्थापन को न स कार्य को अर्धीत के लिए उक्त स्कीम के महा उपस्थिति के अर्धीत में छूट देता है।

अनुशेय

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त नामलनाचु का मैसर्स इण्डस्ट्रियल फौरी और ऐसे लेखा रखेगा

यथा निरीक्षण के लिए ऐसा गुविधान प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (अक) के खण्ड (क) के अर्धीत समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशान्त में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, शिक्कणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सदाय आदि भी है, हाने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तथा उक्त संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अर्धीत छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाना है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदाय करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अर्धीत कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बहाल होते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अर्धीत कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अर्धीत उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अर्धीत अनुशेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अर्धीत सदस्य रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अर्धीत होता तो, नियोजक कर्मचारी के अधिक वारिस/नामनिर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपस्थानों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, नामलनाचु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेने की संभावना हो, वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति-युक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अर्धीत नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अर्धीत कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का सदाय करने में अमकल रहता है, और पालिसी को व्यवगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितों या अधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।



12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर, उसके हकदार नाम निर्देशनियों/विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का संदाय गलतफहमी से भीतर, प्रत्येक दश में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के मातृ दिन के भीतर मुनिश्चित करेगा।

[संख्या. एस-35014/277/82-पां०पफ०-II]

**S.O. 4069.**—Whereas Messrs Engineering Industrial Foundary Company, Mettupalayam Road, Coimbatore-9 (TN/2356) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

#### SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

1001 GI/82—7

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(277)/82-PF. II]

कां०आ० 4070—मेसर्स श्री राम रेयन्स, श्रीराम नगर, कोटा-32404 (राजस्थान) (राज०/1128) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अधिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये वे फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप महत्व बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं।

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त णक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपायय अनुसूची में विनिर्दिष्ट णतों के अधीन रहने हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देता है।

#### अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान को ऐसे विवरणियों भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभावों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रणालन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जातः, बीमा, प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभावों का संदाय-आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पत्र पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम गुरन्म दर्ज करेगा और उसकी बाइन आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदाय करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं, तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुमोदित हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बाइन के होने हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देश्य रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशित को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा, और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति-युक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उक्त सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उक्त नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रह की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्ययिक्त की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके वक्तादार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक वशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के तत्पश्चात् के भीतर मुनिषिचन करेगा।

[संख्या एम-35014/276/82-सी०एफ०-II]

**S.O. 4070.**—Whereas Messrs Shriram Rayons Shriram Nagar, Kota-324004 (Rajasthan) (RJ/1128) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India, in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

### SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under the Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment

shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(276)/82-PF. II]

का० आ० 4071.—मैसर्स राणाक इंटरनेशनल लिमिटेड, इलाहाबाद बैंक बिल्डिंग, 17-पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-1 (डी एल/2229) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अधिवास या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुभूत है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन का सान बर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

#### अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, दिल्ली की ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐम लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निश्चित करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रसारों का प्रत्येक माम की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निश्चित करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रसारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनसे संशोधन किया जाए, तब उन संशोधनों की प्रति तथा कर्मचारियों को बसुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पत्र पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम मुरन्त दर्ज करेगा और उसकी वांछित प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदाय करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाने हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में सम्मिलित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुभूत हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होने हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर उक्त स्कीम के अधीन संशोधन रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस वृत्ति में संशोधन होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिवक वारिस/नामनिर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त दिल्ली के पूर्ण अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का व्यक्तिगत अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत मारोख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यवगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्ययक्रम की वृत्ति में उन मूल सबसर्वों के नामनिर्देशितियों या विधिवक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन होने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों विधिवक वारिसों की बीमाकृत रकम का संदाय तत्पश्चात् से और प्रत्येक वृत्ति में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सान दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014(275)/82-पी०एफ०-11]

S.O. 4071.—Whereas Messrs Raunaq International Limited, Allahabad Bank Building, 17, Parliament Street, New Delhi-110001 (DL/2229) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India, in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

#### SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.



2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(275)/82-PF. II]

क्र.आ. 4072—मेसर्स फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मधुबन, 55 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकोण उपग्रन्थ अधिनियम 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें

इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अधिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निधेय सहस्र बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुश्रेय है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपायधन अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

#### अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त विल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुद्रिणाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रचारों का प्रत्येक मान की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रचारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किया स्थापन को भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम गुरत दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुश्रेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी भान के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्ध्य रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस वषा में संवेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिवत वारिस/नामनिर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।



8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का व्यक्तिगत अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उम्र सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उम्र नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम करे संदाय करने में असफल रहता है, और पॉलिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाना है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तित्वम की वशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सप्ताह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/274/82-फा.एस.-II]

**S.O. 4072.**—Whereas Messrs Fertilizer Corporation of India Limited, Madhuban, 55, Nehru Place, New Delhi-110019 (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India, in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

#### SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heirs/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium etc. the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(274)/82-PF. II]

कां०आ० 4073.—मैसर्स फर्टीलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 48-कांठिवली इण्डस्ट्रियल एस्टेट, कांठिवली (बेस्ट)-बम्बई-400067 (महं./1419) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का मस्यौदा हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारियों, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन

बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुभूत हैं;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसके उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

#### अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियाँ भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएँ प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रसारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिनके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रसारों का संदाय भावि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम गुरस्त दर्ज करेगा और उसको बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत् करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुभूत हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्धेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस वृत्ति में संवेद्य होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना

चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिक्रम की वृत्ति में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरव्यवस्था नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का संदाय तत्पश्चात् से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/270/82-पी०एफ-II]

S.O. 4073,—Whereas Messrs I.P.C.A. Laboratories Pvt. Limited 48, Kandivli Industrial Estate, Kandivli (West)-Bombay-400067 (MH/1419) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India, in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

#### SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol

him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heirs/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(270)/82-PF. II]

का० आ० 4074:—संसर्ग चमकाव, अम्बलूर इण्डस्ट्रियल एस्टेट, मद्रास (टी एन/6767) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रमाण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निवेश सहायक बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हे अनुज्ञेय हैं;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

### अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निविष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभावों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निविष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रणामन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तर्गण, निरीक्षण प्रभावों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत् करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों का उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होने हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन मन्द्य रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी की उस दशा में संध्य होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिका वारिस/नामानिर्देशित को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना, नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का सुक्ति-युक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियम तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियम करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपन हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय के लिए गए किसी व्यतिक्रम की वशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिका वारिसों को



जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होने, बीमा कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व नियोजक पर होता।

12. उक्त स्थापन के समय में नियोजक, इस स्कीम के अर्धन अर्धन वाले किन्हीं सदस्यों की मृत्यु होने पर उनके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिवत बरिम्बो की बीमाकृत रकम का संदाय तत्पश्चात् से और प्रत्येक वर्ष में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के मान्य दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एम- 35014/249/82-पी.एफ. II]

**S.O. 4074.**—Whereas Messrs. Chemfab, Ambattur Industrial Estate, Madras (TN/6767) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

#### SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employers.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Schemes and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, of the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(249)/82-PF.II]

**का.आ. 4075.**—मैसर्स केम्फैब कारपोरेशन, लक्ष्मीनिवास, जयन्तगंज, त्रिवार, 474009 (एम पी/2261) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपग्रह अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अधिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की समूहिक बीमा स्कीम के अर्धन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप महसूला बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करने हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

#### अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायक्त मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभागों का प्रत्येक मस की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. समूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तर्गण, निरीक्षण प्रभागों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।



4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा बना अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अन्तर्गत छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम सुरक्षित दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत् करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों की उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनु-भोग्य हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी की उस वृत्ति में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संवाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का व्यक्ति-युक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इन स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति में कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उन नियत तारीख के अन्तर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पारिसी को अग्रण हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की वृत्ति में उन मूल सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इन स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके उत्तरदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का संवाय तत्परा में और प्रत्येक वर्ष में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एम-35014/248/82 पी.एफ.-II]

**S.O. 4075.**—Whereas Messrs Ambar Corporation, Laxmini-was, Jayendraganj, Gwalior-474009 (MP)2261 (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

1001 GL82—8

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years

#### SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employees, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employer been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India etc. and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of insurance benefits to the nominees or the legal heirs of

deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014 (248)/82-PF.II]

कां.आ. 4076—दीर्घसर्त दूरवाणी केबल्स प्राइवेट लिमिटेड, "मारुथी मैनशन" टीसी मंजिल, 19/7, कनिंघम रोड, बंगलूर-560052 (केएन/4661) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) के कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 10) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् प्रीमियम या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में कायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये कायदे उन कायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहज बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाय अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

#### अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक को ऐसी विवरणियाँ भेजेंगी और ऐसे लेखा रखेंगी तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएँ प्रदान करेंगी जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निश्चित करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रधारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निश्चित करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रसारण में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अक्षरण, निरीक्षण प्रधारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा, यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की अनुसंख्या की भाषा में उक्त मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम गुरुत्व रखेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम का संदाय करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध कायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों

को उपलब्ध कायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध कायदे उन कायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस वृत्ति में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का पुनर्विचार अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिने स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले कायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियम तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को स्वयंसेवक हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्ययक्रम की वृत्ति में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों की जो यदि यह छूट - दो वर्षों की हो तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा कायदों के संशय का अनारक्षित निराकरण होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हक्का नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का संशय तत्परता से और प्रत्येक वर्ष में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस-35014/244/82-पे. १३-II]

S.O. 4076.—Whereas Messrs Doorvanl Cables Private Ltd., Maruthi Mansion, 3rd Floor, 19/7 Cunningham Road, Bangalore-560052 (KN-4661) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

## SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of Insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employers.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium etc. the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

कां० भा० 4077—मैसर्स मेटल वाक्स इंडिया लिमिटेड, 19, इलाहक मुदाली स्ट्रीट, तोदिरपेट, मद्रास (टी एन/196) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया गया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अधिधाय या प्रीमियम का संवाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निधि सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुभूत है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

## अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिसलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रचारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा, प्रीमियम का संवाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रचारों का संवाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सवत करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुभूत हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संवेद्य रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस वक्ता में संवेद्य होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशी को



प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर के बराबर रकम का भुगतान करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपखण्डों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त भवितवाह के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का व्यक्तिगत अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिस स्थापन पहले अपना चुका है, अधिन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधिन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तरीके के अंतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्ययक्रम की वशा में उन मूल सदस्यों के नामनिर्देशनियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न की गई होती तो उनके स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधिन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकार नाम निर्देशनियों/विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक वषा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के बाद दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस० 35014/241/82-पी०एफ० II]

**S.O. 4077.**—Whereas Messrs Metal Box India, Ltd., 19, Elaiya Mudali Street, Tondiarpet, Madras (TN/196) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

#### SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc shall be borne by the employers.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(241)/82-PF.II]

क्र.सं. 4078—जिसमें इन्को इन्स एण्ड कैमिकल्स मैसर्स लिमिटेड को 37, ए-एण्डस्ट्रीट एस्टेट पोली पाउण्ड, दमोदर-452002 (कोड सं. 2470) (जिसे हमने इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे हमने इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधिन छूट दिए जाने के लिए प्रार्थना किया है;



और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अधिनियम या प्रीमियम का संचालन किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए वे फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूलन हैं जो कर्मचारी निधेन सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इससे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुभूति है,

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाय अन्तर्गुह्य में निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्षों की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

#### अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निविष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रसार का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संचालन करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निविष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संचालन, लेखाओं का अन्तर्गण, निरीक्षण प्रभारों का संचालन आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहुत नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुसूचि सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या का भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम सुरक्षित दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संचालन करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं, तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूलन हैं जो उक्त स्कीम के अधीन अनुभूति है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सम्बन्धित रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संचालन करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का संभावना है, वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपनी दृष्टिकोण स्पष्ट करने का सुनिश्चित अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिस स्थापन रहने अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो वह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियम सारिख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें। प्रीमियम का संचालन करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संचालन में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मूल सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संचालन का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियां/विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का संचालन तत्पश्चात् से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/239/82-पी०एफ० II]

S.O. 4078.—Whereas Messrs Ethico Drugs & Chemicals Mfg. Co., 37-A, Industrial Estate, Pologround, Indore-452003, (MP/2470) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India, is the nature of Life Insurance which is more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts, the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

#### SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Madhya Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employer in

his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the said Scheme is enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(239)/82-PF.II]

कां० 4079.—मैसर्स सीबर्स इंजीनियरिंग वर्क्स, इण्डस्ट्रियल टाउन जालंधर-144004 (पी/एन) 160) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्ररुण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 के उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अधिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल जो कर्मचारी विशेष सहज बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुसूची है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपबन्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

### अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त पंजाब को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रसारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रसारों का संदाय प्रादि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुवीक्षित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुबाध, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत् करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों की उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुसूची हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सम्पन्न रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस वृत्ति में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के अधिक वारिस/नामनिर्दिष्ट को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त पंजाब के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व, कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का सुनिश्चित अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उक्त सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी की व्यवगत हो जाने दिया जात है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न की गई होती तो उक्त स्कीम के संलग्न होते, बीमा फायदों के संदाय का अंतरास्थित नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके लुकरदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का संदाय तत्पक्ष से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/238/82-पीएफ-11]

8.O. 4079.—Whereas Messrs Leader Engineering Works, Industrial Town, Julundhar-144004 (PN/160) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

#### SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominees/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(238)/82-PF.II]

कां.मां. 4080--मैसर्स हिन्दुस्तान ब्राउन बोवरी लिमिटेड, पो.वाक्स नं० 16 बार्डोण-फरीदाबाद (पी.एन. 375) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अधिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदों का उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए वे फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप महत्व बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुभूत है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपायध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

#### अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, पंजाब को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर भिन्नित करे।



2. नियोजक, ऐसे निरोक्षण प्रसारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा या केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के अन्वय (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिनके अन्तर्गत सेवाओं का रखा जाना, निरोक्षणों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, सेवाओं का अन्तर्गण, निरोक्षण प्रसारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का प्रस्ताव, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम सुरक्षित करें करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक आनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुसूचित हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी का उस वृत्त में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उद्देश्यों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि अध्याय, पंजाब के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि अध्याय अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों की अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर होगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह छूट यह की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत मर्यादा के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी की व्यवस्था ही जाने दिया जाता है या, छूट यह की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्ययक्रम की वृत्त में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उनके हकदार नाम निर्देशितियों/

विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक वृत्त में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के तान दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एन 35014/237/82-पी०एफ०-11]

S.O. 4080.—Whereas Messrs Hindustan Brown Boveri Ltd., Post Box No.16, I.A. Faridabad (PN)375 (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

#### SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and

where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No.S-35014(237)/82-PF.II]

का० जा० 4081. -- मैसर्स श्री गणेश रोलिंग मिल्स, विल्सी रोड, सातरोड खुरद (हिस्सर)-125044 (कोड नं० पी० एन०/4563) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अधिधाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहस्रक बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुभूते हैं;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपबन्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

#### अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त पंजाब की ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निरदिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रसारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 के उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निरदिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाधियों का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाधियों का अन्तरण, निरीक्षण प्रसारों का संदाय प्रादि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहुत नियोजक द्वारा किया जायेगा।

1001 GI/82-9

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उनकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-बोर्ड पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संबल करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुभूते हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी को मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संवेद्य रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संवेद्य होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त पंजाब के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का मुक्तिपुस्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन जाने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक बला में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के साथ-साथ के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-38014/236/82-पी० एफ-II]

S.O. 4081.—Whereas Messrs Shree Gantah Rolling Mills, Delhi Road, Satrod Khurd (Hissar)-125044 (Code No. PN/4563) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976, (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

#### SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc shall be borne by the employers.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life

Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(236)/82-PF. II]

का० आ० 4082 --संसर्ग नेशनल को-ऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन प्रा० लिमिटेड, मुख्यलय दोपाडी, (5वां फ्लोर) 92-नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019) कोड-नं० बीएल 2333, (जिसे हममें हमके पञ्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि अधीन प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे हममें हमके पञ्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है कि धारा 17 की उपधारा 2क के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

श्रीर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निधन की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निरक्षर सहकारी बीमा स्कीम, 1976 (जिसे हममें हमके पञ्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुमति है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्रीर हममें उपाख्य अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्षों की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

#### अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अस्तर्ण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-बोर्ड पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पक्ष ले हो सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम सुरक्षित दर्ज करेगा और उसकी आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निधन को संदान करेगा ।



6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होने हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संवेद्य रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संवेद्य होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिका को प्रतिद्वार के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का भुगतान करेगा।

8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भाषिय निधि आयुक्त दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किन्हीं संशोधनों में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो सकती है, प्रादेशिक भाषिय निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का सुविधायक अवसर देगा।

9 यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की इस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पड़ने अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों का प्राप्ति होने वाले फायदे किसी रीति में कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10 यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियम तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का भुगतान करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययपत्र हो जाना दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के भुगतान से किए गए किसी व्यतिक्रम की वशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशनियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के भुगतान का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12 उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके सहकार नाम निर्देशनियों/विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का संभाव्य क्षतिपूर्ति में और प्रत्येक वशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के तत्पश्चात् के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एम-15014/231/82-पी० एफ-2]

**S.O. 4082.**—Whereas Messrs National Cooperative Consumer's Federation of India Ltd., H. O. : Deepali (5th Floor), 92, Nehru Place, New Delhi-110019 (Code No. DL2333) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto,

the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

#### SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premium, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employers.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment

shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(234)/82-P.F. II]

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 1982

का० आ० 4083.—मैसर्स डी० सी० एम० इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, असरोन, रोपड़ (पी एन/5959) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संवाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप महसूब बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुभूत है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रखते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

#### अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पंजाब को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रबेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रचारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (ग) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय, लेखाओं का अन्तर्गण, निरीक्षण प्रचारों का संवाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद; स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुभूत हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संवेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस वषा में संवेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता, तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशितों को प्रतिफल के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संवाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पंजाब के पूर्ण अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को भरना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का सुनिश्चित अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले भरना पड़ा है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संवाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है, तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की वषा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संवाय तत्पश्चात् से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सान दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एम-35014/245/81-नो०एफ० 2]

New Delhi, the 13th November, 1982

S.O. 4083.—Whereas Messrs DCM Engineering Products Works, Asron, Ropar (PN/5959) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

#### SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employers.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund, of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(245)/82-PF.II]

का० आ० 4084.—मैमर्स नमिलनाडु शूगर केन फार्म कारपोरेशन लिमिटेड बाधाप्राधिकारनगम थंजावर (टीन एन/7930) (जिसे हममें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) के कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे हममें इसके

पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिवाय या प्रीमियम का संवाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप मल्लवध बीमा स्कीम 1976 (जिसे हममें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसके उपायधन अनुसूची में विनिर्दिष्ट बातों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

#### अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुद्रियाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निरिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निरिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अनगूँन लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संवाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदन सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी, मुख्य बातों का अनुबाध, स्थान के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पक्षे ही सदस्य है, उनके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उरलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उरलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उरलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उन रकम में कम है, जो कर्मचारी की उस वृत्ति में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामानिर्वाहियों को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संवाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन



देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का सुक्तिपुक्त अवसर देना।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उन सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अश्वीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अश्वीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नवोक्त उन नियत शारीरिक के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियुक्त करे प्रतिभार का मदाय करने में प्रयत्न रहता है और पालिसी को अश्वीन हो जाने किश जाना है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. निवांशक द्वारा प्रामिस के मदाय में किए गए किसी अश्वीन को दशा में उन मृत सदस्यों के नामानर्शितया या विधक वारिसों को जो यदि यह छूट न हो गई होती तो उक्त स्कीम के अश्वीन हो, या फायदे के मदाय के, उत्तरदायित्व निवांशक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सब में निवांशक इस स्कीम के अश्वीन आने वाले किसी सदस्य को मृत्यु होने पर उक्त हकदार नाम निर्देशितया विधक वारिसों को बीमाकृत रकम का मदाय तररा से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम में बीमाकृत रकम प्राप्त होने के नाम दिन के भीतर मुतिश्वन करेगा।

[संख्या एस-35014/252/82-पी०एफ०-11]

**S.O. 4084.**—Whereas Messrs Tamil Nadu Sugar Cane Farm Corporation Limited, Vadapathimangalam, Thanjavur. (TN/7930) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

#### SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc., shall be borne by the employers.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(252)/82-PF.II]

का० आ० 4085—मैसर्स डेल्टा केवम लिमिटेड, 24, इन्दिराजी नई दिल्ली (डीएम/179) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी अधिध निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अश्वीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अधिदाय या प्रीमियम का मदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अश्वीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निधेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अश्वीन उन्हें अनुशेष है।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

#### अनुसूची

1. उक्त स्थापन के गबन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली को ऐसा विवरणित भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निश्चित करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संचाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निश्चित करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियां का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संचाय, लेखाओं का अन्तर्गण, निरीक्षण प्रभारों का संचाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी भुज्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संचाय करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुलब्ध हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन गन्धेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संचय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिवत वारिस/नामनिर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनो रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संचाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का संभावना हो, वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियम तारिख के अन्तर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संचाय करने में असफल

रहता है, और पालिसी को अग्रगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संचाय में किए गए किसी व्यक्तिगत की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशनियों या विधिवत वारिसों को जा यदि यह छूट न की गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होने, बीमा फायदों के संचाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशनियों/विधिवत वारिसों की बीमाकृत रकम का संचाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एम०-35014/254/82-वी० एफ-11]

**S.O. 4085.**—Whereas Messrs Delton Cables Limited, 24, Daryaganj, New Delhi (DL/179) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

#### SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employers.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employers.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(254)/82-PF.II]

का० आ० 4086:—मैसर्स जैनेलेक लिमिटेड, जोगेश्वरी इस्ट, बम्बई (एम० एच०/609) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य विधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अधिवास या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सङ्ग्रह बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुमति है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपबन्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

#### अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियाँ भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएँ प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निविष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभागों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निविष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना-विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा-प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तर्गण, निरीक्षण प्रभागों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उनकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी जाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुमति हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संचय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संवेद्य होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामानिर्देशिती को प्रतीकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का सुनित्युक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो वह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियम तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगन हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गए किसी व्यक्तित्व की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हक्कार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एम०-35014/256/82-पी० एफ०-2]



**S.O. 4086**—Whereas Messrs Genelec Ltd., Jogeshwari East Bombay (MH/609) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

#### SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premium, transfer of accounts, payment of inspection charges etc shall be borne by the employers.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their points of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India

1001 GI/82—10

as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members, who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(256)/82-PF(II)]

का० आ० 4087--मैसर्स सुजाता टेक्सटाईल्स लिमि. डाकघर नांद-जंजड (के एन०/89) (जिसे हमें हमके पञ्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपस्थिति अधिनियम 1952 (1952 का 19) जिसे हमें हमके पञ्चात उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए प्रार्थना किया है;

और केन्द्रीय सरकार ता समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पथक अधिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उक्त फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निवेश महद्वद बीमा स्कीम, 1976 (जिसे हमें हमके पञ्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुमति है,

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और हमें उपर्युक्त अनुमति में त्रिनिटिष्ट गतों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

#### अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय को ऐसी विवरणियाँ भेजना और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएँ प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रसारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर, संदाय करे जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अनुबंध लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रसारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उन्हें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उनके अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम सुरक्षित करेंगे और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेंगे।

6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बहाल जाने हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेंगे जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुसूचित हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देश्य रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशित को प्रतिकार के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेंगे।

8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों का अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का व्यक्तिगत अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी वारिस में कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियम ताराख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियम कर, प्रीमियम का सदाय करने में अमफल रहता है, और पालिसी की व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सदाय में काला गण, किसी व्यक्तिगत रूप से उस सन सदस्यों के नामनिर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का सदाय तत्पश्चात् से और प्रत्येक वर्ष से भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के बात वित्त के भीतर गुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस०-35014/269/82-पी० एफ०-II]

**S.O. 4087.**—Whereas, Messrs Sujatha Textile Mills, P.O. Nanjangud, Karnataka (KN/89) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment, are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

#### SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc, shall be borne by the employers.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium etc the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/

legal persons entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(259)82-PF. II]

कॉ. आ० 4088—मैसर्स श्री रामलिंगा मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, 212, रामासामी नगर, अरुपुकोट्टल-626101 (तमिल नाडु स्टेट), (टी० एन०/5252) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 14) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार को समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन ने कर्मचारी, किसी पृथक् अनिवार्य या प्रीमियम का सहाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा नियम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहज बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

#### अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों को प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाता विवरणियों का प्रस्तुत किया जाता, बीमा प्रीमियम का सदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का सदाय छोड़ा भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उतमें संशोधन किए जाएं, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम मुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा नियम को सदाय करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम के किसी बात के होने हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है

जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता था, नियोजक कर्मचारी विधिक धारिग/नाम निर्देशिनी को प्रविष्ट के रूप में दांतों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्ण अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो सके, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का अधिकार्यक अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा नियम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अंतर्गत कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा नियम नियम कर, प्रीमियम का संदाय करने में समफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने लिए जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिथम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का सदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा नियम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एम-35014/437/82-पी० एफ०-11]

S.O. 4088.—Whereas Messrs Shri Ramalinga Mills Private Limited, 212, Ramasamy Nagar, Aruppukottai-626101 (Tamil Nadu State) (TN/5252) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contributions or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

#### SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.



3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(437)/82-PF. II]

का० अ०. 4089:-- सैयर्स मार्जरेट् केर्रीज (घाई) लिमिटेड, ग्रहीयार मद्रास-(टी० एन/10387), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पक्षक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा

के रूप में कायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये कायदे उक्त कायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निवेश महजब्द बीमा स्कीम 1952 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उक्त अनुबन्ध है ,

अन केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसमें उक्त अनुबन्ध में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन का तान बर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन में छूट देती है ।

#### अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक भविष्य प्रौढशिक्षा निधि प्रायुक्त, मद्रास का ऐसी विवरणियां भेजेंगी और ऐसे लेखा रखेंगी तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेंगी जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निविष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रसारी का प्रत्येक मास की मर्यादा के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निविष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रणालन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारा का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, उक्त संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पत्र पर प्रेषित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पक्षक हो सक्षम है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम गुरन्त दर्ज करेगा और उसकी वास्तव आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम का संबन्ध करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों की उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों का उपलब्ध फायदों में समुचित रूप में वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुसंधे है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बान के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिनी को प्रतिकर के रूप में वारों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों से कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, मद्रास के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना वृत्तिकोण स्पष्ट करने का यत्नियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापना ने कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसमें स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों का प्राप्ति होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो वह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक-उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा-निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असमर्थ रहता है, प्रोविडेंट फंड का उपयोग हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिरिक्त की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशनियों या विधिकारियों को जा, यदि यह छूट न दो गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होने, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशनियों/विधिकारियों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्पश्चात् से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के मान दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस० 350/4/438/82-पी०एफ०३]

S.O. 4089.—Whereas Messrs Modern Bakeries (I) Limited, Adyar, Madras-20 (TN/10387) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contributions or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Link Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

#### SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc shall be borne by the employers.

4. The employer display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available

under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employers under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/ legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(438)/82-PF. II]

का० आ० 4090.—जैसम के० एस० श्री० एम्पम लिमिटेड, बोम्बे-मुंबा रोड, प्ला-411018 (एस० ए/6471), (जिसे एममें इसके पञ्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी अधिनियम निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे एममें इसके पञ्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है।

श्री० केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी एक अधिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक असम्भव हैं जो कर्मचारी विशेष संवर्द्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे एममें इसके पञ्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अर्जित हैं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपबन्ध अनुसूची में ब्रिटिश शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

#### अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक अधिकारी निधि आयुक्त, महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियाँ भेजेंगी और ऐसे लेखा रखेंगी तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेंगी जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की

धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निविष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संवाय आदि भी है, होते वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत् करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बाल के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का प्रकृतियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापना के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम धियत करे, प्रीमियम का संवाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी व्यक्तिक्रम, की वशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हक्कावर नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संवाय तत्परता से और प्रत्येक वशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

**S.O. 4090.—Whereas Messrs K. S. B. Pumps Limited, Bombay, Poona Road, Pimpri, Puna-411018 MH/6471, (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);**

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contributions or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

#### SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Maharashtra, maintain such accounts and provide for such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including Maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employers.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment, or the benefits to



the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would, have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(439)/82-PF. II]

क्र० आ० 4091—मैसर्स दी कर्नाटका डेरी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हसन डेरी, पार्क रोड, बंगलोर (के० अ०/6736), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसीपुष्क अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निवेश सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुभूत हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाय्य अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

#### अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त कर्नाटका को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निश्चित करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निश्चित करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिमके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का भंडारण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उक्त संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मूल भाषा में अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम सुरक्षित दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदाय करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुभूत हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, कर्नाटका के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का व्यक्तिगत अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत सारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृतसदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन होने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हक्कार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं०एस-35014/442/82-पी०एफ-2]

ए० के० अट्टरार्ड, प्रभार सचिव

S.O. 4091.—Whereas Messrs The Karnataka Dairy Development Corporation Limited, Hassan Dairy, Park Road, Bangalore (KN/6736), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contributions or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than

the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976, (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

#### SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Bangalore, maintain such accounts and provide for such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees, of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would, have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(442)/82-PF.II]

A. K. BHATTARAI, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 नवम्बर 1982

क्रमांक 4092 - केन्द्रीय सरकार, मध्यक खान और कल्याण निधि अधिनियम, 1946 (1946 का 22) की धारा 3 की उपधारा (4) के अनुसूची में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान मध्यक खान और कल्याण निधि में वित्त-पोषित स्थापनाओं की निम्नलिखित रिपोर्ट उस वर्ष के लेखा विवरण तथा उक्त निधि के वर्ष 1982-83 की प्रारम्भिक और अन्तिम के प्राक्कृत महीने प्रकाशित-कर्ता है।

#### भाग-1

##### (1) सामान्य

मध्यक खान और कल्याण निधि का गठन मध्यक खान और कल्याण निधि अधिनियम, 1946 (1946 का 22) के अधीन मध्यक खान उद्योग में नियोजित श्रमिकों के कल्याण में संबंधित स्कीमों के वित्त पोषण के लिए किया गया है।

2 अधिनियम में, नियति की गई सभी मध्यक पर मूल्यांकन संबंध प्रतियोगिता में अधिकांश पर पर सीमाशुल्क के उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है 2 उपकरण की दर, जो कि पहले मूल्यांकन 25 प्रतिशत थी, 15 जुलाई, 1974 से 31/1 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई। संघर्षों का प्रावधान विभिन्न मध्यक उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में उनके प्रमुख उत्पादन के अनुपात में कल्याणकारी उपायों में संबंधित ब्याज के लिए किया जाता है।

#### भाग-2

##### प्रकाशित सुविधाएँ

##### (क) चिकित्सा

मध्यक खान और कल्याण संगठन द्वारा मध्यक श्रमिकों और उनके आश्रितों के लिए विभिन्न प्रकार की चिकित्सा सुविधाओं की विशुद्ध व्यवस्था की जाती है उनके अत्यंत अस्थिरता, प्रसूति एवं शिशु कल्याण केन्द्रों का प्रावधान और अनुसूचित गृहोपचार सहित क्षयरोग के उपचार की सुविधाएँ, अत्युर्वेदिक औषधालय सहित औषधालय सेवाएँ और अन्य सुविधाएँ शामिल हैं। रिपोर्ट में सर्वप्रथम वर्ष के दौरान मध्यक श्रमिकों और उनके आश्रितों के उपचार के लिए कल्याण संगठन द्वारा निम्नलिखित केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय अस्पताल बनाए जाने रहे :—

क्रम संख्या	अस्पताल का नाम	पसंखियों की संख्या
1	केन्द्रीय अस्पताल, कर्मा (बिहार)	100
2	केन्द्रीय अस्पताल, गंगापुर (राजस्थान)	30
3	केन्द्रीय अस्पताल, कालीबेड़ (प्रान्ध प्रदेश)	30
4	क्षेत्रीय अस्पताल, मिमरी (बिहार)	30
5	क्षेत्रीय अस्पताल, तालपुर (प्रान्ध प्रदेश)	10
6	केन्द्रीय अस्पताल, कालीबेड़ (प्रान्ध प्रदेश)	20
	में मलय क्षयरोग वाडें	
7	क्षयरोग अस्पताल, कर्मा, बिहार	50
8	क्षेत्रीय अस्पताल, मईवाणम	10 (आहार के साथ)

इनके अलावा अन्नक उत्पादन करने वाले तीन राज्यों में निम्नलिखित अन्य प्रकार के जिक्रिया सम्मान भी लगातार कार्य करते रहे :—

जिक्रिया सम्मान का नाम	आन्ध्र प्रदेश	बिहार	राजस्थान	कुल
एसोसिएटिव प्रोड्यूसर	--	5	3	7*
प्रामुखिक प्रोड्यूसर	2	8	4	14
प्रभुति और शिक्षा कल्याण केन्द्र	3	--	3	6
चलते-फिरते जिक्रियाएँ एकक	1	3	2	6
होमोसोसिएटिव एकक	1	--	--	1
सह समुदाय केन्द्र	--	5	--	5

\* आन्ध्र प्रदेश में एक एसोसिएटिव प्रोड्यूसर को 1-9-80 से केन्द्रीय अस्पताल, कालीबेलु के माध्यम से भेजा गया है।

कल्याण संगठन क्षयरोग से पीड़ित खानिकों के उपचार के लिए पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने के प्रयास करने रहा। क्षयरोग अस्पतालों और खानिकों की व्यवस्था के अलावा क्षयरोग/मिनिमोसिस से पीड़ित अन्नक खानिकों के विशेष उपचार की व्यवस्था करने के लिए क्षयरोग सैनेटोरियम, मदार (अजमेर) में चार परलंग आरक्षित किए गए। इसके अतिरिक्त, हम प्रवांजन के लिए केन्द्रीय अस्पताल मगपुर में 10 परलंगों के अलंग बाई हैं। कल्याण निधि क्षयरोग और छाती के रोगों के सरकारी अस्पताल, नैल्मौर में चार परलंगों का बेसल अन्नक खानिकों और उनके परिवारों के प्रयोग के लिए आरक्षण जारी रहा।

क्षयरोग के ऐसे रोगी को 9 मास की अवधि तक के लिए 50 रुपये प्रतिमास का निर्वाह भत्ता दिया जाता है, यदि वह परिवार के लिए स्वयं नसने वाला सदस्य हो। आलोच्य रिपोर्ट की अवधि के दौरान बिहार में 92 मरीजों, राजस्थान में एक मरीज को निर्वाह भत्ता मजूर किया गया। निधि जिक्रिया सुविधाएं :

भातक दुर्घटना लाभ योजना के अन्तर्गत, निधि केन्द्रों की पत्नी को 250 रुपये की अब 500 रुपये तक संशोधित एक मूल्य अदायगी और पांच वर्ष की अवधि के लिए दैनिक 25 रुपये प्रतिमास के भत्ते की अदायगी और प्रत्येक स्कूल जाने वाले बच्चे के लिए उसके 15 वर्ष के होने तक या विवाह करने तक, जो भी पहले हो, 15 रुपये की मासिक छात्रवृत्ति की अदायगी के रूप में वित्तीय सहायता देना जारी रखा।

आलोच्य रिपोर्ट की अवधि के दौरान इस योजना के अन्तर्गत भोलबाड़ा राजस्थान में दो मामलों में 600 रुपये और कर्मा (बिहार) में मृतकों के दो आश्रितों को 700 रुपये की राशि का अनुदान किया गया।

लखनऊरी कोढ़ अस्पताल में कोढ़ से पीड़ित बिहार के अन्नक खानिकों के उपचार के लिए व्यवस्था जारी रही। कैमर में पीड़ित अन्नक खानिकों के उपचार के लिए केन्द्रीय अस्पताल कल्ला (आमनसौर) और राजी मे काके में मानसिक रोगों के अस्पताल में मानसिक रोगों से पीड़ित खानिकों की उपचार व्यवस्था जारी रही। कैमर से पीड़ित अन्नक खानिकों के उपचार की योजना के अन्तर्गत अस्पताल में परलंगों के आरक्षणों की अनुमति दी गई है, जिससे सामान्यतः 9 मास से अतिरिक्त अवधि के लिये मूल्य उपचार की व्यवस्था की गई और कुछ उपचार वाले मामलों में यह अवधि 9 मास से अधिक हो सकती है, यदि उपचार कर रहे जिक्रिया प्राधिकारी ऐसा चाहते हैं।

ऐसे रोगी, जिन्हें हृदय प्रत्यक्ष है, अन्नक खानिक अन्न-कल्याण संगठन द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों से उपचार भी प्राप्त करते हैं। उनके उपचार के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निधि संगठनों को सहायक अनुदान दिया जाता है। अन्नक खानिकों को 30 रुपये प्रति जोड़ा ऐतक आयोक्त लागू पर उनके नवाई की जाती है।

### (ब) शिक्षा और मनोरंजन सुविधाएं :

अन्नक खानिकों और उनके आश्रितों को शिक्षा और मनोरंजन सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए, कल्याण संगठनों द्वारा बहुवर्षीय संस्थान चलाए जाते हैं। प्रत्येक संस्थान में एक प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र और एक रहित कल्याण केन्द्र शामिल है। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का विस्तार करते हुए कल्याण संगठन ने सहायक और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र भी खोले हैं। मनोरंजन के प्रयोजनार्थ अन्नक खानिक क्षेत्रों में रेडियो सेट स्थापित किए गए हैं और अन्नक अन्न कल्याण संगठन के अन्तर्गत मनोरंजन क्लब, पुस्तकालय और रीतिरिवाज कक्षा कार्य रहे हैं। शिक्षा सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु कल्याण संगठनों द्वारा प्राथमिक स्कूल/मिडिल स्कूल/हाई स्कूल चलाए जा रहे हैं। इन सुविधाओं की व्यवस्था करने वाले संस्थानों की संख्या इस प्रकार है :—

प्र.मांक	संस्थाओं का ध्यौरा	आन्ध्र प्रदेश	बिहार	राजस्थान	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	बहुवर्षीय संस्थान ( प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र और महिला कल्याण केन्द्र सहित )	—	9	5	14
2.	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	—	—	7	7
3.	प्राथमिक/प्राथमिक स्कूल	4	3*	—	7
4.	मिडिल स्कूल	—	(4)**	—	4
5.	हाई स्कूल	2	1	—	3
6.	सहायक केन्द्र	—	1	—	1
7.	खानिकों के बच्चों के लिए छात्रावास/होस्टल	2	(4)***	1	7
8.	चलते फिरते सिनेमा एकक	1	3	1	5
9.	विभागीय रेडियो सेट	20	16	8	44
10.	मनोरंजन क्लब	14	—	—	14
11.	भजन-मंडली	9	9	—	18
12.	पुस्तकालय और वाचनालय	—	15	10	25

\* 1-10-1981 से राज्य सरकारों को हस्तांतरित।

\*\* चार में से तीन को पहले ही राज्य सरकार को हस्तांतरित किया गया है।

\*\*\* एक में समावेसित।

चलते फिरते सिनेमा एकक के माध्यम से शैक्षिक एवं धार्मिक महत्व की फिल्मों दिखाई जाती हैं।

स्कूलों और कालेजों में अन्नक खानिकों के पढ़ रहे पुत्रों/पुत्रियों के अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां दी जाती हैं।

अन्नक खानिकों के लिए मनोरंजन की व्यवस्था करने के लिए समय-समय पर खेल-कूद आयोजित किए जाते हैं और विजेताओं को पुरस्कार दिये जाते हैं।

### (ग) पेय जल की सुविधाएं :

अन्नक खानिकों में पीय जल की कमी एक चिरस्थायी समस्या है। इस समस्या को हल करने के लिए कुएं खोदने की एक योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत अनुमानित लागत का 75 प्रतिशत या वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत जो भी कम हो, मासिकों को कुएं खोदने के लिए दिया जाता है। आन्ध्र प्रदेश में कालीबेलु गांव में एक स्थायी जल प्रदाय योजना चल रही है। अभी तक आन्ध्र प्रदेश में 26 कुओं और राजस्थान क्षेत्र में 16 कुओं को खोदा गया है। राजस्थान क्षेत्र में 47 कुओं की संरचना की गई है।



## (ख) आवास.

दो आवास योजनाएं अर्थात् अपना मकान बनाओ योजना और टाइप-1 आवास योजना ( कम लागत आवास योजना ) चल रही है।

अपना मकान बनाओ योजना के अन्तर्गत प्रत्येक मकान के लिए 1500 रुपये की वित्तीय सहायता का भुगतान किया जाता है ( 600 रुपये आर्थिक सहायता के रूप में और मासिक किस्तों में बिना व्याज के रूप में 900 रुपये, जो नौ वर्ष से अनधिक अवधि में बसूल किए जाएंगे ) इस योजना के अन्तर्गत अब तक 718 मकानों को पूरा किया जा चुका है।

टाइप-1 आवास योजना के अन्तर्गत, साधारण क्षेत्रों में मानक अनुमानित लागत का 75 प्रतिशत है, जो 6825 रुपये है और कपास पैदा करने वाली काली या उभरी हुई भूमि वाले क्षेत्रों में 7825 रुपये या मकानों के निर्माण की वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत इनमें जो भी कम है, आर्थिक सहायता दी जाती है। कार्य आदेश जारी होने के साथ ज्ञान प्रबन्धकों को आर्थिक सहायता का 20 प्रतिशत अग्रिम रूप में दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत अब तक 72 मकानों का निर्माण किया जा चुका है।

इससे पूर्व विभागीय कालोनी योजना के अन्तर्गत 98 मकान और आर्थिक सहायता प्राप्त आवास योजना के अन्तर्गत 12 मकान बनाए गए थे। आवास कार्यक्रमों की धमि को तेज करने के लिए और योजनाओं को अधिक आकर्षित बनाने के लिए एक आवास उप समिति गठित की गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इसकी मंजूर्य में जांच की जा रही है।

## भाग--3

वर्ष 1981-82 की प्राप्तियां और व्यय इस प्रकार हैं :-  
प्राप्तियां

पहली अप्रैल, 1981 को अवशेष	1,92,29,453.88
वर्ष 1981-82 के दौरान प्राप्तियां	1,16,93,000.00
वर्ष 1981-82 के दौरान व्यय	84,91,824.00
31 मार्च, 1982 को अन्त शेष	2,24,30,629.88

## भाग--4

वर्ष 1982-83 के लिए अनुमानित प्राप्तियां और व्यय

अनुमान	( रुपये लाखों में )
प्राप्तियां	100.00
व्यय	92.95

[संख्या जेड-16016/1/82-एम०-3/ उत्प०-2]

टी० डी० सहोदा, अवर सचिव

New Delhi, the 13th Nov., 1982

S.O. 4092.—In pursuance of Sub-Section (4) of Section 3 of the Mica Mines Labour Welfare Fund Act, 1946 (XXII of 1946) the Central Government hereby publish the following report of the activities financed from the Mica Mines Labour Welfare Fund during the year ending 31st March, 1982 together with a statement of accounts for that year and an estimate of receipts and expenditure of the said fund for the year 1982-83.

## PART-I

## 1. General

The Mica Mines Labour Welfare Fund has been constituted under the Mica Mines Labour Welfare Fund Act, 1946, (22 of

1946) for financing schemes relating to the Welfare of labour employed in the mica mining industry.

2. The Act provides for the levy of a duty of customs; on all mica exported, upto a maximum rate of 6-1/4 per cent ad-valorem. The rate of cess, which was 2-1/2 per cent ad-valorem previously, has been increased to 3-1/2 per cent with effect from the 15th July, 1974. The collections are allocated for expenditure on welfare measures among the various mica producing areas in proportion to their average production.

## PART-II

## Facilities provided

## A. Medical

Various types of medical facilities for mica workers and their dependents are provided free of cost by the Mica Mines Labour Welfare Organisations. These include provision and maintenance of hospitals, maternity and child welfare centres, facilities for treatment of T.B. including domiciliary treatment dispensary services including Ayurvedic dispensaries and other facilities, etc. The following Central and Regional hospitals continued to be maintained by the Welfare Organisations for the treatment of mica miners and their dependents during the year under report :—

Sl. No.	Name of the Hospitals	Bed Strength
1.	Central Hospital, Karma (Bihar)	100
2.	Central Hospital, Gangapur (Rajasthan)	30
3.	Central Hospital, Kalichedu (Andhra Pradesh)	30
4.	Regional Hospital, Tisri (Bihar)	30
5.	Regional Hospital, Talupur (Andhra Pradesh)	10
6.	T. B. Ward attached to Central Hospital, Kalichedu (Andhra Pradesh).	20
7.	T. B. Hospital, Karma, (Bihar)	50
8.	Regional Hospital, Sydapuram	10

(Dietary)

In addition, the following other medical institutions also continued to function in the three mica producing States.

## States :

Medical Institutions	Andhra Pradesh	Bihar	Rajas- than	Total
Allopathic Dispensaries	—	5	3	*7
Ayurvedic Dispensaries	2	8	4	14
Maternity and child welfare centres.	3	—	3	6
Mobile Medical Unit	1	3	2	6
Homoeopathic Unit	1	—	—	1
Small Community Centres	—	5	—	5

\*One Allopathic Dispensary in A. P. region has been merged with Central Hospital, Kalichedu w.e.f. 1-9-1980.

The Welfare Organisations have been endeavouring to provide adequate facilities for treatment of the miners suffering from T.B. Apart from setting up of T. B. Hospitals and clinics, four beds remained reserved at T.B. Sanatorium, Madar (Ajmer), for providing specialized treatment to mica miners suffering from T.B./Silicosis. Besides, there is a 10 bedded segregated wards in the Central Hospital, Gangapur, for the purpose. Four beds in the Govt. Welfare Fund T.B. & Chest Disease Hospital, Nellore, continued to be reserved for the exclusive use of mica miners and their families.

A subsistence allowance of Rs. 50 per month is granted to a T.B. patient for a period upto 9 months where he happens to be the only earning member of the family. During the period under report 32 patients in Bihar, one patient in Rajasthan were sanctioned Subsistence Allowance.

#### Miscellaneous Medical Facilities

Under the Fatal Accident Benefit Scheme, the Fund continued to provide financial assistance to the spouse of a miner in the form of a lumpsum payment of Rs. 250/- (since revised to Rs. 500/-) and a monthly allowance of Rs. 25/- payable for a period of five years and a monthly scholarship of Rs. 15/- payable in respect of each school going child till he/she attains the age of 15 or is married, whichever is earlier.

During the period under report, an amount of Rs. 600/- to two cases in Bhilwara, Rajasthan and Rs. 700/- to two dependents of the deceased in Karma, Bihar, was paid under this Scheme.

Arrangements continued for the treatment of mica miners of Bihar suffering from Leprosy at the Tetulmari Leprosy Hospital. For the treatment of mica miners suffering from cancer, arrangements continued at the Central Hospital, Kalla (Assansol), and for mental diseases at the Mental Hospital, Kanke, Ranchi. Under the scheme for the treatment of mica miners suffering from cancer, reservation of beds in a hospital have been allowed which provides free treatment generally for a period not exceeding 9 months and in exceptional cases, this period can be more than 9 months if the treating medical authority so desire.

The non-entitled patients also get treatment from the hospitals run by the Mica Mines Labour Welfare Organisation. For their treatment, Grant-in-aid is paid by the concerned State Govts. to the Fund Organisations. Spectacles are supplied to the Mica Mines Workers at a cost not exceeding Rs. 30/- per pair of spectacles.

#### (B) Educational and Recreational facilities

For providing educational and recreational facilities to mica workers and their dependents, various Multipurpose Institutes, each comprising of an Adult Education Centre and Women's Welfare Centre, are run by the Welfare Organisations. In order to expand the Adult Education activities, Feeder and Adult Education Centres have also been opened by the Welfare Organisations. For recreational purpose, Radio Sets have been installed in mica mining areas and recreation clubs as well as Library and reading rooms have been functioning under the Mica Mines Labour Welfare Organisations. In order to provide educational facilities, Primary Schools/Middle Schools/High Schools are run by the Welfare Organisations. The number of Institutions providing the above facilities are as under :

Sl. No.	Particulars of Institutions	A.P.	Bihar	Rajasthan	Total
1	2	3	4	5	6
1.	Multipurpose Institutes (with an Adult Education Centre and Women's Welfare Centre).	..	9	5	14
2.	Adult Education Centre	..	..	7	7
3.	Primary/Elementary Schools	4	3*	..	7
4.	Middle Schools	..	4/1	..	4
5.	High Schools	2	1	..	3

1	2	3	4	5	6
6.	Feeder Centre	..	1	..	1
7.	Boarding Houses/Hostels for miners' children.	2	4**	1	7
8.	Mobile Cinema Units	1	3	1	5
9.	Departmental Radio Sets.	20	16	8	44
10.	Recreation Clubs	14	..	..	14
11.	Bhajan Mandalies	9	9	..	18
12.	Library & Reading Rooms.	..	15	10	25

\*Since transferred to the state Govt. w.e.f. 1-10-81.

@Out of four, three have already been transferred to State Govt.

\*\*Amalgamated into one.

Films of educational and religious value and exhibited through a mobile cinema Unit.

Scholarships are awarded to the sons/daughters of mica miners studying in schools and colleges for their studies.

Games and Sports are organised periodically, to provide recreation to mica miners and prizes are also awarded to the winners.

#### (C) Drinking Water facilities :

Scarcity of drinking water is a chronic problem in mica mining areas. With a view to resolve this problem, a scheme for sinking of wells has been introduced. Under this scheme, 75% of the estimated cost or 75 per cent of the actual cost, whichever is less, is paid to the mine owners for sinking wells. In Kalichedu village in Andhra Pradesh, a permanent water supply scheme is in vogue. The two Water Supply Schemes i.e. Talupur and Sudapuram are also under consideration. Twenty six wells in Andhra Pradesh region and 16 in Rajasthan region have been sunk so far. Forty-seven wells in Rajasthan region have also been renovated.

#### (D) Housing

Two schemes, viz. Build Your Own House Scheme, Low cost Housing Scheme are in vogue.

Under Build Your Own House Scheme, financial assistance to the tune of Rs. 1,500/- per tenement (Rs. 600/- in the form of subsidy and Rs. 900/- in the form of interest free loan recoverable in monthly instalments spread over a period not exceeding 9 years) is paid. 718 houses have so far been completed under this scheme.

Under Type I Housing Scheme, subsidy payable is 75% of standard estimated cost, which is Rs. 6,825/- in ordinary area and Rs. 7825 in black cotton or swelly soil area or 75% of actual cost of construction of houses, whichever is less. 20% of the subsidy is payable in advance to the mine management, with the issue of work order. 72 houses have so far been completed under this scheme.

Earlier, 98 houses were built under the Departmental colony scheme and another 12 houses under subsidized house scheme were constructed. With a view to accelerate the pace of housing programmes and to make the schemes more attractive, a Housing Sub-Committee was constituted, which has since submitted its report. This is being examined in the Ministry.

#### PART-III

The receipts and expenditure for the year 1980-81 are as follows :—

Receipts	
Opening balance as on 1st April, 1981	1,92,29,453.88
Receipt during the year 1981-82	1,16,93,000.00
Expenditure during the year 1981-82	84,91,824.00
Closing balance as on 31st March, 1982	2,24,30,629.88

#### PART-IV

Estimated receipts and expenditure for the year 1982-83	
	(Rs. in lakhs)
Budget Estimates	100.00
Receipts	92.95
Expenditure	

[F. No. Z-16016/1/82-M. III/W. II]  
T. D. SALHOTRA, Under Secy.

